

विषय सूची

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

■ भारत का संवैधानिक विकास	3
■ संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियाँ	5
■ संविधान पर विदेशी प्रभाव	9
■ राष्ट्रीय प्रतीक	11
■ संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका विषयवस्तु एवं महत्व	13
■ संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग	15
■ संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र	28

संविधान के मूल तत्व

■ नगरिकता	30
■ मूल अधिकार	31
■ राज्य के नीति निर्देशक तत्व	42
■ मूल कर्तव्य	46

सरकार की शासन प्रणाली

■ संसदीय व्यवस्था	49
■ संघीय व्यवस्था	50
■ केन्द्र-राज्य सम्बन्ध	50
■ अंतर्राज्यीय सम्बन्ध	52
■ आपातकालीन उपबंध	53

संसद

■ संरचना एवं कार्यप्रणाली	54
■ राष्ट्रपति	58
■ उपराष्ट्रपति	65
■ लोकसभा	66
■ राज्य सभा	71
■ प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	74
■ संसदीय समितियाँ एवं विभिन्न प्रस्ताव	76
■ विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया	77
■ वरीयता अनुक्रम	84

राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली

■ राज्यपाल/उपराज्यपाल	84
■ राज्य विधानमंडल	86
■ मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	88
■ कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध	88

न्यायपालिका

■ उच्चतम न्यायालय-गठन, शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार	88
■ उच्च-न्यायालय-गठन, शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार	94
■ अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण	96

स्थानीय शासन

■ पंचायती राज का विकास एवं संरचना	96
■ नगरीय शासन	102
■ सहकारी समितियाँ	103

संवैधानिक निकाय

■ निवार्चन आयोग	103
■ वित्त आयोग	106
■ भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	106
■ संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग	107
■ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग	109
■ भारत का महान्यायवादी	109
■ राज्य का महाधिवक्ता	110
■ राजभाषा एवं सेवाएँ	110
■ प्रमुख आयोग/समिति एवं संवैधानिक संस्थायें	111

गैर-संवैधानिक निकाय

■ योजना आयोग/नीति आयोग	112
■ राष्ट्रीय विकास परिषद	114
■ राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग	114
■ केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग	115
■ लोकपाल एवं लोकायुक्त	115
■ विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग	115

राजनीतिक गतिशीलता

■ राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता	116
■ दल परिवर्तन कानून	118
■ विविध	118

Download All Subject Free PDF



General Knowledge



Child Development
and Pedagogy



Current Affairs



History



Maths



Geography



Reasoning



Economics



Science



Polity



Computer



Environment



General Hindi



MP GK



General English



UP GK

Join Our Best Course

GK Trick By
Nitin Gupta



Current Affairs



Daily Current Affairs PDF, Best Test Series, Best GK PDF के लिए हमें Follow करें



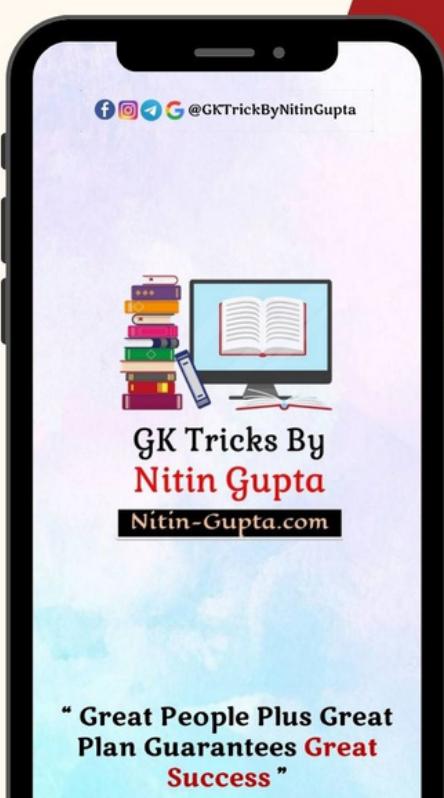
GK Trick By Nitin Gupta
The Ultimate Key to Success.

Welcome To

GK TRICK BY NITIN GUPTA APP

यहाँ पर आपको मिलेगा

- ✓ Best PDF Notes For All Exams
- ✓ Best Test Series For All Exams
- ✓ Daily Current Affairs PDF
- ✓ सभी Course बहुत ही कम Price पर
- ✓ सभी Test Detail Description के साथ व Analysis करने को सुविधा



भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

(Indian Constitution & Polity)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

भारत का संवैधानिक विकास

<p>■ ‘यदि लोग, जो चुनकर आएंगे योग्य चरित्रावान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन है—</p> <p>डॉ. भीमराव अंबेडकर का</p>	UPSI, 2001
<p>■ कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया—</p> <p>जवाहर लाल नेहरू ने</p>	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022
<p>■ भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है—</p> <p>सबसे छोटा लिखित संविधान</p>	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022
<p>■ भारत जैसे देशों के लिए उपर्युक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है—</p> <p>सहकारी संघवाद</p>	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
<p>■ मॉण्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी—</p> <p>केंद्र एवं रियासतों के साथ-साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन</p>	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
<p>■ 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद् के उपाध्यक्ष थे—</p> <p>जवाहर लाल नेहरू</p>	Cane Supervisor (31-08-2019)
<p>■ वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था—</p> <p>भारत सरकार अधिनियम, 1935</p>	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2
<p>■ भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था—</p> <p>प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ</p>	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-I
<p>■ सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव (1934) रखा था— एम. एन. रॉय</p>	RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-II) UPSI 21.11.2021 Shift-III RRB Group-D 24-10-2018 (Shift-I) RRB NTPC 28.12.2020 (Shift-II) Stage Ist
<p>■ 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था—</p> <p>स्वतंत्रता दिवस</p>	RRB NTPC 03.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
<p>■ भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली (Communal Electorate system) सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी—</p> <p>मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, 1909</p>	RRB NTPC 29.12.2020 (Shift-II) Stage Ist
<p>■ वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था—</p> <p>विनियमन अधिनियम 1773</p>	RRB NTPC 11.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
<p>■ संविधान सभा के.....1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ—</p> <p>कैबिनेट मिशन प्लान</p>	RRB Group-D 01-10-2018 (Shift-II)
<p>■ 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था—</p> <p>मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में</p>	UPSI 21.11.2021 Shift-I
<p>■ भारत में लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) के पद को सृजित किया गया है—</p> <p>भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत</p>	UPSI 15.11.2021 Shift-I
<p>■ गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है—</p> <p>भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने</p>	UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
<p>■ ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को, उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर, मताधिकार दिया गया—</p> <p>भारत सरकार अधिनियम, 1919</p>	UPSI Batch-2, 15 Dec 2017
<p>■ भारतीय संविधान लागू होने से पहले, भारत का प्रशासन मूल रूप से दस्तावेज के अनुसार होता था—</p> <p>भारत सरकार अधिनियम, 1935</p>	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017

■ यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है— भारत सरकार अधिनियम 1919	UPSI Batch-1, 19 Dec 2017
■ अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था— 1813 का चार्टर अधिनियम	UPPCS RO/ARO (Mains) 2017
■ ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का मन्त्रिमण्डल नहीं बना— बंगाल और पंजाब	UP RO/ARO (Pre) 2016
■ अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद (इण्डिया कौसिल) को समाप्त किया गया— भारत सरकार अधिनियम 1935	RO-ARO GS Re Exam. Pre 2016
■ 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था— वारेन हेस्टिंग्स 1774 ई.	RO-ARO GS Re Exam. Pre 2016
■ वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल (कलकत्ता) में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी— 1773 रेग्यूलेटिंग एक्ट	RO-ARO GS Re Exam. Pre 2016
■ “हम फिलहाल संविधान निर्माणी सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं” उपर्युक्त कथन है— एम.ए. जिन्ना	BEO Exam 2003
■ 1935 के अधिनियम के तहत कराये गये विधानसभा चुनाव में काँग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं बंगाल प्राप्त किया—	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd 2004
■ ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए एक लाख रुपये दिये थे— चार्टर अधिनियम, 1813	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2009
■ भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम चार्टर एक्ट 1833 है—	(UPPCS (Pre) 2012)
■ एक ‘संघीय व्यवस्था’ और ‘केन्द्र’ में ‘द्वैध शासन’ भारत में लागू किया गया था— 1935 के अधिनियम द्वारा	UPPCS (Main) G.S. II nd 2013
■ एक भारत शासन अधिनियम, 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है— देश के लिए लिखित संविधान	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ भारत में ‘स्थानीय स्वायत्त शासन’ का जनक माना जाता है— लॉर्ड रिपन	UPPCS (Pre.) G.S., 2015
■ भारतीय संविधान के वृहद् होने के कारण हैं— इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है	UPPCS (Pre.) G.S., 1997
■ पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार का गठन हुआ था— सितम्बर, 1946	UPPCS (Main) G.S. II nd , 2006
■ भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था— 22 जनवरी, 1947 को	BEO exam-2006 (I)
■यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों (dominions) में विभाजित किया था— भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम	SSC CHSL (Tier-I) – 17/03/2023 (Shift-III)
■ को भारतीय संविधान के पूर्वगामी (Precursor) के रूप में माना जाता है— भारत सरकार अधिनियम, 1935	SSC JE CIVIL 09/10/2023 (Shift-III) SSC JE Electrical 09/10/2023 (Shift-III)
■ भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदीय विधायिका की शुरुआत की गई थी— भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा	SSC CGL (Tier-I) – 26/07/2023 (Shift-II) UPSI Batch - 3 12-12-2017 UPPCS (Mains) G.S. II- 2008
■ भारत सरकार अधिनियम, 1919 को नाम से भी जाना जाता है— मॉटेंग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट	SSC JE Civil 29.10.2020 (Shift-I) UPSI 16-11-2021 Shift-II
■ के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ— मॉटेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार	SSC MTS- 12/05/2023 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग/ढांचा काफी हद तक _____ के अधिनियम से ले लिया गया है— भारत सरकार अधि. 1935	SSC CHSL (Tier-I) – 14/08/2023 (Shift-IV)

■ 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था-	20	SSC MTS– 11/05/2023 (Shift-II)
■ के परिणामस्वरूप, महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में “भारत की मलिका (Empress of India)” की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई— भारत सरकार अधिनियम 1858		SSC MTS– 10/05/2023 (Shift-I) SSC JE Electrical 10/10/2023 (Shift-II)
■ वह था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी— भारत सरकार अधिनियम, 1858		SSC CGL (Tier-I)-2019 – 06/03/2020 (Shift-II)
■ ब्रिटेन के कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों (इंडियन लेजिस्लेटिव कॉर्डिनेशन) के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था— भारतीय परिषद अधिनियम, 1892		SSC MTS 13/10/2021 (Shift-III)
■ भारत के संविधान में ----- से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है— भारत सरकार अधिनियम, 1935		SSC MTS 27/10/2021 (Shift-II)
■ संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा _____ द्वारा मान्यता दी गई थी— 8(1)		SSC CGL (Tier-I) 19/04/2022 (Shift-II)
■ प्रांतों में द्वैध शासन (डाईआर्को) के उन्मूलन की संस्तुति _____ द्वारा की गई थी— 1935 के भारत सरकार अधिनियम		SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-I)
■ भारत सरकार के के साथ मोटेंगू-चैम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी— भारत सरकार अधिनियम 1919		SSC CGL (Tier-I) – 24/07/2023 (Shift-III)

संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियाँ

■ भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थीं— 23 समितियाँ		UPSI Batch-1, 13 Dec 2017
■ संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था— 09 दिसम्बर, 1946 को		UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
■ संविधान-सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था— 26 नवंबर, 1949 को		Lower-II (Re-exam) (28-07-2019)
■ भारतीय संविधान.....शब्दों का बना है— 1,17,369		लोअर द्वितीय - 15-07-2018
■ भारत का संविधान लिखा गया था— दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि में		कनिष्ठ सहायक - 31-05-2015
■ भारतीय संविधान को माना गया है— रूप-विधान में संघीय और भावना में एकात्मक		UDA/LDA 29-11-2015
■ संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप-समिति के अध्यक्ष थे— एच. सी. मुखर्जी		राज्य मण्डी परिषद - 30-05-2019 (Shift-I) RRB NTPC 05-04-2021 (Shift-II) Stage I st
■ भारत का संविधान, संविधान सभा द्वारा.....को अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था— 26 नवंबर, 1949		व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-I) UPSI 14-11-2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान सभा में कुल.....महिला सदस्य थीं— 15		लोअर द्वितीय- 06-03-2016 UPPSC Kanoongo Exam-2015 SSC CGL (Tier-I) 11-04-2022 Shift-III
■ “राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है।” यह कथन है— डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का		कनिष्ठ सहायक - 24-04-2016
■ भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है— द्वैध शासन		RRB Group-D – 23/08/2022 (Shift-II)
■ मसौदा समिति के अध्यक्ष थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर		RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-I) असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट 22-11-2015

■ स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	RRB JE - 31/05/2019 (Shift-I) RRB NTPC 20.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-I) Stage Ist UPP Constable (Pre)-2013 SSC MTS 27-10-2021 (Shift-II) GIC (Pravakta) Exam-2015 RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-I)
■ 09 दिसंबर, 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष (अस्थायी) थे- डॉ. सच्चिदानन्द सिंहा		RRB NTPC 17.02.2021 (Shift-I) Stage Ist लोअर प्रथम- 28-02-2016 SSC Stenographer 15-11-2021 (Shift-I) RRB JE - 26/05/2019 (Shift-I) Assistant Professor (Pravokata) 2014 UPPCS (Pre.) G.S.-2006 SSC JE Civil 23-01-2018 (Shift-I) SSC JE Electrical 26-09-2019 (Shift-I) SSC GD 18-02-2019 (Shift-III)
■ पं. जवाहर लाल नेहरू ने तिथि को संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)' प्रस्तुत किया था- 13 दिसंबर, 1946		RRB NTPC 15.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान, 'उद्देश्यों के कथन' (उद्देश्य प्रस्ताव) (Objective Resolution) को प्रस्तुत किया- जवाहर लाल नेहरू ने		RRB Group-D 15-10-2018 (Shift-I) RRB NTPC 14.03.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI 13-11-2021 (Shift-I) UPSSSC PET 24-08-2021 (Shift-I)
■ वर्षों (लगभग) के विचार-विमर्श के बाद, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था- 3		RRB NTPC 08.03.2021 (Shift-I) Stage Ist SSC GD 09/12/2021 (Shift-II)
■ स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे- जवाहर लाल नेहरू		RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-II) Stage Ist SSC JE Electrical 10.12.2020 (Shift-II)
■ स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था- R. K. घनमुखम चेट्टी ने		RRB JE CBT-II 28-08-2019 (morning)
■ भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था- 29 अगस्त, 1947		RRB NTPC 14.03.2021 (Shift-II) Stage Ist SSC JE Civil 11.12.2020 (Shift-II)
■ 'भारतीय संविधान के जनक' के रूप में जाना जाता है- डॉ. भीम राव अम्बेडकर को		RRB NTPC 29.12.2020 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी- 9 दिसम्बर, 1946 को		RRB NTPC 03.03.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI 16-11-2021 Shift-III UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2009, 2011 UPPCS (Pre.) G.S., 1995
■ विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान देश का है- भारत		RRB NTPC 11.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है- 26 नवंबर		RRB Group-D 28-09-2018 (Shift-I) RRB NTPC 07.03.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 16.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था- 26 नवंबर, 1949		RRB JE - 23/05/2019 (Shift-III) SSC MTS 19-08-2019 SSC-CGL Tier-I 19-07-2023 Shift-II UPPCS (Pre.) G.S. 2000, 2002, 2006
■ भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है- भारतीय संविधान		RRB NTPC 04.04.2016 (Shift-I) Stage I st

■ भारत का संविधानको लागू हुआ—	26.01.1950	RPF SI 11/01/2019 (Shift-II) RPF Constable 18-02-2019 (Shift-III) RRB NTPC 05.04.2016 (Shift-I) Stage I st RRB NTPC 30.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 10.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 09.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था—	1946 में	RRB JE - 02/06/2019 (Shift-III)
■ भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्योंकि—	इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है	RRB JE - 22/05/2019 (Shift-I)
■ भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है—	राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है	RRB NTPC 31.03.2016 (Shift-III) Stage 1 st
■ ‘संविधान सभा’ के बह सदस्य जिन्होंने कहा कि ‘‘हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था’’—		UPSI 17.11.2021 Shift-III
■ 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तालिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल थीं—	15 महिलाएं	(UPP Constable 28.01.2019)
■ भारत का मूलरूप संविधान हाथ से लिखा गया था—	प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा	(UPP Constable 27.01.2019 Shift-I) UPP Constable, 18.06.2018 (Shift-1) SSC CHSL (Tier-1) – 10/08/2023 (Shift-II) SSC MTS 14/10/2021 (Shift-I)
■ 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है—	संसद भवन का केंद्रीय कक्ष	UPSI Batch-3, 12 Dec 2017
■ संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था—	24 जनवरी, 1950 को	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017 UPPCS (Pre.) 2018
■ दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है—	भारत का संविधान	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017
■ एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है—	संविधान सभा	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ भारत का संविधान, संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई, 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अन्तर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन, प्रादेशिक असेम्बलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल, हस्तान्तरणीय-मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी—	389	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ वह नेता जो केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष थे (1946 से लेकर 1947 तक), फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने—	गणेश वासुदेव मावलंकर	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ मूल हस्तालिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था—	शांति निकेतन	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गयी थी—	नंदलाल बोस	(UP SI/ ASI 2018)
■ भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे—	जवाहर लाल नेहरू	UPP Constable, 18.06.2018 (Shift-1)
■ भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है—	संविधान सभा द्वारा	UPSI (Ranker), 2011
■ भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया—	मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी	UPSI (Ranker), 2011
■ भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ—	26 जनवरी, 1950 को	UPSI (Ranker), 2011
■ संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था—	हैदराबाद	UPSI (Ranker), 2011

■ भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता (संवैधानिक सलाहकार) थे –	श्री बी. एन. राव	UPPSC Polytechnic Lecturer 2021 UPPCS (Pre.) G.S. 2014 UPPSC AE-2013 U.P. Lower (Pre.) G.S. 2009 SSC JE Civil 29.10.2020 (Shift-I) SSC MTS 07.08.2019 (Shift - I)
■ 1939 में यह घोषणा कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह कथन था–	महात्मा गांधी	U.P.P.C.S. (J) G.K., 2016
■ भारत की संविधान सभा का गठन किया गया–	कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd 2004, 2008 UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2010 U.P. Lower (Pre.) G.S. 2009
■ संविधान निर्माणी परिषद की 'झण्डा समिति' के अध्यक्ष थे–	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	UPPCS (Pre) G.S., 1991
■ भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था–	जनवरी 22, 1947	UPPCS (Pre.) G.S., 1998
■ भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय था–	2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2007
■ भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि "भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है" संबंधित है–	के. सी. ल्हीयर	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2005
■ "संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था" यह कथन है–	ऑस्टिन	UP RO/ARO (Pre) G.S., 2013
■ स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान दिया था–	जवाहर लाल नेहरू	SSC CHSL (Tier-1) – 08/08/2023 (Shift-II)
■ संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे–	डॉ. के. एम. मुंशी	SSC CHSL (Tier-1) – 17/08/2023 (Shift-IV) SSC JE Civil 24.01.2018 (Shift-I)
■ संविधान सभा की मसौदा समिति में _____ सदस्य शामिल थे–	7	SSC CGL (Tier-I) 21/04/2022 (Shift-III)
■ संविधान की प्रारूप समिति (मसौदा समिति) की अध्यक्षता ने की–	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	SSC MTS 09/08/2019 (Shift-III) SSC CHSL 12/10/2020 (Shift-III) RRB JE - 2014 RRB Group-D 22-09-2018 (Shift-I)
■ भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे–	जुलाई 1946	SSC GD 22/11/2021 (Shift-II)
■ हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष _____ को संविधान दिवस' मनाते हैं–	26 नवंबर	SSC MTS 06/10/2021 (Shift-I)
■ संविधान सभा के सदस्यों ने _____ को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे–	24 जनवरी, 1950	SSC CHSL 16/04/2021 (Shift-II)
■ भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया–	1950	SSC GD 29/11/2021 (Shift-I)
■ संविधान सभा का दसवां अधिवेशन आयोजित किया गया था–	6-17 अक्टूबर, 1949	SSC CGL (Tier-I) 20/04/2022 (Shift-III)
■ दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में _____ सदस्य थे–	299	SSC GD 07/12/2021 (Shift-II)
■ संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष में परिवर्तित किया गया था–	1950	SSC GD 10/12/2021 (Shift-III)
■ संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी–	दिल्ली में	SSC JE Mechanical - 27/09/2019 (Shift-I) SSC JE Civil - 23/01/2018 (Shift-I)
■ भारत की संविधान सभा की हाउस (सदन) कमेटी के अध्यक्ष थे–	बी. पट्टाभि सीतारमैया	SSC CGL (Tier-I) 18/04/2022 (Shift-II)
■ अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की _____ के अध्यक्ष थे–	प्रत्यय पत्र समिति	SSC CGL (Tier-I) 19/04/2022 (Shift-I)
■ जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के _____ के अध्यक्ष थे–	प्रकार्य समिति	SSC CGL (Tier-I) 20/04/2022 (Shift-I)
■ स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे–	बी. आर. अम्बेडकर	SSC JE Civil 29.10.2020 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I) – 19/06/2019 (Shift-III)

■ भारत के पहले गृह मंत्री थे-	सरदार वल्लभभाई पटेल	SSC GD 29/11/2021 (Shift-II)
■ स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे-	बलदेव सिंह	SSC CHSL 18/03/2020 (Shift-III) SSC CHSL (Tier-I) –09/07/2019 (Shift-II)
■ भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ने की थी– डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा		SSC JE Civil - 23/01/2018 (Shift-I) SSC JE Electrical 26.09.2019 (Shift- I) SSC GD 18.02.2019 (Shift-III)
■ संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था–	सच्चिदानन्द सिन्हा	SSC Stenographer – 15/11/2021 : Shift-I
■ संविधान सभा की पहली बैठक हुई–	दिसम्बर 1946	SSC MTS 18/10/2021 (Shift-I)
■ ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया–	सरदार वल्लभ भाई पटेल	SSC MTS 13/08/2019 (Shift-II)
■ 1946 में मद्रास निवाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे–	अम्मू स्वामीनाथन	SSC CGL (Tier-I) 21/04/2022 (Shift-I)
■ भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे–	1946	SSC CHSL 13/10/2020 (Shift-II)

संविधान पर विदेशी प्रभाव

■ भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे–	फ्रांसीसी संविधान से	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022 RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-II) RPF Constable 05/02/2019 RRB ALP (Stage-II) 21/01/2021 RRB Group-D 22-10-2018 (Shift-II) RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI 17.11.2021 Shift-II SSC CHSL 26/10/2020 (Shift-II) SSC JE Civil - 25/01/2018 (Shift-I) SSC CHSL 07/06/2022 (Shift-I) SSC MTS 14/08/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के लिए DPSP (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) संविधान से प्रेरित थे–	आयरलैंड	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-I UPSI 13-11-2021 Shift-II RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-II) RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-III) UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2005 SSC GD 01/03/2019 (Shift-II) SSC CHSL (Tier-1) – 17/03/2023 (Shift-II) SSC CGL (Tier-1) – 24/07/2023 (Shift-III) SSC MTS– 08/05/2023 (Shift-III) SSC CGL (Tier-I) 21/04/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान में देशों से विशेषताएं (Features) ली गई हैं–	10	RRB Group-D – 23/08/2022 (Shift-II)
■ संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुएने कहा था, ‘संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है।’–	डॉ. बी. आर.अम्बेडकर	RRB NTPC 08.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है–	यह कई संविधानों का मिश्रण है	RRB JE - 28/05/2019 (Shift-II)

■ भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है— यूएसएसआर (सोवियत संघ) के संविधान से	RRB Group-D : 29/08/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III) RRB NTPC 02.04.2016 (Shift-III) Stage I st UP Lower (Pre) G.S., 2003-04 SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-III)
■ भारत के संविधान में अर्द्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है— कनाडा के संविधान से	RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-I)
■ भारत के संविधान की विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है— एकल नागरिकता	RRB Group-D – 14/09/2022 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है— डेनमार्क का संविधान	RRB NTPC 08.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत के ‘राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव’ के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था— दक्षिण अफ्रीका के संविधान से	RRB NTPC 22.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है— आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन	RRB NTPC 09.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए हैं— संयुक्त राज्य के संविधान से	RRB NTPC 20.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-II) UPSSSC Supply Inspector Exam. Date: 17/07/2022 UPSI 14-11-2021 Shift-II UPPSC AE-2007 (Paper-I) RRB Group-D 16-10-2018 (Shift-I) RRB Group-D 05-12-2018 (Shift-III) UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन (Rule of Law) का विचार लिया गया है— ब्रिटिश संविधान से	RRB NTPC 05.04.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 23.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान में “फर्स्ट पास्ट द पोस्ट” (सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय) का प्रावधान देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था— ब्रिटेन	RRB NTPC 03.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहित की गई थी— इंग्लैंड के संविधान से	RRB Group-D 30-10-2018 (Shift-I)
■ भारत के संविधान में ‘भाईचारे’ की भावना प्रेरित है— फ्रांसीसी क्रांति से	RRB Group-D 05-12-2018 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिये गए हैं— जर्मनी के संविधान से	RRB NTPC 02.04.2016 (Shift-I) Stage I st
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्दसे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है— रशियन क्रांति	RRB Group-D 12-12-2018 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में ग्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा (पुनरावलोकन) से अंगीकृत किए गए हैं— अमेरिकी संविधान	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान द्वारा..... देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है— ऑस्ट्रेलिया	RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा देश के संविधान से ‘केन्द्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने’ की संकल्पना को लिया गया था— कनाडा	UPSI 15.11.2021 Shift-II UPSSSC ASO 22/05/2022 UPPCS (Pre) Exam 2021 SSC CGL (Tier-I) – 04/06/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान में ‘शक्तिशाली केन्द्र वाला संघ (फेडरेशन विद स्ट्रांग सेटर)’ संविधान से ली गई विशेषता है— कनाडा का संविधान	UPSI 20.11.2021 Shift-I RRB NTPC 05.03.2021 (Shift-II) Stage Ist

■ भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं— रूप के संविधान से	UPSI Batch-3, 22 Dec 2017 RRB NTPC 22.01.2021 (Shift-I) Stage Ist SSC MTS 02/08/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान में वाक्यांश “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” की अवधारणा ली गई है— जापान के संविधान से	UPSI 22.11.2021 Shift-III UPP Constable, 18.06.2018 (Shift-1) SSC CHSL (Tier-1) – 10/08/2023 (Shift-II)
■ भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है— अर्द्ध-संघात्मक	UPPSC GIC 2008
■ भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है— ब्रिटेन	UPPSC AE-2013
■ भारत में संघ-राज्य संबंध में समानता पायी जाती है— कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में	UPPSC AE- 2007 Paper (I)
■ भारतीय संविधान में ‘द्विसदन प्रणाली’ की विशेषता के संविधान से ली गई है— ब्रिटेन	SSC CHSL (Tier-II) – 26/06/2023 SSC CGL (Tier-I) 11.04.2022 (Shift -III) SSC GD 03.12.2021 (Shift -III)
■ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है— भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन	SSC MTS/Havaldar-06/09/2023 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को _____ से लिया गया है— यूनाइटेड किंगडम	SSC MTS- 16/05/2023 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान में ‘संविधान में संशोधन का प्रस्ताव’ देश के संविधान से लिया गया है— दक्षिण अफ्रीका	SSC MTS 12/10/2021 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा से ली गई थी— ऑस्ट्रेलिया	SSC CHSL (Tier-1) – 07/08/2023 (Shift-IV)
■ भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत देश से लिया गया है— फ्रांस	SSC MTS 08/08/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का उपबन्ध कनाडा के संविधान से लिया गया है— उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार	SSC CHSL (Tier-1) – 09/03/2023 (Shift-I)
■ भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा देश से अपनाया है— इंग्लैण्ड	SSC JE Civil - 24/01/2018 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के ‘संसदीय विशेषाधिकार’ की विशेषता से ली गई है— ब्रिटेन से	SSC JE Mechanical - 25/09/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ‘कानूनों के समान संरक्षण’ की अवधारणा ली गई है— अमेरिकी संविधान से	UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ सही सुमेलन है— सूची-I (स्रोत) आयरलैण्ड जर्मनी सं0 रा0 अमेरिका ब्रिटेन	UPPSC Polytechnic Lecturer 2022 सूची-II (प्रावधान) राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपात उपबन्ध वित्तीय आपात संसदीय व्यवस्था

राष्ट्रीय प्रतीक

■ हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया—	श्री अरबिन्दो ने	UPSI (Pre), 2011
■ राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। इसकी लम्बाई का चौड़ाई से अनुपात है—	3 : 2	UPSI (Pre), 2011 आबकारी सिपाही - 25-09-2016 RRB NTPC 02.04.2016 (Shift-II) Stage I st SSC MTS 08/08/2019 (Shift-III)
■ हमारे राष्ट्रीय चिह्न के नीचे आदर्श वाक्य है—	सत्यमेव जयते	UPSI (Mains), 2014 RRB NTPC 07.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ भारतीय तिरंगे (तिरंगा) ध्वज में अशोक चक्र का रंग है—	गहरा नीला	Lower Exam – 30-09-2019 (Shift-II)
■ वर्ष 1950 में, फल को भारत के ‘राष्ट्रीय फल’ के रूप में अपनाया गया था—	आम	Lower Exam – 30-09-2019 (Shift-II)

■ भारत का राष्ट्र चिह्न लिया गया है-	सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ से	ग्राम विकास अधिकारी - 05-06-2016
■ संविधान सभा ने दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था—	22 जुलाई, 1947	RRB Group-D 02-11-2018 (Shift-I) RRB NTPC 06.04.2016 (Shift-I) Stage I st SSC MTS 05/08/2019 (Shift-I)
■ 'सत्यमेव जयते' उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण लिया गया है—	मुंडक उपनिषद् से	RRB NTPC 03.04.2016 (Shift-I) Stage I st RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 17.01.2017 (Shift-II) Stage I st
■ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है—	बरगद	RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ 'जन गण मन' को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था—	24 जनवरी, 1950 को	RRB NTPC 12.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय दिया जाता है—	पिंगली वेंकेया को	RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 27.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 30.03.2016 (Shift-II) Stage I st
■ विशाल गिलहरी (giant squirrel) राज्य की राजकीय पशु है—	महाराष्ट्र	RRB NTPC 09.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है—	बुड़ पिजन	RRB NTPC 05.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ—	2002 से	RRB NTPC 26.07.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय ध्वज संहिता, 2002 है—	कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है	RRB NTPC 05.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार, भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए, जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो—	दाएं छोर पर	RRB NTPC 08.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वह भारतीय राज्य जिसने मलखंभ (Malkhamb) को अपना राज्य खेल घोषित किया—	मध्य प्रदेश	RRB NTPC 20.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है—	धर्म के नियत का चक्र	RRB JE - 26/05/2019 (Shift-III)
■ कर्नाटक का राज्य फूल है—	कमल	RRB Group-D 24-10-2018 (Shift-III)
■ झारखंड का राज्य फूल है—	पलाश	RRB Group-D 01-10-2018 (Shift-III)
■ नागार्लैंड का राज्य फूल है—	बुरुंश का फूल (Rhododendron)	RRB Group-D 24-10-2018 (Shift-II)
■ आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है—	काला हिरन	RRB Group-D 03-10-2018 (Shift-I) RRB Group-D 03-10-2018 (Shift-III)
■ भारत का राष्ट्रीय जल-जीव है—	गंगा नदी की डॉल्फिन मछली	RRB NTPC Stage I st 19.01.2017 (Shift-I)
■ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक..... सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है—	अशोक	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-III) Stage II nd
■ भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था—	बंकिमचंद्र चटर्जी	RRB NTPC 29.03.2016 (Shift-I) Stage I st RRB NTPC 17.01.2017 (Shift-III) Stage I st
■ भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है—	फील्ड हॉकी	RRB NTPC 04.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं—	रवीन्द्रनाथ टैगोर	RRB NTPC 02.04.2016 (Shift-II) Stage Ist UPP Constable (Pre), 2013
■ वृषभ, चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंहचतुर्मुख स्तम्भशीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ—	26 जनवरी, 1950 को	UPSI Batch-1, 12 Dec 2017 RRB NTPC 12.04.2016 (Shift-I) Stage I st SSC CGL (Tier-I) 11/04/2022 (Shift-I)
■ संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया—	24 जनवरी, 1950	Assistant Professor (Pravakta) 2014

■ राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है-	सिक्किम	SSC Stenographer – 12/11/2021 : Shift-II
■ राजस्थान का राज्य पक्षी है-	सोन चिड़िया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड)	SSC MTS 20/10/2021 (Shift-I)
■ ‘चंदन’ _____ का राजकीय वृक्ष है-	कर्नाटक	SSC CHSL 11/08/2021 (Shift-III)
■ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में तीलियां हैं-	24	SSC GD 15/12/2021 (Shift-II)
■ राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था-	24 जनवरी, 1950	SSC MTS 07/08/2019 (Shift-I)
■ भारत का राष्ट्रीय गीत उपन्यास में परिलक्षित हुआ था-	आनंदमठ	SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-I)
■ ब्लू जे या इंडियन रोलर (नीलकंठ पक्षी) भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है-	3	SSC MTS 02/08/2019 (Shift-I)

संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका, विषयवस्तु एवं महत्व

■ भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है-	आमुख	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date: 17/07/2022
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है— व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को		UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
■ भारतीय संविधान अपने नागरिकों कोकी समानता का वचन देता है— हैसियत और अवसर		कनिष्ठ सहायक - 31-05-2019
■ “संविधान की आत्मा” के रूप में माना गया है—	प्रस्तावना को	राजस्व लेखपाल - 13-09-2015 (Morning) UPPCS (Pre.) G.S. 2008 UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2013, 2015 UP UDA/LDA (Pre.) G.S. 2006
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” शब्द लाया गया था— 42 वाँ संशोधन द्वारा		जूनियर इंजीनियर/तकनीकि - 27-12-2015 UPSI, 2001
■ के अनुसार, संसद ने संविधान में संशोधन (42वाँ संवैधानिक संशोधन) किया और संविधान की उद्देशिका में ‘पंथनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ को शामिल किया— अनुच्छेद 368		RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)
■ बयालीसवें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था— ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को		RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा ‘संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य’ शब्दों को बदलकर ‘संप्रभु समाजवादी’, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’ कर दिया गया, और ‘राष्ट्र की एकता’ शब्दों को भी बदलकर ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया— 42वें		RRB Group-D – 25/08/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-II) UPSI Batch-1, 21 Dec 2017
■ एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, कहलाती है— प्रस्तावना		RRB NTPC 08.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को— संशोधित किया जा सकता है		RRB NTPC 23.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है— संविधान की प्रस्तावना के अन्तर्गत		RRB NTPC 09.02.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI (Mains), 2001
■ संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के हिस्से में परिलक्षित होती है— प्रस्तावना		RRB Group-D 05-12-2018 (Shift-I)
■ संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है— प्रस्तावना		RRB J.E. -2014
■ भारत के संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में प्रयुक्त शब्द ‘गणतन्त्र’ सूचित करता है— कि देश का प्रधान, निर्वाचित प्रतिनिधि है		RRB J.E. -2014 UPPCS (Pre.) G.S. 1997 RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-II) UP SI (Main), 2014

■ एक धर्मनिरपेक्ष देश है-	भारत	RRB Group-D 05-10-2018 (Shift-II) UPP Constable (Main), 2014
■ एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है— उद्देश्यों एवं विचारों में समानता		UPP Constable (Main), 2014
■ प्रस्तावना को “संविधान की राजनीतिक कुंडली” के रूप में वर्णित किया था—के.एम. मंशी ने		UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ प्रस्तावना के अनुसार, भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है— भारत की जनता से		UPSI 13.11.2021 Shift-II
■ वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की ‘कुंजी (कीनोट)’ कहा था— सर अर्नेस्ट बार्कर		UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए ‘न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक’ का आदर्श लिया गया है— रूसी क्रांति से		UPSI 14.11.2021 Shift-I
■ केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था— उद्देशिका को		UPSI 14.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच ‘सामान्य भाईचारे’ की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है— बंधुता		UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द पद जिसका अर्थ है ‘विशेषाधिकार का अभाव’—		UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ 26 नवम्बर, 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है— धर्मनिरपेक्ष शब्द का		UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक बार संशोधन किया गया है— 1		UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है— समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और सम्प्रभुता		UPSI Batch-3, 16 Dec 2017
■ शब्द ‘समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता’ संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे— सन् 1976 में		UPSI Batch-1, 19 Dec 2017
■ संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गयी है— उद्देशिका को		UPSI (Mains), 2014
■ भारत में सर्वोच्च है— संविधान		UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ संविधान का वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है— भाग 7		UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है— संघीय		UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है— सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक		UPPCS RO/ARO (Pre) 2021
■ ‘संविधान की मूल संरचना’ की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी— केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य		UPPCS (Pre) Exam 2022
■ वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है— आर्थिक स्वतन्त्रता		UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ ‘इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ होगा’, (भारतीय संविधान)। ‘यूनियन’ शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया है— कनाडा		UPPCS (J) 2023
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है— आर्थिक स्वतंत्रता का		UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2008
■ उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि ‘उद्देशिका संविधान का भाग है’— बोम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया		UPPCS (Pre.) G.S. 2012
■ भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है— यू.एस.ए. के संविधान से		UPPCS (Pre) G.S. 2015
■ भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है— संविधान की प्रस्तावना		UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2005
■ भारत के संदर्भ में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द का सही भाव व्यक्त करता है— भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है		UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2005 UPP Constable (Main), 2014
■ भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करता है— संविधान की प्रस्तावना		U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है— धार्मिक न्याय		UP Lower (M) G.S. 2013

■ भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है-	साम्यवादी राज्य	UP Lower (M) G.S. 2015-16
■ भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है-	योजनाबद्ध विकास	UPPSC AE-2011
■ भारतीय संविधान में शब्द का उल्लेख नहीं है-	संघवाद	SSC CHSL (Tier-1) – 04/08/2023 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है-	SSC MTS– 02/05/2023 (Shift-I)	बंधुता
■ संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था-	जवाहरलाल नेहरू ने	SSC JE Mechanical 11.12.2020 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है-	विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता	SSC CHSL (Tier-1) – 03/08/2023 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान को 'अर्ध संघीय' कहा-	के.सी. हीयर	SSC CHSL 03/06/2022 (Shift-II)
■के मामले में, एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था-	समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य	UPSI 13.11.2021 Shift-I
■ सही सुमेलन है-		UPPCS (Pre) Exam 2021
सूची-I	सूची-II	
गोलकनाथ वाद	वर्ष 1967	
24वां संविधान संशोधन अधिनियम	वर्ष 1971	
केशवानन्द भारती वाद	वर्ष 1973	
42वां संविधान संशोधन अधिनियम	वर्ष 1976	

संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग

■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि "भारत, राज्यों का एक संघ होगा"- अनुच्छेद 1	UPSSSC ASO 22/05/2022 UPSSSC Assit.Boring Technician 3-7-2022 (U.P.P.C.S. (J) G.K., 2016) SSC GD – 01/02/2023 (Shift-II)
■ वह अनुच्छेद जो "धन विधेयक" को परिभाषित करता है- अनुच्छेद 110	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-II RRB NTPC 29.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद-343के बारे में है- संघ की राजभाषा	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-II
■ भारत के संविधान में अनुसूचियाँ हैं- 12	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022 RRB Group-D – 27/09/2022 (Shift-I) UPSI Batch-2, 15 Dec 2017 UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं- अनुच्छेद 29	UPSSSC PET 24/08/2021 Shift-I (U.P.P.C.S. (J) G.K., 2016)
■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल-बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं- दसवीं अनुसूची	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I RRB Group-D 12-11-2018 (Shift-III) UPPSC AE 2021 UP Lower (M) G.S. 2013 UPPSC AE-2011 UPSI Batch-3, 14-12-2017
■ पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों (फिफ्थ शिड्यूल एरिया) वाले राज्य, पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत) से संबंधित अधिनियम, 1996 के तहत आते हैं- 10	UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-II
■ अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है- 108	UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-II RRB NTPC 30.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 09.02.2021 (Shift-I) Stage Ist UPPCS RO/ARO (Mains) 2021 SSC JE Mechanical – 23/03/2021 (Shift-II)

■ राज्य सभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके—	249	UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-II UPSI 22.11.2021 Shift-I UPPSC AE-2013
■ भारतीय संविधान का का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय-विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगता है—	23	UPSSSC Homeopathic Pharmacist 24/10/2019
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है—	14	Cane Supervisor (31.08.2019) (U.P.P.C.S. (J) G.K., 2016)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11..... पहलू से संबंधित है— भारत की नागरिकता		Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A गारंटी देता है— कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा		Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324-329पहलू से संबंधित है— चुनाव		Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-II) जूनियर इंजीनियर/तकनीकी - 27-12-2015
■ भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है— पंचायती राज प्रणाली का		लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने 'भारत रत्न' और 'पद्मश्री' को प्राप्त किया— अनुच्छेद 18		लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है— अनुच्छेद 49		व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-I)
■ भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान हैं— छठी		व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का भाग II संबंधित है— नागरिकता से		ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- II) UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ 'अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण' के लिए प्रावधान किए गए हैं— 5वीं अनुसूची में		ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- II)
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित आयोग का गठन किया जाता है— हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर		ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है— अनुच्छेद 244		विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift- II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी— अनुच्छेद 75 (1)		विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift- II)
■ भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है— अनुच्छेद 213		लोअर तृतीय - 26-06-2016
■ संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है— सार्वजनिक स्वास्थ्य		ग्राम विकास अधिकारी - 23-12-2018 (shift- II)
■ अंगीकृत किए जाने के समय, भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः थे— 395 अनुच्छेद		RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-II) RRB NTPC 07.01.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI Batch-2, 13 Dec 2017 SSC CGL (Tier-1) – 25/07/2023 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है— 14 वर्ष	14	RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है— 50		RRB Group-D – 17/09/2022 (Shift-I)
■ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, भारतीय संविधान की 'अनुसूची' में शामिल हैं— सातवीं अनुसूची		RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-II) UPSI 13.11.2021 Shift-II UPPCS RO/ARO (Mains) 2021

■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है—	8वीं अनुसूची	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-I) RRB Group-D 05-11-2018 (Shift-II) UPSI Batch-2, 20 Dec 2017 UPP Constable, 19.06.2018 (Shift-2)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है—	22 भागों में	RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-III) RRB JE - 30/05/2019 (Shift-II)
■ संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है—	3 सूचियों के रूप में	RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-I)
■ अनुच्छेद 279A संवैधानिक निकाय से संबंधित है—	वस्तु एवं सेवा कर परिषद	RRB Group-D – 17/08/2022 (Shift-II) UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है—	अनुच्छेद 341	RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है—	राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से	RRB NTPC 21.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं—	अनुच्छेद 72	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-I) Stage Ist UPPCS (J) 2023 UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II UPPSC Polytechnic Lecturer 2021
■ वह विषय जो समवर्ती सूची (Concurrent list) के अंतर्गत आता है—	वन	RRB NTPC 19.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है—	समवर्ती सूची में	RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है—	व्यक्तिगत स्वतंत्रता से	RRB NTPC 15.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है—	जीने का अधिकार (Right to life)	RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21A में अधिनियम का उल्लेख किया गया है—	शिक्षा का अधिकार	RRB JE - 26/06/2019 (Shift-III) RRB NTPC 02.04.2016 (Shift-II) Stage I st RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-III) Stage II nd
■ संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है—	अनुच्छेद-21	RRB NTPC 16.04.2016 (Shift-I) Stage I st RRB NTPC 27.03.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB JE - 29/05/2019 (Shift-I) UPPSC Polytechnic Lecturer 2022
■ आपातकाल के समय अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है—	अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21	RPF SI 18/01/2019 (Shift-II)
■ संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्म-संभ्रांत (स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण) साक्ष्य प्रतिबंधित है—	अनुच्छेद 20	RPF SI 18/01/2019 (Shift-II)
■ अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे—	एन. गोपालस्वामी आयंगर	RRB NTPC 12.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है—	अनुच्छेद 43	RRB NTPC 09.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को निर्धारित करता है—	अनुच्छेद 51	RRB NTPC 08.03.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान के भाग IV का अनुच्छेद 43 B संबंधित है—	सहकारी समितियों से	RRB NTPC 27.02.2021 (Shift-II) Stage Ist

■ भारतीय संविधान के वे दो अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है— अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226	RRB NTPC 08.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट (आदेश) जारी कर सकते हैं— अनुच्छेद 226	RPF SI 18/01/2019 (Shift-II) UPSI 20.11.2021 Shift-II UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है— वित्त आयोग से	RRB NTPC 31.07.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है— नागालैंड	RRB NTPC 19.03.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB Group-D 13-12-2018 Shift-II SSC CHSL (Tier-1) – 20/03/2023 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है— अनुच्छेद 3	RRB NTPC 07.04.2021 (Shift-I) Stage Ist SSC CHSL (Tier-I) 17-08-2023 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I) 12-06-2019 (Shift-III) UPSI Batch-1, 15 Dec 2017 UPSI Batch-1, 16 Dec 2017
■ 44वें संशोधन (1978) ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद को प्रभावित किया— 300(a)	RRB NTPC 14.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है— सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता	RRB NTPC 28.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है— अनुच्छेद 29	RRB NTPC 22.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 01.04.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 18.04.2016 (Shift-I) Stage I st
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा— अनुच्छेद 40	RRB NTPC 02.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है— अनुच्छेद 18	RRB NTPC 02.02.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI 15.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं— अनुच्छेद 243	RRB NTPC 02.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ संविधान के अनुच्छेद में 'केंद्रीय बजट' को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है— अनुच्छेद 112	RRB NTPC 31.01.2021 (Shift-II) Stage Ist (U.P.P.C.S. 2003, 2007) SSC JE Electrical – 24/03/2021 (Shift-I)
■ वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है— अनुच्छेद 263	RRB NTPC 11.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 31.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वित्तीय आपातकाल (Financial emergency) संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है— अनुच्छेद -360	RRB NTPC 25.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है— संविधान के संशोधन से	RRB NTPC 25.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद का भाग XX संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है— अनुच्छेद 368	RRB NTPC 26.07.2021 (Shift-I) Stage Ist UPPCS (Main) G.S. II nd 2008
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है— अनुच्छेद 169	RRB NTPC 19.01.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI 20.11.2021 Shift-II
■ संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत, भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है— अनुच्छेद 32	RRB NTPC 19.01.2021 (Shift-I) Stage Ist

■ भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है— राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से	RRB NTPC 15.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान, राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है— अनुच्छेद 123	RRB NTPC 15.03.2021 (Shift-I) Stage Ist ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है— अनुच्छेद 23	RRB NTPC 10.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था— वर्ष 1954 में	RRB NTPC 29.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में 'अवसरों की समानता' की गारंटी प्रदान की गई है— अनुच्छेद 16	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 08.01.2021 (Shift-I) Stage Ist SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift- III)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है— अनुच्छेद 19	RRB NTPC 26.07.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है— पहली	RRB NTPC 08.02.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 17.01.2017 (Shift-I) Stage I st RRB NTPC 12.04.2016 (Shift-III) Stage I st UPSI Batch-2, 19 Dec 2017 UPSI 16.11.2021 Shift-III UPPCS (Main) G.S. II nd 2014 UPPSC AE- 2007 Paper (II) SSC JE Electrical -26/09/2019 (Shift-II) SSC JE Civil - 27/01/2018 (Shift- II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है— अनुच्छेद 356	RRB JE - 24/05/2019 (Shift-I)
■ अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है— एंगलो-इंडियन समुदाय	RRB JE - 25/05/2019 (Shift-I)
■ संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है— प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित	RRB JE - 27/05/2019 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए— राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	RRB JE - 02/06/2019 (Shift-I)
■ वह अनुच्छेद जो 'मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है— अनुच्छेद 23	RRB JE - 22/05/2019 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है— अनुच्छेद 19 (1)	RRB Group-D 02-11-2018 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा— अनुच्छेद 164	RRB Group-D 30-10-2018 (Shift- II)
■ वह राज्य जो संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है— नगालैंड	RRB NTPC Stage I st 28.04.2016 (Shift-III) UPSI Batch-I 16-12-2017
■ हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा— अनुच्छेद 100	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-II) Stage II nd

■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है— बजट	RRB NTPC 19.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं— नौवीं अनुसूची में	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं— बारहवीं अनुसूची में	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ राज्य सभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है— 4वीं	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ वह भाषा जो संविधान की रचना के समय, 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी— कश्मीरी	UPSI Batch-2, 22 Dec 2017
■ शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान कीअनुसूची में उल्लेख किया गया है— तीसरी	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017 UPSI 20.11.2021 Shift-II UPSI 22.11.2021 Shift-III
■ भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है— उपराष्ट्रपति के चुनाव से	UPP Constable, 25.10.2018
■ भारत का संविधान लागू होने के समय, इसमें अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थीं— 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ	UPSI (Ranker), 2011
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 'दोहरी परिसंकट' के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है— अनुच्छेद 20	UPSI 13.11.2021 Shift-I
■ संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख है— सप्तम अनुसूची में	UPSI (Mains), 2014 UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2006
■ वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो— अनुच्छेद 256	UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले— अनुच्छेद 257	UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है— अनुच्छेद 24	UPSI 14.11.2021 Shift-I UPPSC AE-2011 UPPSC AE-2013 UPPSC AE-2008
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को “आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए” निर्देश देता है— अनुच्छेद 48	UPSI 20.11.2021 Shift-II
■ वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा-सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है— अनुच्छेद 33	UPSI 20.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है— अनुच्छेद 312	UPSI 17.11.2021 Shift-III UPPCS (Main) G.S. IIInd 2012
■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है— ग्यारहवीं अनुसूची	UPSI 17.11.2021 Shift-III UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II SSC MTS 08/08/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है— अनुच्छेद 30	UPSI 17.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है— अनुच्छेद 66	UPSI 17.11.2021 Shift-III RRB JE - 27/06/2019 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉ. बी आर अब्देलकर द्वारा "भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं" के रूप में वर्णित किया गया था— भाग IV	UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद, जो राज्य को “समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने” का निर्देश देता है— अनुच्छेद 39A	UPSI 14.11.2021 Shift-II UPSI 17.11.2021 Shift-II

■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है— अनुच्छेद 352	UPSI 12.11.2021 Shift-II UP Lower (Pre) G.S., 2002
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी— अनुच्छेद 124	UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान वह अनुच्छेद जो “राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया” से संबंधित है— अनुच्छेद 55	UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ‘बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार’ से संबंधित है— अनुच्छेद 19(1)(b)	UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ‘कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा’ प्रदान करता है— अनुच्छेद 22	UPSI 12.11.2021 Shift-I SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो “निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक” प्रदान करता है— अनुच्छेद 329	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो “उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि” से संबंधित है— अनुच्छेद 219	UPSI 14.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत ‘राज्यों में विधायिका’ का गठन किया गया था— अनुच्छेद 168	UPSI 14.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान में ‘संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार’ अनुच्छेद में निहित किया गया है— अनुच्छेद 19	UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है— अनुच्छेद 105	UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का वह भाग जो ‘राज्य लोक सेवा आयोग’ से संबंधित है— भारतीय संविधान के भाग XIV	UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है— अनुच्छेद 324	UPSI 15.11.2021 Shift-I UPPSC Polytechnic Lecturer 2022
■ भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान (44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978) द्वारा के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था— अनुच्छेद 300-A	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है— अनुच्छेद 131	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था— नौवीं अनुसूची	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है— गौण वनोपज	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है— अनुच्छेद 143	UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ “भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।” यह भारत के संविधान के अनुच्छेद.....में घोषित किया गया है— अनुच्छेद 14	UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान के भाग III में उल्लेख किया गया है— मौलिक अधिकारों का	UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान के भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं— भाग IXA	UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है— अनुच्छेद 75	UPSI 17.11.2021 Shift-II

■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को 'धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है-	UPSI 17.11.2021 Shift-III अनुच्छेद 39
■ भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है-	UPSI 20.11.2021 Shift-II भाग III
■ भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं-	UPSI 20.11.2021 Shift-II अनुच्छेद 82 और 170
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 'व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता' से संबंधित है-	UPSI 20.11.2021 Shift-I अनुच्छेद 301
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है-	UPSI 20.11.2021 Shift-I अनुच्छेद 243-K
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 'अंतःकरण की स्वतंत्रता' की गारंटी देता है-	UPSI 20.11.2021 Shift-III अनुच्छेद 25
■ भारतीय संविधान,के तहत छ: से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है-	UPSI 20.11.2021 Shift-III अनुच्छेद 21 A
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है-	UPSI 20.11.2021 Shift-III UPSI 21.11.2021 Shift-I अनुच्छेद 280
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे-	UPSI 21.11.2021 Shift-I अनुच्छेद 13
■ भारतीय संविधान का "अनुच्छेद 243A" संबंधित है-	ग्राम सभा से UPSI 22.11.2021 Shift-III UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था-	UPSI 16.11.2021 Shift-II भाग IX - A
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को 'मातृत्व राहत' प्रदान करने का निर्देश देता है-	UPSI 16.11.2021 Shift-II अनुच्छेद 42
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 'समान कार्य के लिए समान वेतन' से संबंधित है-	UPSI 16.11.2021 Shift-II अनुच्छेद 39
■ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'सहकारी समितियाँ' विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं-	UPSI 16.11.2021 Shift-II केवल राज्य विधानमंडल
■ भारतीय संविधान का "अनुच्छेद 30" संबंधित है-	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार से UPSI 16.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, विषय 'राज्य सूची' में शामिल एक स्वच्छता	UPSI 14.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है-	UPSI 14.11.2021 Shift-I UPPSC GIC 2021 अनुच्छेद 165
■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आबंटन से संबंधित है-	UPSI 15.11.2021 Shift-II चौथी अनुसूची
■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान हैं-	UPSI 15.11.2021 Shift-III द्वितीय अनुसूची
■ भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है-	UPSI 13.11.2021 Shift-II भाग XI UPPSC Polytechnic Lecturer 2021 UP RO/ARO (Pre) G.S. 2014 UPPCS (Mains) Spl. G.S. II nd 2004 SSC CGL (Tier-I) – 04/06/2019 (Shift-III) SSC MTS 12/10/2021 (Shift-II)

■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है— अनुच्छेद 74 और 75	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘परमाणु ऊर्जा’ विषय पर कानून बनाने का अधिकार है— केवल संसद के पास	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानपंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है— अनुच्छेद 323 B	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्रदान करता है— अनुच्छेद 32	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं— 4	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ वह विषय जिसको ‘राज्य सूची’ से ‘समवर्ती सूची’ में स्थानांतरित किया गया था— शिक्षा	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की..... अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके— नौर्वीं	UPSI 22.11.2021 Shift-I UPPSC AE- 2007 Paper (I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय राज्य (भारत राष्ट्र) के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है— अनुच्छेद 25	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान के भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने ‘संविधान की चेतना’ के रूप में वर्णित किया था— भाग III और भाग IV	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ भारत के राष्ट्रपति ने बी.जी. खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी— सन् 1955 ई. में	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है— अनुच्छेद 15 (3)	UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को, “पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने” का निर्देश देता है— अनुच्छेद 44	UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है— अनुच्छेद 315	UPPCS (J) 2023 आबकारी सिपाही - 25-09-2016
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं— अनुच्छेद 21	UPPCS (J) 2023
■ भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर-पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती— नागलैण्ड	UPPCS (J) 2023
■ सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है— अनुच्छेद- 75 (3)	UPPSC Ayurvedacharya 2022
■ भारत के संविधान के भाग IX-A में, क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाईयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया— शहरी क्षेत्र	UPPCS RO/ARO (Mains) 2021
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित है— अनुच्छेद 267	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारत के संविधान में विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है— भाग – IX	UPPSC Unani Medical Officer 2018
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है— अनुच्छेद 343	UPPSC Staff Nurse 2017 (2022)
■ भारत के संविधान के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकरण का सम्बन्ध है— अनुच्छेद 323 A से	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं— त्रिपुरा राज्य पर	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया— बेरुबारी केस	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II

■ भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राथिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है-	अनुच्छेद 265	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2007 UPSI 14.11.2021 Shift-III UPPCS (Pre.) G.S., 1999
■ भारतीय संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गयी है-	अनुच्छेद 19 (1) (d-e), 301 एवं 301 से 307 द्वारा	
■ लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है-	अनुच्छेद 331	UPPCS (Pre.) Re-exam. G.S. 2015 UPPCS (Main) G.S. II nd 2015 UPPCS (Pre.) G.S. 2013
■ भारतीय संविधान में राज्य विधान सभाओं में आँग्ल-भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है-	अनुच्छेद 333	UPPCS (Pre.) G.S., 2015
■ भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, की गयी है-	अनुच्छेद 350 (क)	UPPCS (Pre.) G.S., 2002 UP Lower (Pre.) G.S., 2002 UPPSC AE-2013
■ भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है-	अनुच्छेद 371	UPPCS (Pre.) G.S., 1997
■ संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विशेष प्रावधान किया गया है-	महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए	UPPCS (Main) G.S. II nd 2011
■ समवर्ती सूची का विषय है-	आपराधिक मामले	UPPCS (Main) G.S. II nd 2005
■ यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए-	पहली अनुसूची को	UP Lower (Pre.) G.S. SPL. 2008
■ संविधान की चौथी अनुसूची को सही-सही वर्णित करता है-	इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन	UPPCS (Main) G.S. II nd 2015
■ भारत के संविधान में राज्य-सूची में सम्मिलित नहीं है-आपराधिक (दण्ड) प्रक्रिया संहिता		UUPPCS (Main) G.S. II nd 2006
■ ‘विवाह’, ‘विवाह विच्छेद’ और ‘गोद लेना’ संविधान की सातवीं सूची में सम्मिलित किये गये हैं-	समवर्ती सूची	UPPCS (Main) G.S. II nd 2006 UP Lower (Pre.) G.S. Spl. 2008
■ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III समवर्ती सूची में शामिल है-दण्ड प्रक्रिया		UPPCS (Main) G.S. II nd 2011
■ सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है-	सातवीं अनुसूची में	UP Lower (Pre) Spl. G.S., 2002
■ विधायी शक्तियों का केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है-	सातवीं अनुसूची	UP Lower (Pre.) G.S. 2008
■ आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है-	समवर्ती सूची	UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2006 UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु, सम्मिलित किया गया है-	9वीं अनुसूची	UPPCS (Main) G.S. 2003
■ भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है-	22 भागों में	UPPCS (Main) G.S. II nd 2012 U.P. Lower Pre. 2004-05 UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper 2008
■ भारतीय संविधान का भाग XVI (अनुच्छेद 330 से 342 तक) सम्बन्धित है-		UPPCS (Main) Spl. II nd 2004
लोकसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इण्डियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से		
■ संविधान का भाग VI सम्बन्धित है-	राज्य से	U.P. Lower (Pre.) 2004-05
■ हमारे संविधान में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है-	भाग 9	U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013
■ नागरिकता सम्बन्धित है-	अनुच्छेद 05 से	(U.P.P.C.S. (J) G.K., 2016)
■ भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धान्त को शामिल किया गया है-	अनुच्छेद 21	UPPCS (Main) G.S. II nd 2014
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त ‘हिन्दू’ शब्द सम्मिलित नहीं करता-		UPPCS (Main) G.S. II nd 2014
पारसी धर्म मानने वालों को		
■ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है-	गैस	UPPCS (Pre) G.S., 1997
■ भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है-	संघीय सरकार को	UPPCS (Pre.) G.S., 1995
■ वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है-	अनुच्छेद 117	UPUDA/LDA Special (Mains) G.S., 2010

■ ‘भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्रायें’ का विषय प्रगणित है—	संघ सूची	U.P. Civil Judge (Pre.) 2013
■ संविधान में यह उपबन्धित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा— अनुच्छेद 393		UPPCS (Pre.) 2010
■ संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना साठ दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है— अनुच्छेद 101 (4)		(U.P. Lower (Spl.) 2002, 2003)
■ संविधान के अन्तर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के सम्बन्ध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है— अनुच्छेद 103		(UP Lower 2002)
■ भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है— अनुच्छेद 137		(U.P. Lower SPL 2005)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है— अस्थाई		UPPSC AE- 2007 Paper (I)
■ भारत के संविधान में ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द पहली बार आया है— अनुच्छेद 16(4) में		UPPSC AE-2008
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है— अनुच्छेद-17		UPPSC AE-2008 SSC JE CIVIL 11/10/2023 (Shift-II)
■ संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अन्तर्गत संसद को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है— अनुच्छेद 253		UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ वे तीन भाषाएँ हैं जो संविधान के VIII अनुसूची में, 71 वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गयी हैं— कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली		UPPSC AE-2004
■ भारतीय संविधान, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है— संविधान के अनुच्छेद 323(क) के अंतर्गत		UPPSC AE-2011
■ लोक पद के अनुचित ग्रहण का सुधार जिस ‘रिट’ (याचिका) किया जा सकता है, वह है— अधिकार पृच्छा		UPPSC AE-2011
■ भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय है— 97 (वर्तमान में 100 विषय)		UPPSC AE-2013
■ भारतीय संविधान का भाग XVI _____ से संबंधित है— कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान		SSC MTS- 18/05/2023 (Shift-I)
■ विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है— कृषि		SSC MTS- 10/05/2023 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है— कारखाने		SSC CHSL (Tier-1) – 17/03/2023 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान की में संघ सूची से संबंधित प्रावधान हैं— सातवीं अनुसूची		SSC MTS/Havaldar- 08/07/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है— भाग V		SSC CGL (Tier-1)- 17/07/2023 (Shift-II)
■ मूल भारतीय संविधान में.....भाग और 395 अनुच्छेद है— 22		SSC JE Mechanical - 27/09/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है— 20		SSC MTS 06/10/2021 (Shift-II)
■ भारत के संविधान का नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है— भाग- IVA		SSC MTS 05/10/2021 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है— स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय		SSC CPO-SI 23/11/2020 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है— 13		SSC MTS 07/10/2021 (Shift-III)
■ भारत के संविधान का वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे (सूट) से संबंधित है— भाग XII		SSC MTS 13/10/2021 (Shift-III)
■ ‘पुलिस और लोक व्यवस्था’, भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं— 7वीं		SSC MTS 26/10/2021 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है— भाग V		SSC GD 07/12/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान की संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है— सातवीं अनुसूची		SSC CHSL 03/06/2022 (Shift-III)

■ भारत के संविधान का भाग III संबंधित है—	मूल अधिकार से	SSC CHSL 07/06/2022 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का राज्य विधानमंडल से संबंधित है—	भाग VI	SSC CHSL 09/06/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं—	12	SSC MTS 05/08/2019 (Shift-I)
■ राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है—	मिजोरम	SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-I)
■ भारत के संविधान का भाग-VIIIसे संबंधित है—	केन्द्र शासित प्रदेशों	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 05/03/2020 (Shift-II)
■ भारत के संविधान की का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है—	दूसरी अनुसूची-भाषाएँ	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 07/03/2020 (Shift-II)
■ भारत के संविधान की अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है—	चौथी	SSC JE Electrical 28.10.2020 (Shift-I) SSC CHSL 04.08.2021 (Shift -III) SSC MTS 13/10/2021 (Shift-I)
■ संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय में आता है—	समवर्ती सूची	SSC JE Mechanical 27.10.2020 (Shift-I)
■ अधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है—	8वीं	SSC JE Civil - 23/09/2019 (Shift-I) SSC GD 24/11/2021 (Shift-I) SSC JE Civil - 25/01/2018 (Shift-II)
■ भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई (E) में वेतन/ परिलिंबियों का उल्लेख है—	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के	SSC JE Civil - 23/09/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध से है—	महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन	SSC JE Civil - 25/01/2018 (Shift-I)
■ भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है—	रेलवे	SSC JE Electrical -26/09/2019 (Shift-II)
■ भारत के संविधान के अनुसार, ‘पशुधन और पशुपालन’ का विषय —— में शामिल है—	राज्य सूची	SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान की के अंतर्गत खेल का विषय आता है—	राज्य सूची	SSC MTS 07/08/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है—	भाग XIV	SSC CHSL 27/05/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी—	अनुच्छेद 239AA	SSC Selection Posts XI– 27/06/2023 (Shift-III)
■ संविधान के यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए—	अनुच्छेद 51A (a)	SSC JE CIVIL 09/10/2023 (Shift-I)
■ संविधान के मौलिक कर्तव्य – “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना” पर जोर देता है—	अनुच्छेद 51A (c)	SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-I)
■ अनुच्छेद 51A के खंड (k) के संशोधन के अनुसार जो माता-पिता या संरक्षक हैं, वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें—	6 से 14 वर्ष	SSC JE CIVIL 11/10/2023 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है—	अनुच्छेद 246	SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-III)
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी—	164	SSC JE CIVIL 11/10/2023 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के सन्दर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है—	अनुच्छेद 371	SSC CHSL (Tier-I) – 21/03/2023 (Shift-IV)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से संबंधित है—	लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों	SSC CGL (Tier-1) – 24/07/2023 (Shift-III)
■ अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी—	विधान-परिषद	SSC CGL (Tier-1) – 19/07/2023 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि ‘इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ है’, का उल्लेख करता है—	सहकारी संघवाद	SSC CHSL (Tier-1) – 09/08/2023 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद-2 सम्बन्धित है—	नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से	SSC CHSL (Tier-1) – 09/03/2023 (Shift-IV)

■ भारतीय संविधान के में यह उल्लेख है कि 'राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राजप्रमुख, अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे—	अनुच्छेद-361	SSC CHSL 16/04/2021 (Shift-III)
■ संविधान का अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत 'लाभ का पद' रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है—	102	SSC Stenographer – 12/11/2021 : Shift-I
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं—	246	SSC MTS 05/10/2021 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्ता सुनिश्चित हुई—	वर्ष 1949	SSC MTS 14/10/2021 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं— अनुच्छेद 52 से 78		SSC CHSL 27/05/2022 (Shift-III)
■ भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A संबंधित है—	संपत्ति का अधिकार से	SSC JE Mechanical – 22/03/2021 (Shift-I)
■ अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है—	105	SSC JE Civil 30.10.2020 (Shift-II)
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि 'व्यय का वार्षिक विवरण' संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए—	राष्ट्रपति	SSC JE Electrical 28.10.2020 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है—	110	SSC CHSL 09/06/2022 (Shift-II) SSC MTS 08/10/2021 (Shift-I)
■ अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है—	370	SSC MTS 06/08/2019 (Shift-III)
■ हाल ही में हटाया गया 'अनुच्छेद 370' भारत के राज्य से संबद्ध है—	कश्मीर	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 04/03/2020 (Shift-III)
■ भारत के संविधान के में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है—	अनुच्छेद 330	SSC CHSL (Tier-I) – 09/07/2019 (Shift-I) SSC Stenographer – 12/11/2021 : Shift-II
■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल-बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है—	दसर्वीं	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ सही सुमेलित है— (प्रावधान)	(संविधान का भाग)	UPPCS (Pre) 2023
राजभाषा	- भाग- 17	
संघ राज्य क्षेत्र	- भाग- 8	
अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र	- भाग- 10	
अधिकरण	- भाग 14 (क)	
■ सही सुमेलित है— सूची - I सूची - II अनुच्छेद- 324 निर्वाचन आयोग अनुच्छेद- 315 लोक सेवा आयोग अनुच्छेद- 280 वित्त आयोग अनुच्छेद- 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	UPPCS (Pre) 2023	
■ सही सुमेलन है— सूची-I (प्रावधान) सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष संसद के सदनों का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन	सूची-II (अनुच्छेद) 127 93 83 86	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II

<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>सूची-I (संविधान के भाग)</p> <p>भाग-1 भाग-2 भाग-3 भाग-4 भाग-4A</p>	<p>सूची-II (विषय)</p> <p>संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र नागरिकता मौलिक अधिकार राज्य के नीति-निदेशक तत्व मौलिक कर्तव्य</p>	UPPCS (Pre) Exam 2022
<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>(अनुसूची)</p> <p>तृतीय अनुसूची चतुर्थ अनुसूची</p> <p>सातवीं अनुसूची आठवीं अनुसूची</p>	<p>(विषय)</p> <p>शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा में स्थान का आवंटन संसद और राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनायी जाने वाली विधियों की विषय सूची भाषाएँ</p>	UPPCS (Pre) Exam 2022
<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>सूची-I अनुच्छेद - 52 अनुच्छेद - 51क अनुच्छेद - 154 अनुच्छेद - 165</p>	<p>सूची-II</p> <p>भारत का एक राष्ट्रपति होगा मौलिक कर्तव्य राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य का महाधिवक्ता</p>	UPPSC GDC 2021
<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>सूची-I समानता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार</p>	<p>सूची-II</p> <p>अनुच्छेद 14 – 18 अनुच्छेद 23 – 24 अनुच्छेद 25 – 28 अनुच्छेद 29 – 30</p>	UPPSC GDC 2021
<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>सूची-I (विषय)</p> <p>न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना</p>	<p>सूची-II (सम्बन्धित अनुच्छेद)</p> <p>अनुच्छेद - 50 अनुच्छेद - 46 अनुच्छेद - 40</p>	UPPCS (Pre) Exam 2021
<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>सूची-I संविधान का भाग XV संविधान का भाग XVII संविधान का भाग XVIII संविधान का भाग XX</p>	<p>सूची-II</p> <p>निर्वाचन राजभाषा आपात उपबंध संविधान संशोधन</p>	UPPCS (J) 2023
संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र		
<p>■ को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र को अलग कर उत्तराखण्ड नामक एक नया राज्य बनाया गया-</p>	<p>व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-I) 9 नवंबर, 2000</p>	
<p>■ भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था-</p>	<p>वर्ष 1956 में</p>	<p>लोअर द्वितीय - 15-07-2018</p>
<p>■ त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया-</p>	<p>1972 में</p>	<p>कनिष्ठ सहायक - 31-05-2015</p>

■ आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है-	तेलंगाना राज्य	RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-I)
■ मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी होता है-	उपराज्यपाल	RRB Group-D – 25/08/2022 (Shift-III)
■ महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन में हुआ था-	1960	RRB NTPC 16.01.2021 (Shift-I) Stage Ist (UPPCS (J) G.K., 2016) SSC MTS 14/10/2021 (Shift-II)
■ भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है-	संसद	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-I)
■ 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था-	तेलंगाना	RRB NTPC 30.12.2020 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 05.03.2021 (Shift-II) Stage Ist UPP Constable (Pre), 2013 RRB Group-D 01-12-2018 (Shift-II) RRB Group-D 24-10-2018 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि 'भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा'-	अनुच्छेद 1	RRB NTPC 23.07.2021 (Shift-I) Stage Ist UPPCS Spl. (Pre.) G.S. 2008
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 ए में राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया था-	जम्मू-कश्मीर	RRB Group-D 12-12-2018 (Shift-III)
■ उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है-	सन् 1950 में	RRB Group-D 25-10-2018 (Shift-II)
■ 1949 में भारत का हिस्सा बना था-	त्रिपुरा	RRB Group-D 23-10-2018 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित है-	भाग VIII	RRB JE - 24/05/2019 (Shift-III)
■ 21 जनवरी, 1972 को गठन किया गया था-	मेघालय का	RRB Group-D 22-10-2018 (Shift-I)
■ सिक्किम भारत का एक राज्य बना था-	1975 में	RRB NTPC 03.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था-	वर्ष 1967 में	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-II) Stage II nd
■ वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है-	पुडुचेरी	UPSI Batch-1, 21 Dec 2017
■ वर्ष 1956 में मुख्यतः मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था-	भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता	UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
■ भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है-	भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है	UP PCS (Pre) 2019
■ भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था-	आन्ध्र प्रदेश	UPPCS (Pre) 2018
■ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से सम्पन्न हुआ, वह है-	मध्य प्रदेश	BEO Re-exam-2006-I
■ एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं हैं-	एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2013
■ भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है-	संसद में साधारण बहुमत द्वारा	UPPCS (Pre.) G.S., 2016
■ 'आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक' राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया-	मार्च, 2014 में	UPPCS (Pre) G.S. 2015
■ भारतीय संघ के सह-राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था-	सिक्किम	UPPCS (Pre.) G.S. Spl. 2004
■ जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आगेरी क्रम है-	नागालैण्ड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम	UPPCS (Pre.) G.S. 2010 UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper 2008
■ भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है-	सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड	UPPCS (Main) G.S., I-Paper, 2006
■ भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं-	28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश (जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है)	UPPCS (Pre.) G.S. 2002
■ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है-	करनाल एवं रोहतक	UPPCS (Pre.) G.S., 2011
■ राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है-	संप्रभुता	UPPCS Spl. (Pre.) G.S., 2008
■ भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है-	राष्ट्रपति द्वारा	UPPCS (Pre.) G.S., 1995

■ वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहाँ से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है—	पुडुचेरी	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ आंश्च प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष पारित किया गया था—	2014 में	SSC Selection Posts XI- 28/06/2023 (Shift-III) SSC CHSL 04/08/2021 (Shift-I)
■ 1963 में, एक अलग राज्य बनकर उभरा था—	नागालैण्ड	SSC CHSL 10/08/2021 (Shift-I)
■ नागालैण्ड राज्य दिवस मनाया जाता है—	1 दिसंबर को	SSC Stenographer – 11/11/2021 : Shift-II
■ सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है—	16 मई	SSC Stenographer – 12/11/2021 : Shift-II
■ भारत की केन्द्र सरकार ने वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी—	1953	SSC CHSL 05/08/2021 (Shift-I)
■ भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष थे जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी—	फ्रजल अली	SSC JE Civil – 23/03/2021 (Shift-I)
■ झारखंड को वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था—	2000	SSC CHSL 11/08/2021 (Shift-III)
■ भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य स्थापित हुआ—	1953 में	SSC CHSL 08/06/2022 (Shift-II)
■ मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा _____ के अंतर्गत राज्य बन गए—	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	SSC CGL (Tier-I) – 11/06/2019 (Shift-II)
■ 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए—	मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा	SSC CPO-SI 25/11/2020 (Shift-I)
■ मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वाँ राज्य दिवस मनाया है—	21 जनवरी, 2020	SSC JE Electrical 10.12.2020 (Shift-II)
■ की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था—	सरदार हुक्म सिंह संसदीय समिति	SSC JE Mechanical 28.10.2020 (Shift-II)
■ वह पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना—	दादरा और नगर हवेली	SSC CPO-SI – 11/12/2019 (Shift-I)
■ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिले हैं—	2	SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-II)
■ 2022 तक की स्थिति के अनुसार, भारत में _____ संघ राज्यक्षेत्र हैं—	8	SSC CHSL (Tier-I) – 21/03/2023 (Shift-IV)
■ हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था—	वर्ष 1971	SSC CHSL 11/08/2021 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को _____ के रूप में भी जाना जाता है—	भारत	SSC GD 09/03/2019 (Shift-II)
■ राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम है—		UPPCS (Pre) Exam 2021
सूची-I	सूची-II	
हरियाणा	1 नवंबर, 1966	
गोवा	30 मई, 1987	
झारखण्ड	15 नवंबर, 2000	
तेलंगाना	2 जून, 2014	
■ सही सुमेलन है—		UPPCS RO/ARO (Mains) 2017
सूची-I (राज्य)	सूची-II (अस्तित्व में आने का वर्ष)	
A. नागालैण्ड	1. 1962	
B. झारखण्ड	2. 2000	
C. तेलंगाना	3. 2014	
D. सिक्किम	4. 1975	

संविधान के मूल तत्व (Fundamentals of Constitution)

नागरिकता

■ कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में साल रहा हो, प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है—	12	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-II)
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा—	1 मार्च, 1947	RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-II)

■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 (b)(i) के अनुसार, उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है, जिसने से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्यक्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है-	19 जुलाई, 1948	RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का वह भाग जो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से सम्बन्धित है, जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं-	भाग II	RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D 05-12-2018 (Shift-II)
■ संविधान के प्रारंभ होने के बाद से के तहत नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने सम्बन्धी प्रावधान है-	नागरिकता अधिनियम, 1955	RRB NTPC 11.04.2016 (Shift-III) Stage I st SSC CHSL (Tier-1) – 17/03/2023 (Shift-III) SSC GD 29.11.2021 (Shift -II)
■ भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है-	सम्पत्ति अधिग्रहण	RRB J.E. -2014
■ किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना, भारत के संविधान के के अधीन है-	अनुच्छेद 5 से 7	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017
■ वह कृत्य जो किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है-		UPSI Batch-2, 15 Dec 2017
1. नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शायी हो 2. नागरिक ने, युद्ध के समय गैरकानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो		
■ भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है— जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से		UPSI (Mains), 2014
■ गृह मन्त्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे-	पाकिस्तान	UPP Constable (Main), 2014
■ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाये जाते हैं— ‘निरंतरता एवं परिवर्तन’ के तत्व		UP PSC (Pre) 2020
■ नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है—	संसद	UPPCS (Mains) G.S. II nd 2013
■ भारत में नागरिकता के विषय में सही है—	सम्पूर्ण भारत की एकल नागरिकता	UPPCS (Pre) G.S. 2015 SSC MTS 09/08/2019 (Shift-III)
■ नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहं नहीं हैं—	वे भारतीय जो विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान प्रवासी हो गए	UPPCS (Main) G.S. II nd 2016
■ वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता—	कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना	U.P. Civil Judge (Pre) 2013
■ भारत के संविधान के नागरिकता से संबंधित है—	भाग II	SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित हैं—	अनुच्छेद 5 से 11	SSC CGL (Tier-1) – 14/07/2023 (Shift-I) SSC MTS 06/10/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संसद ने में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित किया—	2019	SSC MTS 11/10/2021 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो—	9	SSC JE Civil 28.10.2020 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ‘नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है—	10	SSC CHSL 10/08/2021 (Shift-I)

मूल अधिकार

■ भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णन किया गया है—	मूल अधिकार का	UPPCS (J) 2023
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अधिकार शामिल है— वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार		UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-I
■ “अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण” के लिए है—	अनुच्छेद 29	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2 RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-I) SSC JE Civil – 23/03/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है—	बंदी प्रत्यक्षीकरण	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022

<p>■ शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि संबंधित है—</p> <p style="text-align: right;">अनुच्छेद 21(अ) से</p>	<p>UPSSSC PET 24/08/2021 Shift-I RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 06/09/2022 (Shift-III) SSC JE Civil – 23/03/2021 (Shift-I)</p>
<p>■ सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है—</p> <p style="text-align: right;">6 से 14 वर्ष</p>	<p>UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-II) UPSI 22.11.2021 Shift-III SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-III) SSC JE Mechanical 22.03.2021 (Shift -II)</p>
<p>■ वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है—</p> <p style="text-align: right;">सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार</p>	<p>विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift- II)</p>
<p>■ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है—</p> <p style="text-align: right;">उच्चतम न्यायालय</p>	<p>UDA/LDA 29-11-2015 UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-1</p>
<p>■ संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है—</p> <p style="text-align: right;">मौलिक अधिकार</p>	<p>राजस्व निरीक्षक - 17-07-2016 (Paper-I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 'विधिक समता' यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है—</p> <p style="text-align: right;">14</p>	<p>Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-I) RRB NTPC 03.02.2021 (Shift-I) Stage Ist UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2015 SSC JE Electrical – 24/03/2021 (Shift-I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है—</p> <p style="text-align: right;">अस्पृश्यता का उन्मूलन से</p>	<p>RRB JE - 01/06/2019 (Shift-II) RRB NTPC 15.03.2021 (Shift-I) Stage Ist SSC CGL (Tier-I)-2019 – 04/03/2020 (Shift-I) SSC CPO-SI 23/11/2020 (Shift-II) SSC GD 03/12/2021 (Shift-II)</p>
<p>■ संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है—</p> <p style="text-align: right;">अनुच्छेद 14-18</p>	<p>RRB JE - 25/05/2019 (Shift-II) UP RO/ARO (Pre) G.S., 2014</p>
<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है—</p> <p style="text-align: right;">अनुच्छेद 17</p>	<p>RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-III) UPSI Batch-1, 16 Dec 2017 UPSI (Ranker), 2011 GIC (Pravakta) 2015</p>
<p>■ भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है—</p> <p style="text-align: right;">अनुच्छेद 15</p>	<p>RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-III) RRB Group- D 18-09-2022 (Shift-III) UPSI (Ranker) -2011 RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift -II) RRB Group-D –05/09/2022 (Shift- II)</p>
<p>■ वह रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसका वह हकदार/अधिकारी नहीं होता है—</p> <p style="text-align: right;">अधिकार पृच्छा</p>	<p>RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है—</p> <p style="text-align: right;">20</p>	<p>RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-I) RRB Group-D–20/09/2022 (Shift-II) SSC CHSL 10/08/2021 (Shift-II)</p>
<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है—</p> <p style="text-align: right;">23 से 24</p>	<p>RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है—</p> <p style="text-align: right;">अनुच्छेद 23 के अंतर्गत</p>	<p>RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-III)</p>

<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खुतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा—</p>	<p>अनुच्छेद 24</p>	<p>RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 14/09/2022 (Shift-II) UPP Constable, 25.10.2018 UPPCS (M) G.S. IInd 2009, 2011, 2012 UPPCS (Pre) G.S. 2004, 2005 U.P.P.C.S. (J) G.K. 2016</p>
<p>■के अनुसार ,“कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना, सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं”—</p>	<p>विधि का शासन</p>	<p>RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है— यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं</p>		<p>RRB Group-D : 13/09/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग है—</p>	<p>निवारक निरोध</p>	<p>RRB Group-D : 30/08/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि ‘किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं’—</p>	<p>अनुच्छेद 21</p>	<p>RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान हैं—</p>	<p>अनुच्छेद 12 से 35</p>	<p>RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 22/08/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 05/12/2018 (Shift-III) RRB NTPC 07.04.2016 (Shift-II) Stage Ist UPSI Batch-1, 14 Dec 2017 SSC JE Mechanical - 27/09/2019 (Shift-II)</p>
<p>■ निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 'जस्टिस के. एस. पुटुस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम 2017 भारत संघ' के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के से संबंधित है—</p>	<p>अनुच्छेद 21</p>	<p>RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-I) UPSI Batch-1, 16 Dec 2017 UPSI 16.11.2021 Shift-III</p>
<p>■ 86 वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(A) जोड़कर अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में, मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था—</p>	<p>शिक्षा का अधिकार</p>	<p>RRB Group-D – 20/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 24/08/2022 (Shift-I) UPPCS (Pre) Exam 2022</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 मेंमौलिक अधिकार का उल्लेख है—</p>	<p>संवैधानिक उपचार का अधिकार</p>	<p>RRB Group-D – 13/09/2022 (Shift-II) SSC MTS 05/10/2021 (Shift-II)</p>
<p>■ भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है—</p>	<p>संपत्ति अर्जित करने का अधिकार</p>	<p>RRB Group- D – 14/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D 22-10-2018 (Shift-III) UPP Constable (Pre), 2013 UPPSC AE- 2007 Paper (I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित 'लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता' संविधान के अनुच्छेद में दी गई है—</p>	<p>अनुच्छेद 16</p>	<p>RRB Group- D – 28/09/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है—</p>	<p>भारत के राज्यक्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना</p>	<p>RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है—</p>	<p>लोक नियोजन में अवसर की समता</p>	<p>RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है—</p>	<p>समानता का अधिकार</p>	<p>RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-I)</p>

<p>■ मूल अधिकारों के हनन (violations) के मामले में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है-</p> <p style="text-align: right;">अनुच्छेद 32</p>	<p>RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-II) SSC CHSL 12/04/2021 (Shift-II) SSC GD 08/12/2021 (Shift-I) SSC CHSL (Tier-1) – 11/08/2023 (Shift-III)</p>
<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से सम्बन्धित है-</p> <p style="text-align: right;">अनुच्छेद 23</p>	<p>RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बना गया— वर्ष 2009 में</p>	<p>RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-II) RRB Group-D 10-10-2018 (Shift-II) RRB NTPC Stage Ist 19.01.2017 (Shift-III) RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुसार, ‘प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण’ मूल अधिकार का हिस्सा है— स्वतंत्रता का अधिकार</p>	<p>RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21-क जोड़ा गया था, जो छह से चौदह वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से सम्बन्धित है— वर्ष 2002 में</p>	<p>RRB Group-D – 27/09/2022 (Shift-III) UPSI 12.11.2021 Shift-II SSC MTS/Havaladar– 06/07/2022 (Shift-II) SSC CPO -SI 23.11.2020 (Shift -I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है— समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार</p>	<p>RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ भारतीय संविधान में ‘मौलिक अधिकार’ के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है— संभाषण का अधिकार</p>	<p>RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है— मौलिक अधिकार को</p>	<p>RRB NTPC 01.04.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगू माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जायेगा— सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार</p>	<p>RRB NTPC 22.01.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ भारत के संविधान के भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं— भाग 3</p>	<p>RRB NTPC 30.12.2020 (Shift-II) Stage Ist SSC CHSL 15/04/2021 (Shift-III)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है, की गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा— 24</p>	<p>RRB NTPC 22.02.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI Pre-2011</p>
<p>■ भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है— भाग III</p>	<p>RRB Group-D 06-12-2018 (Shift-II)</p>
<p>■ भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है— गोपनीयता का अधिकार</p>	<p>RRB Group-D 25-09-2018 (Shift-II) RRB Group-D 31-10-2018 (Shift-I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है— भाग III</p>	<p>RRB Group-D 26-10-2018 (Shift-III)</p>
<p>■ भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है— देश की रक्षा का अधिकार</p>	<p>RRB NTPC 09.04.2016 (Shift-III) Stage Ist</p>
<p>■ भारतीय संविधान मौलिक अधिकार की गारंटी देता है— व्यवसाय का अधिकार</p>	<p>RRB NTPC 22.01.2021 (Shift-I) Stage Ist</p>
<p>■ भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट ‘हैबियस-कॉर्पस’ का शाब्दिक अर्थ है— आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा</p>	<p>RRB NTPC 23.02.2021 (Shift-I) Stage Ist</p>

■ परमादेश रिट होती है—	किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना	RRB NTPC 11.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वह रिट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है—	बंदी प्रत्यक्षीकरण	RRB NTPC 20.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार है—	धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-26)	RRB NTPC Stage I st 30.04.2016 (Shift-II)
■ के मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा—	लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य	UPSI (Mains), 2014
■ आत्म रक्षा का अधिकार है—	1. अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा 2. दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा 3. चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा	UPSI (Mains), 2014
■ भारतीय संविधान का वह भाग जिसको भारत का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है—	भाग III	UPSI 21.11.2021 Shift-II
■ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है—	मौलिक लेकिन अनन्य नहीं	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान के अनुसार, कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु होनी चाहिए—	14 वर्ष	UPSI 13.11.2021 Shift-II RRB JE 2014 UPSI, 1999
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 'बेगार' (बंधुआ मजदूरी) पर रोक लगाता है—	अनुच्छेद 23	UPSI 13.11.2021 Shift-II
■ जब कारावास की अवधि तीन महीने से कम हो, तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति मेंसे अधिक नहीं होगा—	एक समय पर चौदह दिन	UPSI 22.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान के "अनुच्छेद 19" में प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है—	छः	UPSI 21.11.2021 Shift-I SSC CHSL 21/10/2020 (Shift-I)
■ 'हैबियस कॉर्पस' याचिका का शाब्दिक अर्थ है—	किसी को सशरीर पेश करना	UPSI 20.11.2021 Shift-I
■ मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है—	प्राकृतिक अधिकार के रूप में	UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ वह मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है—	सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता	UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा अधिकार की गारंटी दी जाती है—	धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख-रखाव करने का अधिकार	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो—	स्वतंत्रता	UPSI Batch-1, 13 Dec 2017
■ स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है—	1. कोई भी पेशा अपनाना 2. भाषण की स्वतंत्रता	UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
■ भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन हैं—	1. राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है 2. आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017

■ संविधान का वह अनुच्छेद जिसका अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा— अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता	UPSI Batch-3, 12 Dec 2017
■ नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है— राज्य, शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में, किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017
■ वह मौलिक अधिकार जिसका लक्ष्य है, सामाजिक विभेद-का उन्मूलन करना— समानता का अधिकार	UPSI Batch-3, 14 Dec 2017
■ उपाधियों का अन्त संविधान में के अन्तर्गत प्रतिष्ठापित है— समानता का अधिकार	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ ‘मौलिक अधिकार’ से ‘कानूनी अधिकार’ में परिवर्तित किया गया है— संघति के अधिकार को	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ वह अनुच्छेद जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है— अनुच्छेद 33	UPSI Batch-3, 22 Dec 2017
■ भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही कथन है— 1. यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है 2. यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है	UPSI Batch-3, 20 Dec 2017
■ जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, वे— अमान्य और रद्द माने जाएंगे	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग हैं— स्वतंत्रता के	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सन्दर्भ में, सही कथन है— 1. अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सज़ा मिल सकती है 2. भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते	UPSI Batch-3, 16 Dec 2017
■ संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत, मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके, कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्रे पर (जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से) न्यायालय जा सकता है— अनुच्छेद 32	UPSI Batch-2, 15 Dec 2017 UPSI (Mains), 2014
■ भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित सही कथन है— किसी भी व्यक्ति को, एक ही अपाधि के लिए, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता	UPSI Batch-2, 22 Dec 2017
■ वह अनुच्छेद जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है— अनुच्छेद 19(a)	UPP Constable, 26.10.218 (Shift-1)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है— दोष-सिद्धि के सन्दर्भ में संरक्षण से	UPP Constable, 26.10.218 (Shift-2)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत, राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है— 6	UPP Constable, 26.10.218 (Shift-2)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 संबंधित है— कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से	UPP Constable, 26.10.218 (Shift-2)

■ वह मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक अधिकार का सहागा लेकर अदालत में जा सकता है-	संवैधानिक उपचार का अधिकार	UPP Constable (Main), 2014
■ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है-	अधिनियम 25–28 में	UPP Constable (Main), 2014 SSC CGL (Tier-I)-2019 – 07/03/2020 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है-	अनुच्छेद 21	UPP Constable (Main), 2014
■ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं-	1. प्रशासनिक कार्यवाहियों में 2. अर्धन्यायिक कार्यवाहियों में 3. न्यायिक कार्यवाहियों में	UPSI (Mains), 2014
■ एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि— सभा शांतिपूर्ण है		UPSI (Mains), 2014
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है-	धर्म की स्वतंत्रता से	UPSI (Mains), 2014
■ संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है—	विधि के समक्ष समता का अधिकार	UPSI (Ranker), 2011 UPSI (Mains), 2014
■ भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है—	अनुच्छेद 34 में	UPSI (Ranker), 2011
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है—	अनुच्छेद 30	UPSI (Ranker), 2011
■ वह अधिकार जिसको डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया— संवैधानिक उपचारों का सिद्धान्त		UPSI, 1999 SSC CHSL 31/05/2022 (Shift-II)
■ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समुचित पर्यावरण” के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल माना गया—	प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता	UPSI (Mains), 2014
■ मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 संबंधित है— कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से		UPP Constable, 19.06.2018 (Shift-2)
■ यू.एस.ए. के संविधान में पहले दस संशोधनों के लिए सामूहिक नाम है—	बिल ऑफ राइट्स	UPSI 14.11.2021 Shift-II
■ अनुच्छेद 31-A, 31-B और 31-C की संवैधानिकताके मामले में चुनौती का विषय थी—	वर्मन राव बनाम भारत संघ	UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को ‘हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता’ कहा था—	डॉ. एस. राधाकृष्णन	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है—	संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (g)	UPPSC GDC 2021
■ संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) के अन्तर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है—	मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का	UPPSC GDC 2021
■ संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है—	पूजा की समानता	BEO exam-2006 (I)
■ मूल अधिकार नहीं है—	समान कार्य के लिए समान वेतन	GIC (Pravakta) 2015 UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2014
■ बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रभाव में आया—	1 अप्रैल, 2010 को	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है—	आर्थिक समानता	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper 2008
■ भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है— धर्म, (मूलवंश) जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार		U.P. P.C.S. (Pre) 2001 U.P.Lower (Pre) 2002
■ आपातकालीन स्थिति में निलम्बित किये जा सकते हैं—	मौलिक अधिकार	UP Lower (Pre) G.S., 2002

■ ग्रहण के सिद्धांत (डॉक्टरन ऑफ इंजिनियरिंग) के सम्बन्ध में है-	अनुच्छेद 13	(U.P.H.J.S. (Pre) 2009)
■ मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है-	अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत	(U.P.P.C.S. (Spl.) 2004) SSC MTS – 19/05/2023 (Shift-III) SSC CHSL (Tier-1) – 07/08/2023 (Shift-II)
■ भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त छः मूल अधिकारों में से नहीं हैं-	विरोध का अधिकार	UPPCS (Main) G.S. II nd 2015
■ विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं हैं-	अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार	UPPCS (Pre.) G.S., 2007
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवाद' शब्द को इस अनुच्छेद/अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई-	अनुच्छेद 14 तथा 16	UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2001
■ द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है-	समता का अधिकार	UPUDA/LDA Special (Pre) G.S., 2010
■ संविधान में प्रत्याभूत है-	सामाजिक समानता	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2008
■ शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है-	संविधान के अनुच्छेद 15 (4) से	(U.P.P.C.S. (Pre) G.S. 2003) (U.P. Lower (Spl) 2002) (U.P.P.C.S. (Spl) 2004), (U.P.P.C.S. (J) (Pre) 2012)
■ एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है-	अनुच्छेद 16 (1) और 16 (2)	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2009
■ भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता का अधिकार' चार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं-	अनुच्छेद-19 से अनुच्छेद-22 तक	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper, 2016
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है-	मृत्यु का अधिकार	(U.P. Civil Judge (Pre) 2013)
■ अनुच्छेद 19(1)d को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है-	विदेश यात्रा का अधिकार	(UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2001)
■ जिस वाद में यह अभिनिधारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अपडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(I) (g) का उल्लंघनकारी नहीं है-	ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	(U.P.P.C.S. 2008)
■ हमारे संविधान में एक अभियुक्त की दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है-	अनुच्छेद 22(1) के द्वारा	U.P.P.C.S. (J) (Pre) 2015
■ सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को "एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबन्ध" कहा था-	ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद में	U.P. Civil Judge (Pre) 2013
■ श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है-	अनुच्छेद 23	U.P.P.C.S. 2000
■ वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है-	अनुच्छेद 23	BEO Re-exam-2006-I
■ संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है-	अनुच्छेद 24	BEO Re-exam-2006-I
■ छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों (शिशुओं) को शिक्षा का अधिकार है-	मूल अधिकार	UPPCS (Pre.) G.S., 2006
■ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार के निहित जो-	प्राथमिक स्तर तक के हैं	UPPCS (Pre) G.S., 2015
■ धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज-सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है-	धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में	UPPCS (Pre.) G.S., 2003
■ मौलिक अधिकारों का संरक्षक है-	सर्वोच्च न्यायालय	UPPCS (Pre.) G.S. 1992 U.P. Lower (Pre.) 2004-05
■ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं-	मूल अधिकारों का प्रवर्तन	UP Lower (Pre) G.S., 2003-04
■ प्रिवेन्टिव डेटेन्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बन्दी बनाकर रखा जा सकता है-	तीन माह	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2009
■ वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अन्तर्गत सम्पत्ति का अधिकार है एक-	वैधानिक अधिकार	UPPCS (Pre.) G.S. 2007 U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013 U.P.P.C.S. (Pre) G.S. 1992, 1994, 2000

■ भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है-	संसद्	UPPCS (Pre.) G.S. 2016
■ उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि “मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिन्दगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं”-		UPPCS (Pre.) 2012
गोलक नाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में		
■ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार ‘राज्य’ की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है-	भारतीय जीवन बीमा निगम	(U.P.P.C.S. (Pre) G.S. 2000)
■ संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य है-	दिल्ली स्टॉक एक्सचेन्ज	(UP Lower (P) 2004)
■ मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द “राज्य” में सम्मिलित नहीं है-	इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज (संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान)	(U.P.P.C.S. (Pre) G.S. 1995, 2007)
■ ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के दो से अधिक सन्तानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निरहित होगा- एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया-	जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में	(UPPCS (J) 2003)
■ उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये विशेष प्रावधान जोड़े गये-	मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराइराजन	(U.P. Civil Judge 2006)
■ “क्रीमी लेयर” का सिद्धान्त जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था-	इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में	(U.P. Civil Judge 2006)
■ अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है-	भारत में प्रेस की स्वतंत्रता	(U.P.H.J.S. (Pre) 2012)
■ यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड्डताल पर जाने का अधिकार नहीं है, दिया गया-	टी. के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में	(U.P.P.C.S. (J) 2003)
■ “प्राग-दोषमुक्ति” सिद्धांत सम्बन्धित है-	दोहरे परिसंकट से	(U.P. Civil Judge 2006)
■ सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की व्याख्या “ऋजु, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया” के रूप में की है-	मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में	(U.P.P.C.S. 2000) (U.P.H.J.S. (Pre) 2009)
■ भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है-	अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत	UPSC (Main) Spl. G.S. II nd Paper 2008
■ वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है-	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्धारण का अधिकार है-	संसद को	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत प्रकार की रिट जारी की जा सकती है-	पाँच	SSC CGL (Tier-II) – 06/03/2023 SSC CHSL 10.06.2022 (Shift -III)
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से अधिकारों की गारंटी दी थी- सात		SSC JE CIVIL 09/10/2023 (Shift-I)
■ भारत के संविधान का उच्च न्यायालय को रिट (writ) जारी करने का अधिकार देता है-	अनुच्छेद 226	SSC CGL (Tier-II) – 03/03/2023
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकारसे संबंधित है-	शोषण के विरुद्ध अधिकार	SSC CHSL (Tier -I) 17.08.2023 (Shift-IV) SSC CGL (Tier - I) 18.04.2022 (Shift -III) SSC MTS/Havaladar- 11/07/2022 (Shift-III) SSC MTS- 19/05/2023 (Shift-III) SSC CHSL (Tier-1) – 02/08/2023 (Shift-I) SSC GD 18/02/2019 (Shift-I) SSC CGL (Tier-1) – 26/07/2023 (Shift-II) SSC JE Electrical 10.12.2020 (Shift-II)

■ भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से बलात श्रम के निषेध पर जोर देता है— शोषण के विरुद्ध अधिकार	SSC GD 23/11/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 संबंधित है— धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता	SSC CHSL (Tier-1) – 15/03/2023 (Shift-III) SSC MTS 06/10/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के समूह शामिल हैं— 6	SSC CGL (Tier-1) – 26/07/2023 (Shift-I)
■ भारत के संविधान का कहता है कि राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी— अनुच्छेद 28	SSC Selection Posts XI– 27/06/2023 (Shift-II)
■ 28 जून 2021 को, उच्चतम न्यायालय ने मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है— केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ	SSC CGL (Tier-1) – 17/07/2023 (Shift-III)
■ जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई : न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित ‘राज्य’ शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं— अनुच्छेद 12	SSC CHSL (Tier-1) – 08/08/2023 (Shift-IV)
■ भारतीय संविधान का स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है— अनुच्छेद 19	SSC CHSL (Tier-1) – 08/08/2023 (Shift-IV)
■ संपूर्ण भारत के भू-भाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है— 19	SSC CGL (Tier-I) – 06/06/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है— धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	SSC CGL (Tier-1) – 21/07/2023 (Shift-II) SSC MTS 08.08.2019 (Shift -II)
■ भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है— राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना	SSC CHSL (Tier-1) – 14/08/2023 (Shift-II)
■ सरकार भारतीय संविधान के के तहत, श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है— अनुच्छेद 21	SSC CHSL (Tier-1) – 11/08/2023 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद ‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार (Right to Constitutional Remedies)’ से संबंधित है— 32–35	SSC MTS– 10/05/2023 (Shift-I) SSC CHSL 06.06.2022 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि ‘किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगा’— 20	SSC MTS/Havaladar– 08/07/2022 (Shift-II)
■ जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के के तहत इंटरनेट तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है— अनुच्छेद 19	SSC JE Civil 28.10.2020 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 06/03/2020 (Shift-I)
■ अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है— 21	SSC MTS 13/08/2019 (Shift-I) SSC GD 23/11/2021 (Shift-II) SSC MTS 09/08/2019 (Shift-III)
■ संविधान का यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा— अनुच्छेद 21	SSC Stenographer – 12/11/2021 : Shift-I
■ भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात में की गई है— अनुच्छेद 15	SSC CHSL 09/08/2021 (Shift-II) SSC CHSL 21.10.2020 (Shift-III) SSC MTS 02/08/2019 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 04/03/2020 (Shift-I) SSC CHSL 24/05/2022 (Shift-III)
■ ‘सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा’। भारतीय संविधान का अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है— 30	SSC CHSL 10/06/2022 (Shift-I) SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-I)
■ किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है— अनुच्छेद 22	SSC JE Civil 11.12.2020 (Shift-II) UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2013 SSC CHSL 02/06/2022 (Shift-III)
■ भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के तहत सुनिश्चित की गई है— अनुच्छेद 19	SSC JE Civil - 27/01/2018 (Shift-II)

■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद , किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है—	16	SSC JE Electrical 29.10.2020 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद , यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान, 1950 के लागू होने से पहले के भाग III से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे—	13	SSC MTS 08/10/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का राज्य को 'उपाधियाँ (Titles)' प्रदान करने से रोकता है— अनुच्छेद 18	SSC Stenographer – 15/11/2021 : Shift-I SSC JE Mechanical – 23/03/2021 (Shift-II)	
■ भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है—	14 से 18	SSC CGL (Tier-I) 20/04/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं, जो के संविधान में निहित है— संयुक्त राज्य अमेरिका		SSC CHSL 15/04/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किये गए हैं— क्रमशः छ: और ग्यारह		SSC GD 15/12/2021 (Shift-I)
■ भारत में संघ बनाना एक है—	मौलिक अधिकार	SSC MTS 13/08/2019 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं—	मूल अधिकार	SSC JE Civil - 27/01/2018 (Shift-I) SSC MTS 09/08/2019 (Shift-III) SSC CHSL (Tier-I) – 02/08/2023 (Shift-III)
■ मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था—	1978	SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-II)
■ ने उस नौ-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया, जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था— जे.एम. खेहर		SSC CHSL 15/10/2020 (Shift-II)
■ भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, क्योंकि नागरिकों के पास का मौलिक अधिकार है— अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता		SSC CHSL 19/10/2020 (Shift-I) RRB NTPC Stage I st 22.04.2016 (Shift-III)
■ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर-कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है— बन्दी प्रत्यक्षीकरण		SSC MTS 02/08/2019 (Shift-III) SSC JE Electrical -26/09/2019 (Shift-II) SSC CHSL 11/08/2021 (Shift-II)
■ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट (wirts) जारी की जा सकती हैं—	पांच	SSC CHSL 26/05/2022 (Shift-III)
■ भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार, फोन कॉल का दोहन (टैपिंग) संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किये गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है— 21		SSC CPO-SI – 11/12/2019 (Shift-I)
■ परमादेश रिट का अर्थ है—	हम आदेश देते हैं	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 09/03/2020 (Shift-I)
■ बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष में लागू किया गया है— 2009		SSC CGL (Tier-I) 18/04/2022 (Shift-II) SSC MTS 19/08/2019 (Shift-I)
■ सही सुमेलन है— सूची-I (मौलिक अधिकार)	सूची-II (भारतीय संविधान के अनुच्छेद)	BEO Exam 2003
A. समता का अधिकार B. वाक स्वातंत्र्य अधिकार C. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार D. सांविधानिक उपचारों का अधिकार	1. अनुच्छेद 14, 18 2. अनुच्छेद 19 (1) क 3. अनुच्छेद 25 4. अनुच्छेद 32	
■ सही सुमेलन है— सूची-I A. बन्दी प्रत्यक्षीकरण B. परमादेश C. प्रतिषेध D. अधिकार पृच्छा	सूची-II 1. दू हैव दि बॉडी ऑफ 2. वी कमाण्ड 3. रिट ऑफ प्रोहिविशन 4. बाई व्हाट अथॉरिटी	UP PCS (Pre) 2019

राज्य के नीति निदेशक तत्व

■ वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए-	राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-II
■ 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में नया DPSP (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त) जोड़ा गया-	समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2
■ भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है-	राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त	UPSSSC PET 24/08/2021 Sift-II
■ महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है-	महिलाओं को शिक्षित करना	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
■ अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान, भारतीय संविधान केके एक भाग के रूप में उल्लिखित है-	राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त	Lower Exam - 01-10-2019 (Shift-I) RRB NTPC 06.04.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत का एकमात्र राज्य जहाँ समान सिविल कोड का प्रावधान है-	गोवा	लोअर द्वितीय- 06-03-2016
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है-	अनुच्छेद 40	UPSSSC PET 24/08/2021 Sift-II UPSI Batch-1, 12 Dec 2017 SSC CGL (Tier-1) – 25/07/2023 (Shift-IV) SSC CHSL (Tier-1) – 02/08/2023 (Shift-I)
■ भारत में पंचायती राज व्यवस्थाके अंतर्गत रखी गई है-	राज्य के नीति निदेशक तत्व	UPSSSC PET 24/08/2021 Sift-I
■ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन आता है-	राज्य के नीति निदेशक तत्व के अन्तर्गत	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को शामिल किया गया है-	राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में	RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-I)
■ राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 51 संबंधित है-	अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से	RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है-	अनुच्छेद 49	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-I) UPSI Batch-3, 16 Dec 2017 UPSI Batch-1, 21 Dec 2017
■ राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में निहित प्रावधानों को-	किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है	RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है-	अनुच्छेद 44	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 06/10/2022 (Shift-II) RRB NTPC 11.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग में किया गया है-	भाग 4	RRB NTPC 01.02.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB Group-D 03-10-2018 (Shift-II)
■ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का वह भाग जिसको संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है-	राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त	RRB Group-D 01-11-2018 (Shift-II) UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ भारत सरकार द्वारा अधिगृहित वह नीति जो 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' द्वारा निर्देशित नहीं है-	भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी	RRB NTPC 27.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है-	भाग IV	RRB Group-D 26-10-2018 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है-	राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त	RRB JE - 26/06/2019 (Shift-I)
■ 'क्रीमी लेयर' सम्बन्धित है-	सामाजिक एवं आर्थिक हालात से	कमिष्ट सहायक - 31-05-2015

■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को “गायों के वध पर रोक लगाने” का निर्देश देता है— अनुच्छेद 48	UPSI 21.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-48A के अनुसार, “राज्य.....के लिए प्रयास करेगा”— 1. पर्यावरण की रक्षा 2. पर्यावरण में सुधार 3. देश के बन्यों और बन्यजीवों के संरक्षण	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को “ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए” निर्देशित करता है— अनुच्छेद 43	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को ‘पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन’ के लिए निर्देशित करता है— अनुच्छेद 48 A	UPSI 13.11.2021 Shift-I
■ एक ऐसी विशेषता जो ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ और ‘मौलिक कर्तव्य’ दोनों में समान है— दोनों ही गैर-न्यायसंगत गैर वाद योग्य हैं	UPSI 20.11.2021 Shift-I
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (अर्लीं चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) सभी बच्चों को तब तक दी जानी है, जब तक कि वे.....वर्ष की आयु पूरी न हो— छह	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से संबंधित है— समान नागरिक संहिता से	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से वह अनुच्छेद जो प्रबन्धन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है— अनुच्छेद 43A	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गयी है— अनुच्छेद 47	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017
■ निदेशक सिद्धान्तों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे पारित किया जाना आवश्यक होता है— 1. संसद के दोनों सदन द्वारा 2. संसद में उपस्थित दो—तिहाई सदस्यों का अनुमोदन और मतदान द्वारा	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017
■ भारत के मूल संविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त के रूप में उल्लेख नहीं किया गया— पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य के कर्तव्य का	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था— शिक्षा का अधिकार	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में उल्लेखित है— 1. काम पाने का अधिकार 2. कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ “यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धान्तों के लिए केवल आडम्बर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है।” राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द कहे गए हैं— डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन हैं— 1. ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं 2. इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है “राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और बन तथा बन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा”—अनुच्छेद 48-A	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को वर्गीकृत किया जाता है— अन्य देशों के साथ संबंध	UPSI Batch-3, 22 Dec 2017
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48, भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह— गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए	UPSI Batch-2, 22 Dec 2017

■ भारत में राज्य के नीति के निदेशक सिद्धान्तों के संदर्भ में सही कथन है— सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए, ये राज्य को संबोधित किये गये कुछ निर्देश हैं	UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
■ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निदेशक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। राज्य को प्रयास करना होगा— 1. अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि—बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का 2. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त, संविधान के अध्याय IV के में निहित हैं— अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51	UPSI Batch-3, 12 Dec 2017
■ भारतीय संविधान के भाग IV में विवरण प्रस्तुत है— राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का	UPP Constable, 19.06.2018 (Shift-1)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त “न्याय” को सूचित करने के लिए प्रयुक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय हुआ है—	UPSI (Ranker), 2011
■ “राज्य के नीति निदेशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है”, यह कथन है— के.सी. व्हीयर का	UPPCS (J) 2023
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ‘समान नागरिक संहिता’ से संबंधित है— अनुच्छेद- 44	UPPCS (J) 2023 SSC CGL (Tier-II) – 07/03/2023 SSC MTS/Havaladar-01/09/2023 (Shift-I) SSC MTS – 15/05/2023 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I) – 04/06/2019 (Shift-II) SSC MTS 22/10/2021 (Shift-III) SSC MTS 09/08/2019 (Shift-III) SSC MTS 14/10/2021 (Shift-I) SSC GD 15/12/2021 (Shift-III)
■ भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है— भाग-IV	UPPSC Unani Medical Officer 2018
■ राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें— अनुच्छेद- 43A	UPPSC GIC 2021
■ कौन-सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है - पर्यावरण का संरक्षण	UPPCS (Pre) 2023 UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2009
■ राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं— समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी में	UPPCS (Pre) 2018
■ भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है— राज्य के नीति निदेशक तत्वों में	GIC (Pravakta) 2015
■ भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धान्तों को जो अनुच्छेद 39 (b) और (c) में वर्णित है, प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है— 42वाँ संशोधन	UPPCS (Main) G.S. II nd 2009
■ राज्य का नीति-निदेशक सिद्धान्त, संविधान के बाद में जोड़ा गया— मुफ्त कानूनी सलाह	UP RO/ARO (Pre) G.S. 2014
■ भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है— संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में	UPPCS (Pre) G.S. 1997 U.P. Lower (Pre) 2004-05 UP Lower (M) G.S. 2013 SSC CGL (Tier-II) – 02/03/2023 SSC CGL (Tier-I) 19.07.2022
■ अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है— कल्याणकारी राज्य का	UP Lower (Pre) G.S. 2003-04
■ राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है— राज्य का	(U.P.A.P.O. 1995)
■ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का उद्देश्य नहीं है—एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना	UP RO/ARO (Pre) G.S. 2013
■ समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक— राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों का अंग है	UPPCS (Pre) G.S., 1998 UP Lower (Pre) G.S., 2003-04 UPUDA/LDA (Main) G.S., 2010 UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2012

■ एक नीति निदेशक तत्व है-	समान आचार संहिता	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2010
■ राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में सम्मिलित है-	मद्य निषेध	UPPCS (Main) G.S. 2002
■ नीति निदेशक सिद्धान्तों (Directive Principles) में सम्मिलित नहीं है—सूचना का अधिकार		UPPCS (Pre) G.S. 2006 UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2010
■ राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में संविधान शान्त है-	प्रौढ़ शिक्षा के बारे में	U.P. Lower (Pre) G.S. 2008
■ राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में नहीं है-	अस्पृश्यता उन्मूलन	UP Lower (Pre) G.S. SPL 2008 UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ राज्य का नीति- निदेशक तत्व नहीं है— चौदह (14) वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा		UPUDA/LDA (Pre) G.S. 2010
■ राज्य का नीति- निदेशक तत्व नहीं है— नागरिकों व गैर-नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता		(U.P. Civil Judge (Pre) 2013)
■ मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन-	गलत है	(UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2009)
■ नीति-निदेशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपर्युक्त कथन कहा गया है-	के.टी. शाह द्वारा	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2007
■ “राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा हैं, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया था—	ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा	(U.P.P.C.S. (Pre) G.S. 2006)
■ मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था— अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु		(UPUDA/LDA (Pre) G.S. 2010)
■ संविधान के अन्तर्गत “काम का अधिकार” पाया जा सकता है— राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में		(U.P.P.C.S. (J) (Pre) 2015) (U.P.P.C.S. (Pre) G.S. 1993, 2007)
■ राज्य के नीति-निदेशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है—	लोक मत का	(U.P. Civil Judge (Pre) 2014)
■ संविधान में राज्य के नीति के निदेशक सिद्धान्तों में कुछ नहीं कहा गया है—	वयस्क शिक्षा के बारे में	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ भारतीय संविधान का स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है—	अनुच्छेद 49	SSC CHSL (Tier-1) – 09/08/2023 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B..... का प्रावधान करता है— सहकारी समितियों को बढ़ावा देने		SSC MTS— 04/05/2023 (Shift-II)
■ 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था—	एक	SSC Selection Posts XI– 27/06/2023 (Shift-III)
■ कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके उत्पाइन की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है, यह के अंतर्गत आता है—	अनुच्छेद 42	SSC CHSL (Tier-1) – 09/08/2023 (Shift-I) SSC CHSL (Tier-1) – 02/08/2023 (Shift-III)
■ ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों में चार नए विषयों (अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A) को जोड़ा— 42वां संशोधन अधिनियम, 1976		SSC CGL (Tier-1) – 20/07/2023 (Shift-IV) SSC Selection Posts XI– 28/06/2023 (Shift-II)
■ सरकारी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों के के अंतर्गत आते हैं—	अनुच्छेद 48	SSC CHSL (Tier-1) – 07/08/2023 (Shift-II)
■ भारत के संविधान का ‘अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा’ पर राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है—	अनुच्छेद 51	SSC CHSL 20/10/2020 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है—	39A	SSC CGL (Tier-I) – 06/06/2019 (Shift-II)
■ कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है—	अनुच्छेद 48	SSC CHSL 05/08/2021 (Shift-II)
■ अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है—	अनुच्छेद 38	SSC MTS 20/10/2021 (Shift-I)
■ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध है—	अनुच्छेद 45 में	SSC GD 29/11/2021 (Shift-I)

■ नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए को निर्देश देता है— अनुच्छेद 39	SSC MTS 22/10/2021 (Shift-I)
■ राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है— अनुच्छेद 50	SSC Stenographer – 15/11/2021 : Shift-II
■ भारत के संविधान का भाग-IV स्पष्ट रूप से राज्य से के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है— नौकरीपेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश	SSC CPO-SI – 11/12/2019 (Shift-I)
■ “राज्य हर जगह है: यह शायद ही कोई अन्तराल छोड़ता है”, यह कथन धारणा की व्याख्या करता है— कल्याणकारी राज्य	SSC JE Civil - 27/01/2018 (Shift-II)
■ सही सुमेलन है— सूची-I (राज्य के नीति निदेशक तत्व) राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए 38 सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39 सहकारी समितियों का संवर्धन 43B अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि 51	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II

मूल कर्तव्य

■ मौलिक कर्तव्य हैं— 1. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना 3. भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2
■ मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है— भाग –IV के में	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-II RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-I) RRB Group - D : 29/09/2022 (Shift-I) UPPSC AE-2013
■ 42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किये गए थे— 10	UPSSSC Computer Oprator 10/01/2020
■ मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया— स्वर्ण सिंह समिति ने	राजस्व लेखपाल - 13-09-2015 (Morning) ग्राम विकास अधिकारी - 05-06-2016 RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 22/08/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-II) UPPSC GIC 2021 UPSI 12.11.2021 Shift-III UPPSC AE-2013 SSC CGL Mains -26/10/2023 (Shift-I) SSC CGL (Tier-1) – 19/07/2023 (Shift-IV) SSC CHSL (Tier-1) – 04/08/2023 (Shift-I) SSC MTS 02/08/2019 (Shift-I)
■ मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था— 42वाँ संशोधन अधिनियम द्वारा	Cane Supervisor (31-08-2019) RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-III) RRB Group-D 29/08/2022 (Shift-I) RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-I)

<p>■ 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा, भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत, अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था— यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित, चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे</p>	RRB Group-D – 17/09/2022 (Shift-III)
<p>■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अन्तर्गत आता है—</p>	मौलिक कर्तव्य RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-I) RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-I) RRB J.E. -2014 RRB Group-D 06-12-2018 (Shift-III) UPSI 15.11.2021 Shift-III SSC MTS- 12/05/2023 (Shift-III) SSC CHSL (Tier-1) – 04/08/2023 (Shift-III) SSC MTS/Havaladar– 05/07/2022 (Shift-I) SSC GD – 13/02/2023 (Shift-I) SSC Selection Posts XI– 27/06/2023 (Shift-I) SSC MTS/Havaladar–08/09/2023 (Shift-II) SSC MTS 07/08/2019 (Shift-I) SSC MTS 02.11.2021 (Shift -I) SSC CHSL 10.08.2021 (Shift-II) SSC GD 10.12.2021 (Shift -III)
<p>■ 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया—</p>	11 वां मौलिक कर्तव्य RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-I)
<p>■ भारतीय संविधान के अन्तर्गत, एक मौलिक कर्तव्य नहीं है— लोक चुनावों में वोट डालना</p>	लोअर प्रथम- 28-02-2016
<p>■ 0-6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा—</p>	मौलिक कर्तव्य है RRB Group-D – 06/10/2022 (Shift-I)
<p>■ भारतीय संविधान में मौलिक (मूल) कर्तव्यों की सूची में, 11 वें मौलिक (मूल) कर्तव्य को शामिल किया गया था—</p>	वर्ष 2002 में RRB Group-D – 11/10/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 24/08/2022 (Shift-II)
<p>■ भारतीय संविधान के भाग IV A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है—</p>	11 RRB Group-D – 30/08/2022 (Shift-III) RRB NTPC 27.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB Group-D 22-10-2018 (Shift-I) RRB Group-D 07-12-2018 (Shift-I) Lower Exam -30-09-2019 कनिष्ठ सहायक 31/05/2015 UPSI (Mains), 2014 UPPSC Unani Medical Officer 2018 UPSI 20.11.2021 Shift-III
<p>■ भारतीय संविधान का पालन करना, तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है—</p>	पहला RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)
<p>■ वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से के तहत संविधान के भाग-IV में दस मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है—</p>	अनुच्छेद 51A RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-III)
<p>■ भारतीय संविधान के भाग में केवल एक अनुच्छेद 51-A है, जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है—</p>	भाग IV-A RRB Group-D – 17/08/2022 (Shift-II)
<p>■ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था—</p>	तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने RRB Group-D – 06/10/2022 (Shift-III) SSC GD – 08/02/2023 (Shift-IV)

■ भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड 'K' को शामिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि "जो माता-पिता या संरक्षक हैं, उन्हें छह से चौदह वर्ष के अपने बच्चों को, जैसा भी मामला हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे-	RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-III) अनुच्छेद 51 A
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A (d) के अनुसार- देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए	RRB Group-D – 08/09/2022 (Shift-I)
■ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है— मौलिक कर्तव्य	RRB NTPC 23.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है— मानवों के अवैध क्रय-विक्रय और बलात् श्रम का निषेध	RRB NTPC 26.07.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है— अनुच्छेद 51A	RRB NTPC 28.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वर्णों, झीलों, नदियों और वन्य-जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना, है एक— मौलिक कर्तव्य	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं— केवल नागरिकों पर	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान के भाग IV-A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है— सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य	UPSI 22.11.2021 Shift-III
■ "भारत के मूल संविधान" का हिस्सा नहीं था— मौलिक कर्तव्य	UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ भारत के संविधान में उल्लेख किए गये हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है— हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य	UPSI Batch-1, 13 Dec 2017
■ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिये गये हैं— पूर्व सोवियत संघ के संविधान से	UPSI (Ranker), 2011
■ भारतीय संविधान के भाग दो में प्रावधान किया गया है— नागरिकता संबंधी	UPPCS (J) 2023
■ भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है— आम चुनावों में मतदान	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ मौलिक कर्तव्य नहीं है— स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना— एक मौलिक कर्तव्य नहीं है	UPPCS (Main) G.S. II nd 2007
■ एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है—अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें	U.P. Lower (Pre) G.S. 2008
■ मौलिक कर्तव्यों से सम्बन्धित सही कथन नहीं है— उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है	UPUDA/LDA (Pre) G.S. 2001
■ भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है— वन्य जीव का संरक्षण	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है— वन्य जीवों	SSC JE CIVIL 09/10/2023 (Shift-III)
■ मौलिक कर्तव्य हैं और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं— वैधानिक	SSC CGL (Tier-1) – 27/07/2023 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जाँच और सुधार की भावना विकसित करे— 51A	SSC JE Mechanical – 22/03/2021 (Shift-I) SSC CGL (Tier-1) – 18/07/2023 (Shift-II)
■ 'देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यन्वित करने वाली समिति को के नाम से जाना जाता है— जे.एस. वर्मा समिति	SSC CHSL (Tier-1) – 10/08/2023 (Shift-II)
■ एक मौलिक कर्तव्य नहीं है— अस्पृश्यता-उन्मूलन के लिए प्रयास करना	UPPCS (J) 2023

सरकार की शासन प्रणाली (Government Governance)

संसदीय व्यवस्था

■ संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है-	विधान-मंडल के प्रति	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-I
■ भारत में प्रकार की सरकार है-	संसदीय	RRB Group- D – 11/10/2022 (Shift-I)
■ सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है-	उत्तरदायी शासन को	UPSI 20.11.2021 Shift-I
■ परम्परागत रूप से भारत की संसद में 'शून्यकाल' का प्रारम्भ होता है-	12:00 बजे मध्याह्न काल	UPPCS (J) 2023 SSC CGL (Tier-I) – 13/06/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संसद की कार्यवाही में 'शून्य काल' का अर्थ है-	प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है-	धन विधेयक	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारत में संसदात्मक व्यवस्था केन्द्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी- 1980 के दशक में		UPPCS (M.) Spl. G.S. II nd 2008
■ यह एक लोकतांत्रिक गणतन्त्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह सभी मूलभूत लक्षण हैं- भारत में राजनीतिक व्यवस्था के		UPPCS (Pre) G.S., 2009
■ विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है-	संसदात्मक शासन व्यवस्था में	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है-	अध्यक्षात्मक सरकार	UPPCS (Main) G.S. II nd 2015
■ गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है-	सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान (एक ही) व्यक्ति में निहित हो	UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2010
■ सरकार के संसदीय स्वरूप को _____ मॉडल के रूप में भी जाना जाता है- वेस्टमिन्स्टर		SSC GD – 06/02/2023 (Shift-III)
■ अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है- अनुच्छेद 247		SSC CGL (Tier-I) – 26/07/2023 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है- 79		SSC CGL (Tier-I) – 17/07/2023 (Shift-III)
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 100(3) के तहत, संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है-		SSC GD – 01/02/2023 (Shift-II) UPPCS (Main) G.S. I st Paper 2004
■ भारतीय संविधान के के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो- अनुच्छेद 84		SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-II)
■ जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती, तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है- गणना के आधार पर मतदान (वोट ऑन अकाउंट)		SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-I)
■ भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित किया गया-	वर्ष 1995 में	SSC MTS 18/10/2021 (Shift-I)
■ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, में अधिनियमित किया गया था- 1986		SSC MTS 27/10/2021 (Shift-II)
■ इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख, जिस लोक सभा में उसका निर्वाचन किया गया हो, से लेकर उसके भाग होने के बाद नई लोक सभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है-	सभापति	SSC CHSL 06/08/2021 (Shift-I)
■ भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था-	1956	SSC CHSL 15/04/2021 (Shift-I)
■ सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है- विधेयक		SSC CHSL 15/04/2021 (Shift-II)
■ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार, बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार का होता है- उसके पति		SSC CGL (Tier-I) 11/04/2022 (Shift-II)
■ संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था- 1977		SSC CGL (Tier-I) 20/04/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय करता है-	संसद	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-I)

संघीय व्यवस्था

■ भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है— बहु-स्तरीय सरकार-संघ, राज्य और स्थानीय शासन	RRB Group- D – 27/09/2022 (Shift-II)
■ राजनीतिक व्यवस्था की वह विधा जो अलग-अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है, कि प्रत्येक को अपनी अखण्डता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है— संघवाद	RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-II)
■ वह साकेतिक शब्द (की वर्ड) जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है— संघवाद (Federalism)	RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान की विशेषता राज्य स्तर पर और केन्द्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है— संघवाद	RRB Group-D 22/08/2022 (Shift-I)
■ भारत की समेकित निधि (consolidated Fund of India) वह निधि है जिसमें— भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं	RRB J.E. (14.12.2014, Green paper)
■ “भारतीय संविधान एक सशक्त केन्द्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है” यह कथन है— सर आड्वर जैनिंग्स का	(U.P.P.C.S. (J) (Pre) 2015)
■ “भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है” यह कथन है— के. सी. लीयर का	UPPCS (Main) G.S. II nd 2005
■ भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है— इकहरी नागरिकता	UPPCS (Pre) Re-exam GS, 2015 (U.P.P.C.S. (J) G.K., 2016)
■ ‘संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है’ यह कथन है— ए. के. अच्युत का	UPPCS (M.) Spl. G.S. II nd 2008
■ संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है— लोकसभा	UPPCS (Main) G.S. II nd 2015
■ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है— एकल कार्यपालिका	UPPCS (Main) G.S. II nd 2006
■ कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद् का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये सभी विशेषताएँ हैं— अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की	UPPCS (Main) G.S. II nd 2014

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

■ वह आयोग जिसको केन्द्र- राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुसंशाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था— सरकारिया आयोग	UPSI 22.11.2021 Shift-III UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2 UPSI Batch-3, 20 Dec 2017 UPPCS (Pre) 2018 UPPSC AE-2004 UPPCS (Pre) G.S., 2008 UP RO/ARO (Pre) G.S., 2014 RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में, ‘संक्रामक या संसर्गज रोगों’ का विषय, एक भाग है— समवर्ती सूची का	UPSI 13.11.2021 Shift-I
■ अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र-राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष थे— एम.एम. पुंछी	UPSI 14.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केन्द्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है— अनुच्छेद 245 से 255	UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान की ‘राज्य सूची’ में मौजूद विषयों में से एक है— पुलिस	UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ संघीय संसद राज्य-सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, बरतें वह प्रस्ताव कम से कम समर्थित हो— उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 द्वारा	UPSI Batch-1, 12 Dec 2017
■ राज्य सरकारों को हिन्दी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है— केन्द्र	UPPSC AE-2004
■ किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी-घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्यायनिर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है— संसद को	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017

■ समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं-	संघ और राज्य सरकारें	UPSI Batch-3, 20 Dec 2017 UPSI (Mains), 2014
■ यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है, तो मान्य होगा-	संघ कानून	UPSI Batch-3, 20 Dec 2017
■ केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा तीन सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था-	पी.वी. राजमन्नार को	UPSI Batch-1, 16 Dec 2017
■ वह विषय जो संघ सूची का हिस्सा है-	रक्षा	UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ वह विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आता है-	डाकघर बचत बैंक	UPSI Batch-2, 15 Dec 2017
■ वह विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आता है-	शेयर बाज़ार और वायदा बाज़ार	UPSI Batch-1, 12 Dec 2017
■ वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है-	बाज़ार और मेले	UPSI Batch-3, 12 Dec 2017
■ समवर्ती सूची का एक हिस्सा है-	दिवालियापन और ऋणशोधन क्षमता	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017
■ वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है-	भूमि और भवन पर कर	UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
■ वह विषय जो समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है-	वन्य पशु एवं पश्चियों की सुरक्षा	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ वह विषय जो राज्य सूची के अन्तर्गत आता है-	पथकर	UPSI Batch-3, 14 Dec 2017
■ वह विषय जो समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है-	न्यास और न्यासी	UPSI Batch-3, 16 Dec 2017
■ वह विषय जो राज्य सूची के अन्तर्गत आता है-	पथकर	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ वह विषय जो राज्य-सूची का एक हिस्सा है-	कृषि आय पर कर	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ वह विषय जो संघ सूची का एक हिस्सा है-	रेल सेवा	UPSI Batch-1, 20 Dec 2017
■ संघ सूची का एक हिस्सा है-	औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद	UPSI Batch-3, 19 Dec 2017
■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें, संघ और राज्यों के बीच, अधिकारों एवं कार्यों के आबंटन से संबंधित सूची दी गई है-	सातवीं	UPSI Batch-2, 22 Dec 2017 UPPCS (Pre.) G.S., 1993
■ वह विषय जो समवर्ती सूची में आता है-	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम	UPSI Batch-2, 22 Dec 2017
■ वह विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है-	नशीले पेय	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है-	संघ सूची में दिए विषयों पर	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ वजन और माप के मानकों का संस्थापन का एक हिस्सा है-	समवर्ती सूची	UPSI Batch-1, 19 Dec 2017
■ विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है-	राज्य सूची का	UPSI Batch-1, 21 Dec 2017
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है, और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कानूनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है-	अनुच्छेद 253	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ संघ सूची का एक हिस्सा है-	प्रकाश स्तम्भ	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017
■ भारत के संघीय ढाँचे के अनुसार, खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है-	समवर्ती सूची में	UPSI Batch-1, 13 Dec 2017
■ वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि जो कि राज्य सूची में है, को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है-	अनु. 368	UPSI, 1999
■ वह विषय जिसमें संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है-	बैंकिंग	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ एक नयी अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है-	राज्य सभा का	UPPCS (Pre) 2018
■ शिक्षा एक विधि-विषय के रूप में सम्मिलित है-	समवर्ती सूची	DIET (Pravakta) Exam 2014
■ सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है-	शक्तियों का केन्द्रीकरण	Govt. Inter College (Pravakta) 2015
■ भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है-	भाग 11 और अध्याय 1	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2012

■ भारत में संघ-राज्य सम्बन्ध से सम्बन्धित नहीं है-	इन्द्रजीत गुप्ता समिति	UPPCS (Pre) G.S., 2015
■ संवैधानिक प्राविधानों पर, परम्पराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिये यन्त्रविन्यास पर निर्भर करते हैं-	भारत में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध	UPPCS (Pre.) G.S., 2009
■ ‘राज्य संघ के सामन्त (मातहत) नहीं हैं’ कथन है-	बी.आर. अम्बेडकर का	UPPSC AE-2013
■ भारत के संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों दोनों में प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है-	संसदीय	SSC Selection Posts XI- 28/06/2023 (Shift-IV)

अंतर्राज्यीय सम्बन्ध

■ वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना की गई— सरकारिया आयोग	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ अंतर-राज्यीय विवादों की जाँच करना और उन पर सलाह देना, केन्द्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियाँ करना, प्रमुख उद्देश्य हैं— अंतर राज्यीय परिषदों के	ACF/RFO (Mains) Hind 2018 UPSI Batch-3, 22 Dec 2017
■ बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है— अयोग्य	UPPCS (Pre) 2018
■ कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद सम्बन्धित है— तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी	UPUDA/LAD Special (Pre) G.S. 2010
■ अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को भारत के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है— बिना किसी राज्य की सहमति से	UPPCS (Pre) G.S., 2006
■ संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है— अनुच्छेद 51 क (क)	UPPSC AE-2011
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है— 355	SSC CHSL (Tier-1) – 09/03/2023 (Shift-I)
■ आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान, लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में से अनुधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है— एक वर्ष	SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-III)
■ धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं— अनुच्छेद 352	SSC GD 01/12/2021 (Shift-II)
■ 1959 में, भारत की केन्द्र सरकार ने भारत के संविधान के के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था— अनुच्छेद 356	SSC CHSL 12/04/2021 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का, केन्द्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है— अनुच्छेद 356	SSC Stenographer – 11/11/2021 : Shift-I
■ 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे— फखरुद्दीन अहमद	SSC MTS 11/10/2021 (Shift-III) SSC JE Mechanical 28.10.2020 (Shift-II)
■1975 की रात में, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की— 25 जून	SSC CPO-SI 23/11/2020 (Shift-II) SSC MTS 09/08/2019 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I) – 07/06/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद ‘आपात की उद्घोषणा’ से संबंधित है— 352	SSC MTS 02/11/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है— 356	SSC JE Mechanical - 25/09/2019 (Shift-II)
■ अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है— 360	SSC JE Civil - 25/09/2019 (Shift-I) SSC MTS 06/10/2021 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है— अंतरिक अशांति	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-II)

आपातकालीन उपबंध

■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को ‘आपातकाल की घोषणा’ करने का अधिकार है-	अनुच्छेद 352	RRB Group-D – 27/09/2022 (Shift-I)
■ भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है-	राष्ट्रपति के पास	RRB JE - 27/05/2019 (Shift-I) RRB NTPC 18.04.2016 (Shift-III) Stage I st RRB NTPC 12.03.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ जब इंदिरा गाँधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई— 1975 में		RRB JE - 01/06/2019 (Shift-II)
■ वह अनुच्छेद जिसके अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है— 356		RRB NTPC Stage I st 29.04.2016 (Shift-I)
■ भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था—	इंदिरा गाँधी के शासनकाल में	RRB Group-D 12-10-2018 (Shift-III)
■ आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकता है— आकस्मिक निधि का		RRB Group-D 02-11-2018 (Shift-II)
■ नीलम संजीव रेड़ी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने—	ज्ञानी जैल सिंह	(UPP Constable 27.01.2019 Shift-I)
■ प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं माँगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते— अतारांकित प्रश्न		UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ भारत के राज्य में पहले यह कहा कि केन्द्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन (अनु० 356) के द्वारा खारिज किया जा सकता है— अरुणांचल प्रदेश		UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ भारतीय संविधान में “वित्तीय आपातकाल” का उल्लेख किया गया है— अनुच्छेद 360 में		UPSI 21.11.2021 Shift-II RRB NTPC Stage I st 28.04.2016 (Shift-III) RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-II)
■ किसी राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ को निरस्त करने का अधिकार है— भारत के राष्ट्रपति के पास		UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है— अनुच्छेद 356		UPSI 13.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें ‘आपातकालीन प्रावधान’ शामिल हैं— भाग XVIII		UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ वे आपातकाल जो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं—	1. राष्ट्रीय आपातकाल 2. राज्य आपातकाल 3. वित्तीय आपातकाल	UPSI Batch-1, 21 Dec 2017 UPPCS (Main) G.S. II nd 2014
■ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं— स्वतंत्रता का अधिकार		UPSI Batch-1, 19 Dec 2017
■ आजादी के बाद से भारत में आपातकाल स्थिति घोषित की गई है— तीन बार		UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ भारतीय गणराज्य में, शब्द का तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है— राष्ट्रपति शासन		UPSI Batch-2, 15 Dec 2017
■ भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी— चीनी आक्रमण के समय (1962) में		UPSI (Mains), 2014
■ वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहाँ अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है— एस.आर. बोम्मई मामला		UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ संसद द्वारा संकटकाल (Emergency) की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है— 1 माह के अंतराल में		UPPCS (Pre.) G.S., 2006 UPSI Batch-3, 22 Dec 2017 UPPSC AE-2008

■ आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ायी जा सकती है-	संसद द्वारा	UPPCS (Pre.) G.S. Spl., 2004
■ भारत में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा की गई है— कभी नहीं		UPPCS (Pre.) G.S., 2006
■ भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है— आन्तरिक शान्ति को खतरा		UPPCS (Main) G.S. II nd 2016
■ वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है— व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार		UPPCS (Main) G.S. II nd 2008
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था— पेपू में		UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ संविधान के अन्तर्गत युद्ध या शान्ति की घोषणा की शक्ति निहित है— राष्ट्रपति में		UPPSC Feed & Sanitary Inspector Exam, 2013
■ लोक सभा के विधिटि रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है— राज्य सभा द्वारा और उसके उपरान्त नई लोक सभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से तीस दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है		U.P.P.C.S. (J) 2003
■ राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधार/आधारों पर की जा सकती है— बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय		UPPSC AE-2011
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है— अनु. 356		UPPSC AE-2013

संसद (Parliament)

संरचना एवं कार्यप्रणाली

■ अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है— कानून बनाना	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2
■ किसी केन्द्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है— संसद के पास	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-1
■ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है— वैधानिक निगम	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-1
■ भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल हैं— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-1 UPSI Batch-2, 13 Dec 2017
■ एक बहु मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है— कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
■ संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं— नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा	UDA/LDA 29-11-2015
■ किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है— प्रथम	व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-II)
■ वह संस्था जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है— संसद	गत्रा पर्यवेक्षक - 03-07-2016 (Paper-I)
■ विधायी मामलों में, दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं— धन	UPSSSC Van Rakshak Date : 21/08/2022
■ वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है— अनुच्छेद 112	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 08/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है— अनुच्छेद 84	RRB Group-D – 13/09/2022 (Shift-III)
■ भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक पारित किया गया था— वर्ष 2022 में	RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-III)

■ भारतीय संविधान के अनुसार..... मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है-	डाक एवं तार	RRB Group- D – 25/08/2022 (Shift-II)
■ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार होता है-	कानून द्वारा संसद के पास	RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-II)
■ एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है-	विधेयक	RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-III)
■ भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है-	विधान परिषद्	RPF SI 18/01/2019 (Shift-II) RRB NTPC 31.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना, 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को- रिक्त घोषित कर सकता है		RRB NTPC 16.02.2021 (Shift-II) Stage Ist UP PSC Computer Assistant 2019
■ भारतीय संसद का एक अंग नहीं है-	राज्य विधान सभाएं	RRB NTPC 13.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है-	संसद के किसी भी सदन में मंत्री	RRB NTPC 04.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई-	1952 से	RRB NTPC 18.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है-	6 माह	RRB NTPC Stage I st 26.04.2016 (Shift-I) RRB NTPC Stage I st 27.04.2016 (Shift-II) RRB NTPC 12.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं-	संसद	RRB JE - 27/06/2019 (Shift-III)
■ वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई-	31वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1973	RRB JE - 01/06/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के अन्तर्गत, वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है-	संसद को	RRB NTPC 31.03.2016 (Shift-II) Stage I st RRB NTPC Stage I st 19.01.2017 (Shift-II)
■ भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है-	ग्रीष्म सत्र	RRB JE - 27/05/2019 (Shift-I)
■ भारत की समेकित निधि (consolidated Fund of India) वह निधि है जिसमें- भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं		RRB J.E. (14.12.2014, Green paper)
■ 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव रखा था-	एकवर्थ समिति ने	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा निजी विधेयक		UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है-	संसद	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017 UPPSC Asstt. Forest Conservator Exam, 2015
■ भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी सम्पत्ति पर लागू होते हैं-	संसद के नियम	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है: “संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे” –	अनुच्छेद 79	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017 RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-I) UPSI 17.11.2021 Shift-I UPSI, 1999 UPPCS (Pre.) G.S., 2012 UPPSC AE- 2007 Paper (I) UP Lower (M) G.S. 2013
■ किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है-	मतदान करना	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017

■ एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं— तारांकित प्रश्न	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है— 1. संसद में बोलने की स्वतंत्रता 2. संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति 3. जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर— अवैध नहीं ठहराया जा सकता	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है— सदन को	UPSI Batch-3, 16 Dec 2017
■ संसद की गैलरियों में गैर-सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर, किसी भी वक्त, रोक लगाने का अधिकार है— सदन को	UPSI Batch-3, 16 Dec 2017
■ वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किये गये दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के सन्दर्भ में सही कथन है— 1. न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएँ उपलब्ध होंगी जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता, इत्यादि 2. यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केन्द्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश-व्यवस्था इत्यादि	UPSI Batch-3, 16 Dec 2017
■ सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देती है— संसद	UPSI Batch-1, 20 Dec 2017
■ संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किये जाने का आदेश देता है, या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है— प्रस्ताव	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ मंत्रिमंडल सचिवालय में का गठन किया गया है, ताकि सरकारी नौकरी और निजी, दोनों क्षेत्रों में ठप्प पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द-से-जल्द दूर किया जा सके— परियोजना अनुवीक्षण दल (पीएमजी)	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961, के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय होता है— वित्त मंत्रालय	UPSI Batch-3, 14 Dec 2017
■ जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित करती है— संसद	UPP Constable, 2009
■ साधारण विधेयक सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है— किसी भी	UPSI (Mains), 2014
■ भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है— प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर	UPSI, 1999 Rajaswa Nirikshak - 17.07.2016 (Paper-I)
■ कार्यकरण नियम के अनुसार, हस्ताक्षर और सम्पुष्टि से पहले, सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों (सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त हैं) की आवश्यकता होती है— मंत्रिमण्डल के अनुमोदन की	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है— भारत की संसद के पास	UPSI 16.11.2021 Shift-III UP RO/ARO (Main) G.S., 2014 UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2015
■ भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है— अनुच्छेद 253	UPPSC AE 2020

■ अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से सम्बन्धित थी—	पॉल एपिलबी रिपोर्ट	BEO Re-exam-2006-I
■ संसदीय सम्प्रभुता नहीं है—	भारत में	BEO exam-2006 (I)
■ लोक सभा द्वारा पारित धन-विधेयक राज्य सभा के द्वारा भी पारित मान लिया जायेगा, यदि राज्य सभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती—	14 दिनों तक	UPPCS (Pre.) G.S., 2016
■ यदि उपाध्यक्ष लोक सभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह— मत-बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं		UPPCS (Main) G.S. II nd Paper, 2016
■ भारत की संसद के सम्बन्ध में सही कथन नहीं है— मंत्रिमण्डल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है		UPPCS (Pre.) G.S., 2011
■ पार्लियामेन्ट द्वारा दिसंबर, 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है—	18 वर्ष	UPPCS (Pre.) G.S., 2000
■ संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है— संसद		UPPCS (Pre.) Re-exam G.S., 2015
■ संसद में शून्य काल का समय है—	दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक	UPPCS (Pre.) Re-exam G.S. 2015 UPPCS (Main) G.S. II nd 2015
■ संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है— यदि राज्य सभा ऐसा संकल्प पारित करती है		UPPCS (Pre.) G.S., 2012
■ लाभ के पद (Office of profit) का निर्णय करेगा—	राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद	UPPCS (Pre.) G.S., 2006
■ संसद की बैठक एक वर्ष में होना आवश्यक है—	दो बार	UPPCS (Pre.) G.S., 1995
■ भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्त्रिहित हैं—	संसद में	UPPCS (Pre.) G.S., 1991 U.P. Lower, 2002
■ कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अन्तर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे— संसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ किया जा सकता है		UPPCS (Main) G.S. II nd Paper, 2016
■ जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है—	राष्ट्रपति को	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2011
■ धन विधेयक प्रस्तुत होता है—	लोक सभा में	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper, 2006
■ भारत के किसी राज्य में विधान परिषद् का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है— राज्य विधान सभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा		U.P. Lower (Pre.) G.S. SPI. 2008
■ संसद में 'लेखा के लिये वोट' आवश्यक होता है— जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती		U.P. Lower (Pre.) G.S. SPI. 2008
■ लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है—	द्वितीय वाचन के समय	UP RO/ARO (Main) G.S., 2014
■ बजट का प्रस्तुतीकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित हैं—	सामान्य वित्तीय विधायन में	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2005
■ निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है—	'लेखानुदान'	UPPCS (Main) G.S. 2002
■ भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है— साधारण विधेयक के सम्बन्ध में		UPPCS (Pre.) G.S., 1997
■ भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी—	दहेज उन्मूलन विधेयक के सम्बन्ध में	U.P. Lower (Pre.) Spl. G.S. 2004
■ भारतीय संसद की सम्प्रभुता प्रतिबंधित है—	न्यायिक समीक्षा से	UPPCS (Pre.) G.S., 2015
■ लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्य सभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं—	संसद के अधिकारियों में	U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013 UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2010
■ 'शून्य काल' संसदीय व्यवस्था देन है—	भारत की	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper, 2004
■ 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया— दागी विधायकों से संबंधित विधेयक		UPPCS (Main) G.S. II nd 2014
■ संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है— निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति		UPPSC AE-2011

■ लोक सभा व राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है-	545 व 250	UPPSC AE-2013
■ भारत के संविधान के के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं-	अनुच्छेद 123	SSC MTS 06/08/2019 (Shift-III) SSC CPO-SI – 11/12/2019 (Shift-II)

राष्ट्रपति

■ संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' बुलाने का अधिकार है-	भारत के राष्ट्रपति के पास	UPSI 13.11.2021 Shift-II
■ भारत में, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है-	राष्ट्रपति के पास	UPSI Batch-1, 16 Dec 2017
■ राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है-	भारत के मुख्य न्यायाधीश	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022 RRB Group-D 16-10-2018 (Shift-III) RRB J.E. 2014 (14.12.2014 Red Paper) RRB NTPC 30.01.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे-	डॉ. जाकिर हुसैन	चकबन्दी लेखपाल - 08-11-2015 (Evening)
■ भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र सौंपते हैं-	उपराष्ट्रपति को	ग्राम पंचायत अधिकारी- 21-02-2016 वन रक्षक - 11-12-2015
■ अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिये एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति होती है-	भारत के राष्ट्रपति के पास	लोअर तृतीय - 26-06-2016
■ मृत्युदण्ड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है-	राष्ट्रपति को	जूनियर इंजीनियर/ तकनीकी- 31-07-2016
■ नीलम संजीव रेडी भारत के राष्ट्रपति थे-	6वें	ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- II)
■ भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'चरित्र को बदले बिना' सजा की मात्रा को कम करना' (अनुच्छेद 72) को कहा जाता है-	क्षमादान	ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- II)
■ भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है-	पाँच वर्ष का	व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-II) SSC CHSL 19/10/2020 (Shift-I)
■ वह राष्ट्रपति जो निविरोध निर्वाचित हुए थे-	नीलम संजीव रेडी	स्टेनोग्राफर - 03-04-2016 चकबन्दी लेखपाल - 08-11-2015 (Morning) UPPCS (Pre.) G.S., 1998
■ वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आइरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गये-	वी.वी. गिरि	स्टेनोग्राफर - 03-04-2016
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है-	अनुच्छेद 86	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-II)
■ भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है-	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है-	53	RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 24/08/2022 (Shift-I) UPP Constable (Main), 2014 UPSI (Mains), 2014 UPPCS (Pre.) Re-exam G.S. 2015 UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2010

■ अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं—		RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-III) UPSI (Ranker), 2011 SSC MTS 08/08/2019 (Shift-III) SSC CHSL (Tier-I) –09/07/2019 (Shift-III) SSC MTS 09/08/2019 (Shift-II)
1. संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य		
2. राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य		
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार से संबंधित है—	87	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-I)
■ भारत में, जब संविधान के अतिक्रमण/उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तो आरोप लगाया जाता है—	संसद के किसी भी सदन द्वारा	RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-I)
■ भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है—	राष्ट्रपति	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-I) RRB Group-D 12-11-2018 (Shift-II) RRB NTPC 16.04.2016 (Shift-I) Stage I st UPSI, 1999 RRB NTPC 09.01.2021 (Shift-II) Stage Ist SSC JE Civil 28.10.2020 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से सम्बन्धित है—	60	RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-II)
■ भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु है—	35 वर्ष	RRB Group-D – 17/09/2022 (Shift-III) RRB J.E. 2014 (14.12.2014 Red Paper) RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-III) Stage II nd UPSI 14.11.2021 Shift-II UP Lower (Pre.) G.S., 1998 SSC Stenographer – 11/11/2021 : Shift-I
■ भारत में, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है—	राष्ट्रपति	RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D 25-10-2018 (Shift-II) RRB NTPC 19.04.2016 (Shift-I) Stage I st RRB NTPC 17.01.2017 (Shift-III) Stage I st
■ गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं—	भारत के राष्ट्रपति	RRB Group-D – 06/09/2022 (Shift-III)
■ वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है—	अनुच्छेद 111	RRB Group-D – 14/09/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है—	राष्ट्रपति को	RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-III) UPPCS (Pre) G.S., 2015 UP Lower (M) G.S. 2013 SSC Stenographer – 15/11/2021 : Shift-II
■ वह शर्त जो भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है—	संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए	RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-III)
■ भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है—	राष्ट्रपति	RRB Group-D – 24/08/2022 (Shift-II) RPF Constable 05/02/2019 RRB NTPC 23.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ राष्ट्रपति समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है—	एंग्लो-इंडियन (वर्तमान में स्थगित)	RRB NTPC 18.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 05.03.2021 (Shift-II) Stage Ist

■ भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को, बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है-	राष्ट्रपति को	RRB NTPC 18.01.2021 (Shift-I) Stage 1st
■ भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के में उल्लिखित है-	अनुच्छेद 61	RRB NTPC 25.01.2021 (Shift-I) Stage 1st RRB JE - 25/05/2019 (Shift-III) UPSI, 1999 UPPCS (Pre.) G.S., 1994 SSC CPO-SI – 12/12/2019 (Shift-II) SSC CHSL 06/06/2022 (Shift-II) SSC JE Electrical – 24/03/2021 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I) – 11/06/2019 (Shift-I) SSC MTS 26.10.2021 (Shift -II)
■ भारतीय संविधान के में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे-	अनुच्छेद 74 (1)	RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-I) Stage 1st
■ वह भारतीय राज्य जिसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ-	छत्तीसगढ़	RRB NTPC 15.03.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है-	भारत का मुख्य न्यायाधीश	RRB NTPC 12.02.2021 (Shift-I) Stage 1st UPPCS (Pre.) Re-exam G.S., 2015 SSC CGL (Tier-I) – 07/06/2019 (Shift-I)
■ भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता (second preference) मतणगना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था-	बी.वी. गिरी	RRB NTPC 22.01.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है-	राज्यों के मुख्यमंत्री	RRB NTPC 21.01.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं-	प्रतिभा पाटिल	RRB Group-D 31-10-2018 (Shift-II) RRB NTPC 09.01.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है-	राष्ट्रपति	
■ भारत के चौथे राष्ट्रपति थे-	वराहगिरि वेंकट गिरि	RRB NTPC 01.04.2021 (Shift-I) Stage 1st
■ 25 जुलाई, 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था-	13	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-I) Stage IInd
■ भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं-	रामनाथ कोविंद	RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है-	डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम	RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे-	श्री नीलम संजीव रेण्डी	RRB NTPC 28.12.2020 (Shift-I) Stage 1st
■ भारत में, दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं-	राष्ट्रपति	RRB NTPC 12.01.2021 (Shift-I) Stage 1st
■ भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था-	एस. राधाकृष्णन को	RRB NTPC 04.02.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ वह पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला-	डॉ. जाकिर हुसैन	RRB JE - 25/05/2019 (Shift-III) SSC JE Civil - 23/09/2019 (Shift-II) SSC JE Civil - 25/01/2018 (Shift-II)
■ राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया-	एस. राधाकृष्णन ने	RRB JE - 24/05/2019 (Shift-I)
■ भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में नामित किया जाता है-	12 सदस्यों को	RRB NTPC 12.04.2016 (Shift-I) Stage Ist RRB JE - 28/05/2019 (Shift-I)

■ राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट.....के समक्ष पेश किया जाता है—	RRB JE - 31/05/2019 (Shift-III)
लोक सभा	
■ वह भारतीय राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा—	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
■ राष्ट्रपति का अध्यादेश दिनों तक प्रभावशाली रहता है—	छ: महीने
■ भारत का पहला नागरिक होता है—	राष्ट्रपति
■ निर्वाचिक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, का गठन किया जाता है—	RRB Group-D 28-09-2018 (Shift-I)
संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा	
■ भारत के 14 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद पदभार	RRB Group-D 11-10-2018 (Shift-III)
संभालते थे—	RRB Group-D 05-10-2018 (Shift-I)
■ भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे—	डॉ. जाकिर हुसैन
मीरा कुमार को	RRB Group-D 25-09-2018 (Shift-II)
■ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबंध रखते हैं—	उत्तर प्रदेश से
मीरा कुमार को	RRB ALP & Tec. (17-08-18 Shift-II)
■ रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए पराजित किया—	RRB Group-D 05-11-2018 (Shift-II)
भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई	RRB Group-D 12-10-2018 (Shift-III)
कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति	
■ भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के संबंध में पॉकेट	RRB NTPC Stage I st 29.04.2016 (Shift-II)
वीटो का प्रयोग किया था—	वीटो का प्रयोग किया था—
ज्ञानी जैल सिंह	RRB NTPC 12.04.2016 (Shift-I) Stage I st
■ भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है—	RRB NTPC 10.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ राष्ट्रपति के पांच वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है—	RRB JE CBT-II 29-08-2019 (evening)
जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं	
■ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-II) Stage II nd
अधिकार है—	SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-II)
■ वह अधिकारी जिसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है—	RRB NTPC 31.03.2016 (Shift-II) Stage I st
राष्ट्रपति	
■ आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे—	UPP Constable, 26.10.218 (Shift-2)
■ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं—	UPSI 12.11.2021 Shift-III
भारत के राष्ट्रपति	
■ भारत के राष्ट्रपति को प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचिक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है—	UPSI Batch-1, 13 Dec 2017
एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व	
■ राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति—	UPSI Batch-3, 12 Dec 2017
■ संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं—	UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
राष्ट्रपति	
■ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचिक मण्डल का हिस्सा नहीं है—	UPSI Batch-3, 14 Dec 2017
प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधानपरिषद के निर्वाचित सदस्यगण	
■ संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है—	राष्ट्रपति
■ किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है—	राष्ट्रपति शासन
■ राष्ट्रपति शासन के खण्डन के लिए अनिवार्य नहीं है—	संसद का अनुमोदन
संसद का अनुमोदन	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017

■ विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं-	राष्ट्रपति का	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरम्भ होता है-	संसद सत्र	UPSI Batch-3, 20 Dec 2017
■ राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के के अन्दर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए-	2 महीने	UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है-	राष्ट्रपति	UPSI Batch-1, 20 Dec 2017
■ भारत के केन्द्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है-	राष्ट्रपति द्वारा	UPP Constable, 26.10.218 (Shift-1)
■ भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं-	द्वौपदी मुर्मू	UPP Constable (Pre), 2013
■ राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है-	कोई भी सदन सत्र में नहीं है	UPSI (Mains), 2014
■ भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है-	संसद में महाभियोग	UPSI (Mains), 2014
■ राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है-	राष्ट्रपति के ऊपर	UPSI (Pre), 2011
■ भारत के निविरोध चुने गए राष्ट्रपति थे-	डॉ. संजीव रेड्डी	UPSI, 2001, 1999
■ भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है-	संसद द्वारा	UPSI, 1999
■ वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया-	तक ₹ 5 लाख	(UPP Constable 28.01.2019)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति, क्षेत्र के लिये शांति, प्रगति और सुशासन के लिये विनियम नहीं बना सकता-	मिजोरम	UPSI (Ranker), 2011
■ उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो 'लोकपाल' के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है-	भारत के राष्ट्रपति	UPSI 17.11.2021 Shift-III
■ राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए-	50-50	UPPSC Polytechnic Lecturer 2022
■ भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है-	राष्ट्रपति के पास	UPPSC Polytechnic Lecturer 2022
■ लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है-	राष्ट्रपति	UPPCS (Pre) Exam 2021 UPPCS (Pre.) G.S. 2012 SSC JE Civil – 23/03/2021 (Shift-I)
■ अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है-	राष्ट्रपति	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारतीय राष्ट्रपति जो लोक सभा अध्यक्ष भी रहे हैं-	नीलम संजीव रेड्डी	UPPCS RO/ARO (Pre) 2021
■ भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उप-राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था-	नीलम संजीव रेड्डी ने	UPPCS (Pre) Exam 2022
■ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है-	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	UPPSC Unani Medical Officer 2018
■ राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिये आवश्यक नहीं है-	पढ़ा-लिखा होना	UPPCS (Pre.) G.S., 1992
■ एक सांसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित होने के उपरान्त अपनी सदस्यता छोड़नी होगी		UPPCS (Main) Spl. G.S. IIInd Paper 2008
■ भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है-	कम से कम 14 दिन पूर्व	UPPCS (Pre.) G.S., 2014
■ राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए-	छ: माह में	UPPCS (Pre.) G.S., 2005
■ वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है-	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2005
■ संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं-	अनुच्छेद 53 के अन्तर्गत	
■ भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है-	भारत का राष्ट्रपति	UP RO/ARO (Main) G.S., 2013
■ लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक नियंत्रण से धनराशि निकाली जायेगी-राष्ट्रपति के आदेश द्वारा		U.P.P.C.S. 1993

■ भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले-	UPPCS (Pre.) G.S. 2008
■ किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है—राष्ट्रपति को	UPPCS (Pre.) G.S. 2006
■ विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है— राष्ट्रपति को	UPPCS (Pre.) G.S. 2004
■ भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है— राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper 2008
■ भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं—	UPPCS (Pre.) G.S. Spl. 2004
■ भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है— बाहरी आक्रमण का एवं संस्थान विव्रोह का	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबन्ध कर सकता है— अनुच्छेद 160 में	UPPCS (Main) G.S. II nd 2007
■ संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है— वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2007
■ राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है— भारत सरकार अधिनियम 1935	UPPCS (Main) G.S. II nd 2008
■ राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है— एक न्यायिक शक्ति	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ प्रारम्भ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है— राजेन्द्र प्रसाद, एस. राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी. वी. गिरि	UPPCS (Pre.) G.S., 2009
■ ‘राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है’ यह कथन है— हृदयनाथ कुंजरू का	UPPCS (M.) Spl. G.S. II nd 2004
■ भारत के राष्ट्रपति से सम्बन्धित सही कथन नहीं है— वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ “राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता” यह उक्ति लागू होती है— राष्ट्रपति पर	UPPCS (Main) G.S. II nd 2007
■ भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया— जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह	UPPCS (Main) G.S. I st 2004
■ राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे— नीलम संजीव रेड़ी	UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार दो कार्य अवधि पूर्ण की— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है— उप-राष्ट्रपति की	UPPCS (Pre.) G.S., 1997
■ संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा— चुनाव-आयोग के विचारानुसार	(U.P.P.C.S. (J) (Pre) 2012)
■ प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है— संसद	(U.P.P.C.S. (J) (Pre) 2012)
■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है— भारत के राष्ट्रपति को	UP Lower (M) G.S. 2013
■ प्रेसिडेंसियल आर्डिनेंस (राष्ट्रपति का अध्यादेश) की अधिकतम संभावित अवधि है— छ: महीने	UPPSC AE- 2007 Paper (I)
■ राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है— पी.एम. और उनके मंत्रिमण्डल द्वारा	UPPSC AE-2008
■ लोकसभा को विघटित कर सकता है— राष्ट्रपति	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को _____ कहा जाता है— निर्वाचक मंडल	SSC JE CIVIL 09/10/2023 (Shift-I)
■ भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं— महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य	SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-III)

■ बहुमत-प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है-	राष्ट्रपति	SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-III)
■ भारत का नाममात्र कार्यकारी प्राधिकारी (nominal executive authority) है-	राष्ट्रपति	SSC JE Electrical 10/10/2023 (Shift-II) SSC MTS/Havaldar-05/09/2023 (Shift-III)
■ भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च-पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजीमेंटों की सलामी लेता है-	भारत के राष्ट्रपति	SSC CGL (Tier-1) – 25/07/2023 (Shift-II)
■ भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है-	भारत के राष्ट्रपति	SSC CGL (Tier-1) – 19/07/2023 (Shift-IV)
■ राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है-	अनुच्छेद 55	SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-II)
■ भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है-	अनुच्छेद 60	SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं- 72		SSC GD 06/12/2021 (Shift-I) SSC GD 10/12/2021 (Shift-II) SSC GD 22/11/2021 (Shift-II) SSC CGL (Tier-1) – 27/07/2023 (Shift-III) SSC JE Electrical -26/09/2019 (Shift-II) SSC MTS 27/10/2021 (Shift-III)
■ एक व्यक्ति जो, राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा— अनुच्छेद 57		SSC MTS 06/10/2021 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा— अनुच्छेद 52		SSC JE Civil – 23/03/2021 (Shift-I)
■ भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे—	वी.वी. गिरी	SSC CHSL 02/06/2022 (Shift-I)
■ भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है— संविधान का उल्लंघन करने पर		SSC Stenographer – 11/11/2021 : Shift-I
■ भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है— महाभियोग प्रस्ताव		SSC GD 18/02/2019 (Shift-I)
■ राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना होता है— उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हों		SSC Stenographer – 15/11/2021 : Shift-II
■ भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष (विजिटर) होता है— भारत के राष्ट्रपति		SSC MTS 14/10/2021 (Shift-III)
■ भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था— ज्ञानी जैल सिंह		SSC CHSL 19/04/2021 (Shift-III)
■ केन्द्र राज्य और अंतर-राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर-राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है— भारत के राष्ट्रपति		SSC CHSL 06/06/2022 (Shift-I)
■ संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार, कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है— राष्ट्रपति		SSC MTS 08/08/2019 (Shift-I)
■ जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति थे— आर. वेंकटरमण		SSC JE Civil 30.10.2020 (Shift-I)
■ स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे—	राजेन्द्र प्रसाद	SSC CHSL 19/10/2020 (Shift-III)
■ भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं— भारत के प्रधानमंत्री		SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-I)
■ राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं— राज्यपाल		SSC CPO-SI – 12/12/2019 (Shift-I)
■ संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति के पास है—	राष्ट्रपति	SSC CGL (Tier-I) – 10/06/2019 (Shift-I)
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है— 331 (अब स्थगित)		SSC CGL (Tier-I) – 12/06/2019 (Shift-II)

■ जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे— ज्ञानी जैल सिंह	SSC CPO-SI 23/11/2020 (Shift-I)
■ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं— राजेन्द्र प्रसाद	SSC CHSL (Tier-I) -09/07/2019 (Shift-II)

उपराष्ट्रपति

■ राष्ट्रपति लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है— उप राष्ट्रपति को	SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-II)
■ उप-राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकारके पास है— राज्यसभा	राजस्व लेखपाल - 13-09-2015 (Evening) IAS (Pre) G.S., 2004 UPPCS (Main) G.S. I st 2004 UPPSC AE - 2013
■ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे— डॉ. एस. राधाकृष्णन	वन रक्षक - 11-12-2015
■ भारत के संविधान के अनुसार, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है— उपराष्ट्रपति	RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-II) UPPCS (Pre.) G.S., 1993
■ 11 अगस्त, 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया— जगदीप धनखड़	RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-III)
■का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है— उपराष्ट्रपति	RRB Group-D 15-11-2018 (Shift-III)
■ भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है— उप-राष्ट्रपति का	RRB NTPC 08.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत के उपराष्ट्रपति का पद समय के लिए होता है— 5 वर्ष	RRB JE - 30/05/2019 (Shift-III)
■ भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है— उच्चतम न्यायालय	RRB Group-D 16-11-2018 (Shift-III)
■ पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है— उपराष्ट्रपति	RRB Group-D 07-12-2018 (Shift-III) UPSI 21.11.2021 Shift-II
■ भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है— लोक सभा की सदस्यता का धारक	RRB NTPC 16.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ भारतीय संविधान के के अनुसार, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो— अनुच्छेद 66	RRB Group-D 12-11-2018 (Shift-I) ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- II) SSC CHSL 10/06/2022 (Shift-II) UPPCS GDC 2012 UPPSC AE - 2007 Paper (i) UPPCS (Pre) G.S., 2012 UPSI (Ranker), 2011
■ भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मण्डल में शामिल होते हैं— संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत, सभी सदस्य	UPSI 22.11.2021 Shift-III RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-II) RRB NTPC 07.04.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC Stage I st 19.01.2017 (Shift-III)
■ राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए— 30 वर्ष	UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वकादारी की शपथ लेते हैं— उपराष्ट्रपति	UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
■ उप राष्ट्रपति अधिकतम अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं— 6 महीने	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017
■ उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है— भारत के राष्ट्रपति	UPSI Batch-1, 20 Dec 2017
■ उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है— अप्रत्यक्ष	RO ARO GS Mains Re-exam 2016

■ भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वह व्यक्ति है-	भारत का उपराष्ट्रपति	U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013 UPUDA/LDA (Pre) G.S. 2010
■ भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे-	डॉ. जाकिर हुसैन	SSC CGL Mains -26/10/2023 (Shift-I)
■ सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है-	60 दिन	SSC CHSL 02/06/2022 (Shift-II)
■ उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर जमा करनी होती है-	₹ 15,000	SSC CHSL 31/05/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है-	अनुच्छेद 67	SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-II)
■ भारत के उपराष्ट्रपति का पद वर्षों का होता है-	पाँच	SSC MTS – 15/05/2023 (Shift-I)
■ राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है-	उप-राष्ट्रपति	SSC CHSL 19/03/2020 (Shift-I)
■ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है-	राष्ट्रपति	SSC CGL (Tier-I) 18/04/2022 (Shift-I)

लोकसभा

■ भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है-	लोकसभा अध्यक्ष	UPSI 15.11.2021 Shift-III
■ लोक सभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है-	लोक सभा अध्यक्ष के पास	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2
■ लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में, के पास वोट डालने का अधिकार होता है-	स्पीकर	UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-II
■ भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी-	13 मई, 1952 को	अमीन परीक्षा- 14-08-2016 (Paper-I) SSC CHSL (Tier-I) –08/07/2019 (Shift-I)
■ लोकसभा की सदस्यता के लिये उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है-	25 वर्ष	लघु सिंचाई विभाग - 09-08-2015 राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift-I) राजस्व लोखपाल - 13-09-2015 (Morning) UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-1 UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022 RRB Group-D 11-10-2018 (Shift-III) RRB NTPC 29.03.2016 (Shift-I) Stage I st UPSI 14.11.2021 Shift-I
■ लोक सभा में 'शून्यकाल' की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है-	एक घंटा	जूनियर इंजीनियर/तकनीकी - 27-12-2015
■ लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि है-	एक माह	विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift- II)
■ संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत (संख्या) है-	552 (550 वर्तमान में)	ग्राम विकास अधिकारी - 23-12-2018 (shift- I) RRB J.E. -2014 RPF SI 11/01/2019 (Shift-II) RRB Group-D 18-09-2018 (Shift-II) RRB NTPC 28.12.2020 (Shift-I) Stage Ist UPSI 14-11-2021 Shift II SSC MTS 22/10/2021 (Shift-III)

■ वर्तमान मेंलोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है-	543	राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift-I) RRB NTPC 28.01.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं-	131 (84 + 47)	लोअर द्वितीय - 15-07-2018 UPSI Batch-2, 13 Dec 2017 UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
■ लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है-	5 वर्ष का	लोअर द्वितीय - 15-07-2018 RRB Group-D 11-10-2018 (Shift-II) SSC MTS- 08/05/2023 (Shift-III) (U.P. Lower (Special) 2003) SSC CHSL 06/08/2021 (Shift-II)
■ वह लोकसभा अध्यक्ष जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है-	डॉ. बलराम जाखड़	आबकारी सिपाही - 25-09-2016
■ उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं-	80	कृषि प्रविधिक - 15-02-2019 (UPP Constable 27.01.2019 Shift-I)
■ सांसद निधि की वर्तमान राशि है-	पाँच करोड़ रुपये	कनिष्ठ सहायक - 24-04-2016 RRB J.E. - 2014
■ लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या (कोरम) होनी चाहिए-	सदन के सदस्यों की कुल संख्या की $\frac{1}{10}$	RRB Group- D – 14/09/2022 (Shift-I) UPP Constable (Main), 2014 RRB NTPC Stage I st 19.01.2017 (Shift-II) UPPCS (Main) G.S. II nd 2006 UPPSC AE 2008
■ एक वर्ष में लोकसभा के सत्र होते हैं-	3	RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I) – 13/06/2019 (Shift-II)
■ 2019 के लोकसभा आम चुनावों के बाद लोकसभा का गठन किया गया था-	17 वर्षों	RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-I) RRB NTPC 11.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत के वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है-	लोकसभा में	RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं-	लोकसभा अध्यक्ष	RRB NTPC 03.03.2021 (Shift-II) Stage Ist RPF Constable 05/02/2019 UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2014 UPPCS (Mains) G.S. II nd Paper 2008 UPPCS (Pre) G.S. 2007 SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I) – 13/06/2019 (Shift-I) UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे-	जी.वी. मावलंकर	RRB NTPC 20.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC Stage I st 28.04.2016 (Shift-II) RRB NTPC 28.03.2016 (Shift-II) Stage I st RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-I) Stage II nd RRB NTPC 04.02.2021 (Shift-II) Stage Ist लोअर द्वितीय - 15-07-2018 UPSI 17.11.2021 Shift-III UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II

■ धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है-	केवल लोकसभा में	RRB NTPC 31.07.2021 (Shift-II) Stage Ist UPPCS (Pre) G.S., 2012 UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2011
■ लोकसभा में एक से अधिक सीट है-	मेघालय की	RRB NTPC 22.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थीं-	सुमित्रा महाजन	RRB NTPC 31.07.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ लोकसभा का 16वाँ चुनाव हुआ था-	2014 में	RRB NTPC 28.03.2016 (Shift-I) Stage I st
■ लोकसभा में स्पीकर रही हैं-	सुमित्रा महाजन	RRB Group-D 01-11-2018 (Shift-II) RRB NTPC 12.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ वर्तमान में..... राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है-	उत्तर प्रदेश	RRB NTPC 31.07.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ लोकसभा के प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे-	1951-1952 में	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 03.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है-	लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा	RRB NTPC 19.01.2021 (Shift-I) Stage Ist SSC GD – 08/02/2023 (Shift-IV)
■ दूसरी लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker) थे-	एम. अनंतशयनम् अच्यंगार	RRB NTPC 07.04.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ लोक सभा में उन सदस्यों की कुल संख्या है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है-	530	RRB NTPC Stage I st 19.01.2017 (Shift-III) RRB NTPC Stage I st 30.04.2016 (Shift-III) RRB NTPC 11.04.2016 (Shift-II) Stage I st SSC CPO-SI 24/11/2020 (Shift-II)
■ लोकसभा में (भारत के संविधान के अनुसार) केन्द्र शासित प्रदेशों से अधिकतम हो सकते हैं-	20 सदस्य	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-III) Stage II nd
■ लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है-	लोकसभा का अध्यक्ष	RRB NTPC 29.12.2020 (Shift-II) Stage Ist UPPCS (Pre) G.S., 2014 UP Lower (M) G.S. 2013 SSC CGL (Tier-I) – 12/06/2019 (Shift-II) SSC MTS 08/10/2021 (Shift-III)
■ 17 वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष (Protom Speaker) थे-	वीरेंद्र कुमार	RRB NTPC 06.04.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है-	कार्यवाहक अध्यक्ष	RRB NTPC 05.04.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था-	मीरा कुमार को	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-I) Stage Ist UPPCS (Pre) 2023 UPPSC (main) G.S. II nd Paper 2008 SSC GD 08/03/2019 (Shift-III)
■ वह राजनीतिज्ञ जो कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है-	श्री मनमोहन सिंह	RRB NTPC 14.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से उत्तरदायी है-	लोक सभा के प्रति	RRB Group-D 05-10-2018 (Shift-III) RRB NTPC 01.04.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं-	ओम बिड़ला	RRB Group-D 03-10-2018 (Shift-II) SSC MTS 05/08/2019 (Shift-I)
■ भूतपूर्व लोक सभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं-	इंदौर	RRB NTPC 18.04.2016 (Shift-II) Stage I st

■ वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोक सभा में दूसरे स्थान पर है-	महाराष्ट्र	RRB NTPC 19.04.2016 (Shift-I) Stage I st SSC GD 22/11/2021 (Shift-III)
■ लोक सभा के संदर्भ में 'सदन के नेता' का अर्थ है-	प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-I) Stage II nd
■ नव निर्वाचित लोक सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए 'स्पीकर प्रो टेम (कुछ समय के लिए स्पीकर)' की नियुक्ति करता है-	भारत के राष्ट्रपति	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ वह समिति जिसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं-	प्राक्कलन समिति	UPSI 20.11.2021 Shift-III
■ 17वें आम चुनाव (2019) में लोकसभा में निर्वाचित हुईं-	78 महिलाएं	UPSI 20.11.2021 Shift-III SSC CHSL 15/10/2020 (Shift-II) SSC MTS 27/10/2021 (Shift-III)
■ गणपूर्ति (कोरम) पूरा करने के लिए लोकसभा में सदस्यों (अध्यक्ष सहित) को उपस्थित होना चाहिए-	52 लोकसभा सदस्य	UPSI 17.11.2021 Shift-III
■ लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते लिए जाते हैं-	भारत के समेकित कोष से	UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ दो चरणों में बजट की चर्चा की जाती है-	लोकसभा में	
■ लोक सभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्य सभा की मेज पर रखा जाता है-	'वार्षिक वित्तीय विवरण'	UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है-	लोकसभा के समक्ष	UPSI Batch-2, 15 Dec 2017
■ लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार है-	राष्ट्रपति को	UPSI Batch-1, 16 Dec 2017
■ सामान्यतः लोकसभा की बैठक में के दौरान, प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है-	पहले घंटे	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ लोक सभा में राज्यों को आधार पर सीटें आवंटित होती हैं-	जनसंख्या	UPP Constable (Main), 2014
■ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है-	उपाध्यक्ष	UPSI (Mains), 2014
■ लोक सभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक अर्हता है-	उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो	UPSI (Mains), 2014
■ लोक सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि राज्य से हैं-	उत्तर प्रदेश	UPSI, 1999
■ वह भारतीय राज्य जिसकी लोकसभा में केवल एक सीट है-	मिजोरम	UPSI Batch-1, 19 Dec 2017
■ भारत में (जनसंख्या की दृष्टि से) सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है-	मलकाजगिरी (तेलंगाना)	UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में)-	लक्ष्मीप	UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ लगभग हर 10 वर्ष में, एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति-व-जनजातियों का आरक्षण और वर्षों के लिए बड़ा दिया जाता है-	10	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ अनन्य अधिकार जो लोक सभा के हैं-	1. धन विधेयक को पेश करना 2. मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना	UPPSC AE 2021
■ गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है-	26	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II SSC CHSL 16/04/2021 (Shift-II)
■ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है-	50 सदस्य	GIC (Pravakta) Exam-2009
■ लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं-	त्रिपुरा में	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper, 2016
■ लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है-	स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं विघटन द्वारा	UPPCS (Pre) G.S. 2000
■ लोक सभा के सत्र का अवसान करने के लिये प्राधिकृत हैं-	राष्ट्रपति	UPPCS (Main) G.S. IIInd 2015

■ लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है-	द्वितीय वाचन में	UPPCS (Main) G.S. IInd 2006
■ डिलिमिटेशन के बाद यू.पी. में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोक सभा सांसद क्षेत्र है-	उत्तराव	UPPCS (Main) G.S. IInd 2007
■ 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है-	714	U.P. Lower (Pre.) Spl. G.S. 2004
■ लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है-	उत्तर प्रदेश में	UPPCS (Pre) G.S., 1995
■ प्रो-टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है-	सदस्यों को शपथ दिलाना	UPPCS (Pre.) G.S., 2010
■ लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है-	यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे	UPPCS (Pre) G.S., 2007
■ लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है-	लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा	UPPCS (Pre) G.S. 1997 UPPSC AE-2011
■ लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) अपने 'कॉस्टिंग वोट' का प्रयोग करते हैं-	वोट बराबर-बराबर होने पर	UPPCS (Main) Spl. G.S. IInd Paper 2008
■ लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है-	लोकसभा के डिप्टी-स्पीकर को सम्बोधित कर	UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2014 SSC MTS 18/10/2021 (Shift-II)
■ प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे-	पी. ए. संगमा	UPPCS (Pre) G.S., 2015
■ प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था-	जी. वी. मावलंकर	UPPCS (Pre) G.S., 2005
■ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है-	अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर एवं मेघालय में	UPPCS (Pre.) G.S. 2000
■ लोक सभा के दो सत्रों के अन्तराल को कहते हैं-	सत्रावसान काल	UPPCS (Pre) G.S. 2006
■ 'सत्रावसान' से तात्पर्य है-	लोक सभा के सत्र की समाप्ति करना	(U.P. Civil Judge (Pre) 2013)
■ भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है- लोकसभा अध्यक्ष		UP Lower (M) G.S. 2013
■ लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है-	राष्ट्रपति द्वारा	UPPSC AE-2011
■ 'सदन' के एक सदस्य से 'स्पीकर' बोलने को मना करते हुए, दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है। इसे कहा जाता है-	ईलिंग द फ्लोर	UPPSC AE-2013
■ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है-	राज्यसभा के उपसभापति	SSC CHSL 24/05/2022 (Shift-II)
■ अविश्वास प्रस्ताव में लाया जाता है-	लोकसभा	SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-II)
■ भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है-	प्रधानमंत्री की सलाह पर	SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-II)
■ 'पॉपुलर चैम्बर' कहा जाता है-	लोकसभा को	SSC CGL (Tier-I) – 12/06/2019 (Shift-I)
■ प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे-	एम. अनंतशयनम अच्यंगर	SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-II)
■ दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था-	1957	SSC JE Mechanical – 22/03/2021 (Shift-II)
■ लोक सभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है-	2	SSC CGL (Tier-I) – 07/06/2019 (Shift-III)
■ लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है-	अध्यक्ष	SSC CHSL (Tier-I) – 08/07/2019 (Shift-I)
■ दसवीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता है-		SSC CGL (Tier-I) – 07/06/2019 (Shift-III)
■ लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है-	20	SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर, अंतिम निर्णय के द्वारा लिया जाता है-	अध्यक्ष, लोकसभा	SSC CHSL (Tier-I) – 10/07/2019 (Shift-II)

■ कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है—	लगातार छः महीने	SSC CHSL 30/05/2022 (Shift-III)
■ राज्यों का लोकसभा में सदस्य संख्या का सही सुमेलन है—	UPPCS (J) 2023	
सूची-I	सूची-II	
गुजरात	26	
हरियाणा	10	
हिमाचल प्रदेश	4	
झारखण्ड	14	

■ सही सुमेलन है—

सूची-I	सूची-II
(लोकसभा)	(चुनाव वर्ष)
सातवीं	1980
प्यारहवीं	1996
नवीं	1989
तेरहवीं	1999

राज्य सभा

■ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जा सकता है—	12	राजस्व निरीक्षक - 17-07-2016 (Paper-I) ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- I) RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-II) RRB Group-D : 29/08/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-II) UPSI (Pre), 2011 SSC CHSL 13/04/2021 (Shift-II) SSC Stenographer – 11/11/2021 : Shift-II
■ प्रत्येक दो वर्ष के बाद राज्य सभा के सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं—	1/3	Lower-II (Re-exam) (28-07-2019) UPPSC AE-2008
■ राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं—	उपराष्ट्रपति	परिचालक - 23-08-2015 RRB Group- D – 27/09/2022 (Shift-II) UPPSC (Main) G.S. II nd 2011 SSC CHSL 19/04/2021 (Shift-III) SSC MTS 20/10/2021 (Shift-III)
■ भारत की राज्य सभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था—	वर्ष 2016 में	RRB JE - 23/05/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है—	250	RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift-III) RPF SI 11/01/2019 (Shift-II) RRB JE - 28/06/2019 (Shift-III) RRB Group-D 08-10-2018 (Shift-II) RRB NTPC 30.12.2020 (Shift-II) Stage Ist SSC MTS 08/10/2021 (Shift-III) SSC JE Electrical – 24/03/2021 (Shift-II)
■ राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है—	30 वर्ष	बन रक्षक - 11-12-2015 लोअर द्वितीय- 06-03-2016 RRB JE-22/05/2019 (Shift-III) UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2006
■ प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं—	राज्य सभा	RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-III)

<p>■ राज्यसभा की शक्तियों में से एक है— यह गैर-धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है</p>	राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift - II)
<p>■ इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होती है— राज्यसभा</p>	RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D 17-09-2018 (Shift-I) RRB NTPC 08.02.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 05.04.2016 (Shift-III) Stage I st
<p>■ राज्य सभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है— राज्यसभा के सभापति द्वारा</p>	RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-III)
<p>■ राज्यों की परिषद (राज्य सभा) पहली बार गठित की गई थी— 3 अप्रैल 1952 को</p>	RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-III) UPSI Batch-3, 12 Dec 2017 SSC CHSL 21/10/2020 (Shift-II) SSC CHSL 13/04/2021 (Shift-II)
<p>■ भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में सही कथन है— यह कभी भी भंग नहीं होता</p>	RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-II) RRB NTPC 25.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
<p>■ राज्यसभा के पहले सभापति थे— डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन</p>	RRB NTPC 07.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB JE - 26/06/2019 (Shift-I) RRB NTPC 10.02.2021 (Shift-I) Stage Ist SSC Stenographer– 15/11/2021 : Shift-I
<p>■ किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है— 14</p>	RRB NTPC 09.03.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 19.03.2021 (Shift-I) Stage Ist UPPCS (Pre) G.S. 2006 SSC MTS– 19/05/2023 (Shift-III) SSC Selection Posts XI– 28/06/2023 (Shift-I)
<p>■ राज्य सभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि होती है— छः वर्ष</p>	RRB Group-D 17-09-2018 (Shift-II) RRB NTPC 06.04.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 04.02.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI Batch-1, 20 Dec 2017 UPP Constable (Main), 2014 UPP Constable (Pre), 2013
<p>■ राज्य सभा का कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है— 25</p>	RRB NTPC 27.03.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI 15.11.2021 Shift-III
<p>■ अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता, यदि वह— राज्यसभा सदस्य है</p>	RRB Group-D 24-09-2018 (Shift-I) RRB Group-D 26-09-2018 (Shift-II)
<p>■ अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है— राज्यसभा</p>	RRB Group-D 25-09-2018 (Shift-II) UPPCS (Pre) G.S., 1997
<p>■ राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है—राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा</p>	RRB NTPC 30.03.2016 (Shift-I) Stage I st
<p>■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार, राज्यसभा की संरचना में निहित है— 1. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्य 2. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, अधिकतम दो सौ अड़तीस प्रतिनिधि</p>	UPSI Batch-3, 12 Dec 2017
<p>■ राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के सन्दर्भ में सही कथन हैं— 1. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है 2. भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उन्हें मत देने का अधिकार है</p>	UPSI Batch-3, 14 Dec 2017

■ राज्य सभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो— लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017
■ एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं— राज्यसभा के सदस्य	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017
■ राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आधारित होती हैं— प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर	UPSI 15.11.2021 Shift-II UPPCS (Pre) G.S., 1993 SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-I) SSC CPO-SI – 11/12/2019 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 09/03/2020 (Shift-III) SSC JE Electrical 10.12.2020 (Shift-II)
■ 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है— उत्तर प्रदेश से	UPSI 20.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है— अनुच्छेद -253	UPPCS RO/ARO (Pre) 2021
■ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है— राज्यसभा को	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है— हिमाचल प्रदेश से	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2006, 2010
■ पहली बार एक सांसद/विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी साठ लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वह राज्यसभा के सदस्य थे—	UPUDA/LDA (Pre) G.S. 2001
■ वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है— राज्य सभा	UPPCS (Pre.) G.S. 1992 UPUDA/LDA (Main) G.S., 2010
■ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुये थे— असम से	UPPSC AE- 2007 Paper (I)
■ सांसद जया बच्चन को राज्य सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया, क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थीं— उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद् में	UPPSC AE-2004
■ राज्य सभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है— उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु (वर्तमान में- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल)	UPPSC AE-2011
■ राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं— महाराष्ट्र को	SSC CHSL 30/05/2022 (Shift-II) SSC Stenographer – 12/11/2021 : Shift-I
■ केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है— पुदुचेरी	SSC MTS 20/10/2021 (Shift-II)
■ राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थीं— रुक्मिणी देवी अरुण्डेल	SSC JE Civil - 24/01/2018 (Shift-I)
■ सही सुमेलन है— सूची-I (राज्य) राजस्थान गुजरात कर्नाटक पंजाब	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ सही सुमेलन है— सूची-I (राज्य) असम छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश	UPPSC GIC 2021
सूची-II (राज्यसभा में प्रतिनिधित्व) 10 11 12 7	
सूची-II (राज्यसभा में सीटों की संख्या) 07 05 03 31	

<p>■ सही सुमेलन है-</p> <table border="0"> <tr> <td>सूची-I (राज्य)</td><td>सूची-II (राज्य सभा में स्थान)</td></tr> <tr> <td>छत्तीसगढ़</td><td>5</td></tr> <tr> <td>झारखण्ड</td><td>6</td></tr> <tr> <td>तेलंगाना</td><td>7</td></tr> <tr> <td>उत्तराखण्ड</td><td>3</td></tr> </table>	सूची-I (राज्य)	सूची-II (राज्य सभा में स्थान)	छत्तीसगढ़	5	झारखण्ड	6	तेलंगाना	7	उत्तराखण्ड	3	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
सूची-I (राज्य)	सूची-II (राज्य सभा में स्थान)										
छत्तीसगढ़	5										
झारखण्ड	6										
तेलंगाना	7										
उत्तराखण्ड	3										
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्											
<p>■ भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यावधि को नियति से वादा (ट्रिस्ट विद डेस्टिनी) शीर्षक भाषण दिया था—</p>	संसद (संविधान सभा) से Cane Supervisor (31-08-2019)										
<p>■ भारतीय संसद में मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है—</p>	विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift- I) 50										
<p>■ भारत के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं—</p>	स्टेनोग्राफर - 10-03-2019 UPSI Batch-1, 12 Dec 2017 RRB NTPC 03.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 11.01.2021 (Shift-II) Stage Ist UPPSC AE-2011, 2004										
<p>■ वह भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया—</p>	वी.पी. सिंह Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-II)										
<p>■ 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि थी—</p>	दो हफ्ते Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-II) SSC MTS 13/08/2019 (Shift-II)										
<p>■ वह केन्द्रीय मंत्रालय जिसके तहत नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं—</p>	मानव संसाधान विकास मंत्रालय RRB Group-D 25-09-2018 (Shift-III)										
<p>■ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और वह किस राजनीतिक दल के थे—</p>	सरदार वल्लभभाई पटेल, आईएनसी RRB Group-D 07-12-2018 (Shift-I) RRB NTPC 28.03.2016 (Shift-I) Stage Ist RRB Group-D 30-10-2018 (Shift-I) RRB JE CBT-II 28-08-2019 (evening)										
<p>■ भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 मंत्रालय द्वारा पेश किया गया—</p>	वित्त मंत्रालय RRB ALP & Tec. (13-08-18 Shift-III)										
<p>■ भारतीय संविधान के में कहा गया है कि 'मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी'—</p>	अनुच्छेद 75 (3) RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift-I) UPPCS (Pre) Exam 2021 UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2012 SSC CPO-SI – 12/12/2019 (Shift-I) SSC CHSL (Tier-I) – 11/07/2019 (Shift-I)										
<p>■ भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है—</p>	प्रधानमंत्री RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-III) UPSI 21.11.2021 Shift-I UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2013										
<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है—</p>	अनुच्छेद 78 RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-III) RRB NTPC 07.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 31.01.2021 (Shift-I) Stage Ist U.P. PSC Kanoongo Exam 2015										

■ भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह हैं— रक्षा मंत्री	RRB JE - 31/05/2019 (Shift-II)
■ पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समयकी आयु सर्वाधिक थी— मोरारजी देसाई	RRB NTPC 28.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत में, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा.....को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है— प्रधानमंत्री	RRB NTPC 01.02.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 08.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं— जवाहरलाल नेहरू	RRB JE - 29/05/2019 (Shift-II) RRB NTPC 13.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री (Acting Prime Minister) बने— गुलजारी लाल नंदा	RRB NTPC 22.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 19.04.2016 (Shift-III) Stage I st RRB NTPC 16.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला— लाल बहादुर शास्त्री	RRB JE - 30/05/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है— संघीय	RRB NTPC 31.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं— तीसरी अनुसूची में	RRB NTPC 30.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत के उप प्रधानमंत्री (1977 से 1979 तक) थे— जगजीवन राम	RRB NTPC 16.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ वह भारतीय प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना नहीं किया— चरण सिंह	RRB JE - 27/05/2019 (Shift-III) UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2006
■ पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे— चरण सिंह	RRB JE - 02/06/2019 (Shift-I)
■ एक व्यक्ति, जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य, में होना होगा— 6 महीना	RRB J.E. (14.12.2014, Green paper)
■ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लोक सभा में स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं— वाराणसी	RRB J.E. 2014 (14.12.2014 Set-2, Red Paper)
■ भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम है— नरेन्द्र मोदी	RRB NTPC 30.03.2016 (Shift-II) Stage I st
■ वह प्रधानमंत्री जो भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था— नरेन्द्र मोदी	RRB NTPC 15.02.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 31.03.2016 (Shift-III) Stage I st
■ सीएसआईआर के पदेन अध्यक्ष है— प्रधानमंत्री	RRB NTPC 06.04.2016 (Shift-I) Stage I st
■ भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है— जवाहरलाल नेहरू	RRB NTPC 12.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किये जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए— 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है	RRB NTPC 02.04.2016 (Shift-I) Stage I st RRB NTPC 09.04.2016 (Shift-III) Stage I st RRB Group-D 02-11-2018 (Shift-II)
■ व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख होता है— प्रधानमंत्री	RRB NTPC 01.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ 1975 में आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री थीं— इंदिरा गांधी	UPP Constable, 26.10.218 (Shift-1)
■ ‘आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति’ का अध्यक्ष होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वयक करता है— भारत के प्रधान मंत्री	UPSI 21.11.2021 Shift-III UPPSC ACF-RFO Main II Paper 2019

■ भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है-	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	UPSI 13.11.2021 Shift-I UPSI (Mains), 2014 UPPSC Ayurvedacharya 2022
■ मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपूष्टि के लिए किसी भी समझौते/संधि/सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले वह मंत्रालय जो उसके पाठ का निरीक्षण करके, उसे पारित करता है-	विदेश मंत्रालय	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ भारत की केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् उत्तरदायी है-	लोकसभा के प्रति	UPSI (Mains), 2014
■ वह प्रधानमंत्री जिन्होंने पहली बार लोक सभा को भंग किया था-	इंदिरा गांधी	UPSI, 1999
■ कैबिनेट का नेता होता है-	प्रधानमंत्री	UPSI, 1999
■ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं-	नरेन्द्र दामोदर दास मोदी	UPSI, 1991
■ भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है-	25 वर्ष	UPP Constable, 2009
■ भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है-	6 माह बाद	UPPCS (Pre) G.S. 1993, 1995 UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2015
■ कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं-	केवल कैबिनेट मंत्री	UPPCS (Pre) G.S. 1992
■ अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में लोकसभा के सदस्य थे-	चन्द्रशेखर	UPPCS (Pre) G.S. 2015
■ भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे-	चन्द्र शेखर	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2011
■ भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे-	देवगौड़ा	UPPCS (Pre) G.S., 2005
■ उप-प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ-	संविधान के प्रावधानों से हटकर	UPPCS (Main) G.S. IIInd 2009
■ मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है-	तकनीकी शिक्षा विभाग	UPPCS (Pre.) G.S. 2006
■ भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है-	वित्त मंत्रालय	UPPCS (Main) G.S. II nd 2012
■ भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है-	भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते	UPPCS (Main) G.S. II nd 2011
■ भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है-	बजट	UPPCS (Main) G.S. II nd 2011
■ भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयान्तर के बाद सुशोभित किया-	गुलजारी लाल नन्दा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी	UPUDA/LDA (Main) G.S., 2010
■ प्रधानमंत्री को एक 'निर्वाचित राजा' के रूप में संबोधित किया था-	हिंटन ने	UPPSC AE-2013
■ 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे-	मोरारजी देसाई	SSC MTS 18/10/2021 (Shift-I)
■ स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था-	अगस्त 1963	SSC JE Civil 30.10.2020 (Shift-II)
■ 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने-	गुलजारीलाल नंदा	SSC CHSL (Tier-I) -11/07/2019 (Shift-II)
■ भारत की पहली प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी-	इंदिरा गांधी	SSC GD 11/03/2019 (Shift-II)
■ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म ————— को हुआ था-	2 अक्टूबर, 1904	SSC CPO-SI 25/11/2020 (Shift-II)
■ मोरारजी देसाई भारत के उप-प्रधानमंत्री रहे थे—	1967-1969	SSC CPO-SI 23/11/2020 (Shift-I)

संसदीय समितियाँ एवं विभिन्न प्रस्ताव

■ वह स्थाई समिति जो संसद के प्रत्येक सदन में होती है-	1. याचिका समिति 2. विशेषाधिकार समिति 3. व्यापार परामर्शदात्री समिति	RRB JE - 26/06/2019 (Shift-III)
■ OBC वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था-	राम नंदन समिति	RRB NTPC Stage I st 29.04.2016 (Shift-II)
■ भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा-परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है-	लोक लेखा समिति (पीएसी)	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं— अविश्वास प्रस्ताव		UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ सदन के अधिकार और विशेषाधिकार, उसकी समितियाँ और सदस्यों के अधिकारी हैं— पीठासीन अधिकारी		UPSI Batch-3, 12 Dec 2017

■ संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत 'मूल संरचना' अथवा ढाँचे को 'क्षतिग्रस्त', 'निष्पावारी', 'नष्ट', 'निरस्त', 'परिवर्तन' या 'हेर-फेर' करने के लिए नहीं कर सकती।" वह मामला जो उपरोक्त कथन से सम्बन्धित है-	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य	UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ भारतीय संविधान का पहला संशोधन, वर्षमें कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जर्मीदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए-	1951	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई-	नवीं अनुसूची	UPSI Batch-3, 16 Dec 2017
■ वह मामला जिसमें निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ—	चम्पकम दोरेराजन बनाम मद्रास राज्य	UPSI Batch-1, 16 Dec 2017
■ भारतीय संविधान में संशोधन लाने की पद्धतियां हैं—	3	UPSI Batch-1, 12 Dec 2017
■ लोक-लेखा समिति के सदस्य होते हैं—	(लोक सभा)-1 5 , (राज्य भाग)-0 7	UPPCS (J) 2023
■ भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है—	नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ विशेषाधिकार समिति में सदस्य होते हैं—	15	UPPSC Polytechnic Lecturer 2021
■ सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं—	शाशि थस्कर	UPPSC Polytechnic Lecturer 2022
■ वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिये—	अधिक अनुदान	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है—	एक वर्ष	UPPCS (Main) G.S. II nd 2016
■ संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है—	भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक	UPPCS (Main) G.S. II nd 2011
■ ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया है—	स्थगन प्रस्ताव	UPPCS (Pre.) G.S., 2010
■ भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है—	विश्वास प्रस्ताव	UPPCS (Pre) G.S. 2006 UPPCS (Main) G.S., II nd 2010
■ कटौती प्रस्ताव का संदर्भित सम्बन्ध है—	संघीय बजट	UPPCS (Pre) G.S. 2002 UP Lower (Pre) Sp. G.S., 2002
■ संसदीय समिति गठित नहीं की गई है—	अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में	UPPCS (Main) G.S. II nd 2012
■ 'लेखानुदान' संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है—	निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए	UPPSC AE-2004
■ वह समिति का अध्यक्ष सामान्यतया विषयी दल से होता है—	लोक लेखा समिति	UPPSC AE-2011
विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया		
■ संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है—	1. संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत 2. संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत	UPSI (Mains), 2014
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया—	42 वें संशोधन द्वारा	UPSI, 1999 RRB Group-D 04-10-2018 (Shift-I) RRB Group-D 24-10-2018 (Shift-II) RRB NTPC Stage I st 29.04.2016 (Shift-I) RRB NTPC 23.02.2021 (Shift-I) Stage Ist SSC JE Civil 29.10.2020 (Shift-I) SSC CHSL 05/08/2021 (Shift-III) SSC Stenographer – 12/11/2021 : Shift-I

■ 1992 में संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों (जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है) के बारे में है-	73वाँ	UPSSSC ASO 22/05/2022 Cane Supervisor (31-08-2019) जूनियर इंजीनियर/तकनीकी- 31-07-2016 UPPCS (Pre) Exam 2022 SSC CGL (Tier-I) 13/04/2022 (Shift-I)
■ संविधान के 103 वें संशोधन के जरिए भारत में पारित किया गया है-	‘आर्थिक आरक्षण’	UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-I
■ भारत के संविधान के ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया-	1992 का 73 वां संशोधन अधिनियम	ग्राम विकास अधिकारी - 23-12-2018 (shift- I)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-368 का सम्बन्ध है-	संविधान संशोधन प्रक्रिया से	ग्राम विकास अधिकारी - 05-06-2016
■ भारतीय संविधान के ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी-	1989 का 61वां संशोधन अधिनियम	ग्राम विकास अधिकारी - 23-12-2018 (shift- II) UPSI 21.11.2021 Shift-II UPSI 22.11.2021 Shift-II UPPSC AE 2021 UPPCS (Pre) Exam 2021 SSC JE CIVIL 11/10/2023 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I) 21/04/2022 (Shift-II)
■ संविधान का 52 वां संशोधन संबंधित है-	दल बदल से	लोअर द्वितीय- 06-03-2016 SSC CGL (Tier-I)-2019 – 06/03/2020 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के द्वारा ‘संपत्ति के अधिकार’ को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया-	44वें संविधान संशोधन 1978	RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-I) RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift-III) RRB NTPC 21.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 16.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 07.04.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI 22.11.2021 Shift-III SSC CGL (Tier-I) – 04/06/2019 (Shift-III) SSC GD 18/02/2019 (Shift-III) SSC Stenographer – 11/11/2021 (Shift-I) SSC CHSL 08/06/2022 (Shift-III) SSC CGL (Tier-1)– 17/07/2023 (Shift-II) SSC CGL (Tier-1) – 27/07/2023 (Shift-III)
■ 73वें संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद IX जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243(O) के प्रावधान कवर करता है-	पंचायत	व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे स्थापित किया गया है-	चौबीसवां संशोधन अधिनियम द्वारा	RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था-	1951 में	RRB Group-D 28-09-2018 (Shift-I) RRB Group-D 28-09-2018 (Shift-III) RRB NTPC 28.03.2016 (Shift-I) Stage 1 st RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 04.04.2016 (Shift-III) Stage 1 st UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-I UPSI 17.11.2021 Shift-III

<p>■ भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति वर्णित है-</p>	<p>अनुच्छेद 368 में</p>	<p>RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-I) SSC CHSL 01/06/2022 (Shift-III) SSC CGL (Tier-I) 18/04/2022 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 06/03/2020 (Shift-II)</p>
<p>■ जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य सभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली-</p>	<p>09 अगस्त, 2019 को</p>	<p>RRB NTPC 15.02.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ वह संशोधन जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी—</p>	<p>संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003</p>	<p>RRB NTPC 12.03.2021 (Shift-I) Stage Ist स्टेनोग्राफर - 03-04-2016 RRB NTPC 01.04.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI 12.11.2021 Shift-III</p>
<p>■ वह संशोधन जिससे पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की—</p>	<p>73 वें संशोधन</p>	<p>RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-I) Stage Ist</p>
<p>■ सिक्किम को भारतीय संघ में संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था—</p>	<p>36वां संशोधन</p>	<p>RRB NTPC 22.01.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ 1987 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था—</p>	<p>56वें</p>	<p>RRB NTPC 02.03.2021 (Shift-I) Stage Ist</p>
<p>■ ‘भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते’ के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था—</p>	<p>100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2015</p>	<p>RRB NTPC 15.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 23.07.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था—</p>	<p>वस्तु एवं सेवा कर</p>	<p>RRB NTPC 31.01.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया—</p>	<p>42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम</p>	<p>RRB NTPC 28.12.2020 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 06.04.2021 (Shift-I) Stage Ist UP Lower (Pre) Spl. G.S. 2002 SSC CGL (Tier-I) – 14/07/2023 (Shift-IV) SSC GD 18/02/2019 (Shift-III)</p>
<p>■ श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत....., को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है—</p>	<p>42वें संशोधन अधिनियम</p>	<p>RRB NTPC Stage Ist 27.04.2016 (Shift-I) RRB NTPC 01.04.2021 (Shift-I) Stage Ist</p>
<p>■ भारत के संविधान के अंगो/प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है—</p>	<p>न्यायिक समीक्षा के</p>	<p>RRB NTPC 07.04.2021 (Shift-II) Stage Ist</p>
<p>■ 124 वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है—</p>	<p>सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण</p>	<p>RRB NTPC 15.02.2021 (Shift-I) Stage Ist</p>
<p>■ वह संवैधानिक संशोधन जिसमें नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई—</p>	<p>42वें</p>	<p>RRB NTPC 20.01.2021 (Shift-I) Stage Ist</p>
<p>■ वह संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा दिया गया था—</p>	<p>69वें संशोधन अधिनियम</p>	<p>RRB JE - 02/06/2019 (Shift-II) UPSI 20.11.2021 Shift-I UPPCS (Main) G.S. IInd 2009 SSC GD 08/03/2019 (Shift-III)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक संसद के सदन में पारित होता है—</p>	<p>दोनों, ऊपरी और निचले</p>	<p>RRB Group-D 19-09-2018 (Shift-I)</p>
<p>■ 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है—</p>	<p>भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए</p>	<p>RRB Group-D 10-10-2018 (Shift-I)</p>

■ भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया गया—	RRB NTPC 26.07.2021 (Shift-II) Stage 1st 92वां संशोधन अधिनियम
■ संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य है— ओडिया के स्थान पर उरिया शब्द का प्रयोग	RRB NTPC Stage I st 26.04.2016 (Shift-III)
■ मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या थी— 100	RRB NTPC Stage I st 26.04.2016 (Shift-III) RRB NTPC Stage I st 22.04.2016 (Shift-III) RRB NTPC 03.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ संविधान का वह संशोधन जो सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है— 93वां संशोधन	RRB NTPC 07.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ संविधान का 99वां संशोधनके बारे में है— राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना	RRB NTPC 07.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है— 7वें संवैधानिक संशोधन	UPSI 13.11.2021 Shift-I
■ पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया— 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में ‘न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)’ पर नया भाग XIVA से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था— 42वाँ संशोधन	UPSI 21.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान में.....संशोधन द्वारा “वनों” और “जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा” के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समर्वर्ती सूची में हुआ था— बयालीसर्वे	UPSI 15.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम है— 42वाँ संवैधानिक संशोधन	UPSI 15.11.2021 Shift-III
■ 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था— सन् 1992 में	UPSI 13.11.2021 Shift-I UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ के मामले में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है— अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य	UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था— अनुच्छेद 31A को	UPSI 20.11.2021 Shift-I
■ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था— बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साह के वाद में	UPSI 17.11.2021 Shift-III
■ 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था— सहकारी समितियों को बढ़ावा देना	UPSI 12.11.2021 Shift-II
■के मामले में अपने निर्णय के अनुसार, संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है— बंगाल इम्प्रूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ वह संवैधानिक संशोधन जिसने ‘पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग’ को संवैधानिक दर्जा दिया— 102वां संवैधानिक संशोधन	UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है— मौलिक कर्तव्यों को	UPSI 12.11.2021 Shift-I

■के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास, मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है— गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य	UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल (कॉलेजियम प्रणाली) को बदलना था— 9 वाँ संवैधानिक संशोधन	UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने भारत में ‘शिक्षा के अधिकार’ को मौलिक अधिकार बना दिया— 8 6वाँ संशोधन	UPSI 15.11.2021 Shift-II RRB Group-D – 25/08/2022 (Shift-III) SSC JE CIVIL 11/10/2023 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I) – 07/06/2019 (Shift-II) SSC JE Mechanical - 25/09/2019 (Shift-II) SSC CGL (Tier-1) – 26/07/2023 (Shift-III)
■ “संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती। यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है।” वह ऐतिहासिक मामला जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी— केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने बहुमत से फैसला दिया था कि, जबकि संसद के पास “व्यापक” अधिकार हैं, लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है— 7-6	UPSI Batch-1, 16 Dec 2017
■ भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है— लोकसभा या राज्यसभा में	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ मूल भारतीय संविधान का सातवां अध्याय, जिसे 1956 में संशोधित किया गया था, वह था— भाग B राज्यों के विषय में	UPSI Batch-2, 22 Dec 2017
■ संविधान में 42वाँ संशोधन पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति थे— फर्खरुद्दीन अली अहमद	UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू हुआ— 1 जुलाई, 1961 से	UPPCS (J) 2023
■ वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा ‘दिल्ली’ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया— 69th	UPPCS (Pre) Exam 2022
■ वह संविधान संशोधन अधिनियम जो जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है— 101 वाँ संशोधन अधिनियम	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा ‘भाग IX B’ जोड़ा गया है— 9 7वाँ संवैधानिक संशोधन	UPPSC AE 2021
■ नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद ने पारित किया— 11 दिसम्बर 2019 को	UPPSC Polytechnic Lecturer 2021
■ वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में ‘सहकारी समितियाँ’ शब्द जोड़ा गया— 97वाँ संवैधानिक संशोधन	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ ग्राहरहवें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया— वर्ष 2002 में	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति-निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया— समान आचार संहिता	UPPCS (Pre) G.S., 1998
■ संविधान के 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी हैं— राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए	UPUDA/LDA (Main) G.S. 2010
■ संविधान का 52वाँ संशोधन सम्बन्धित है— दल बदल से	UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2006

■ 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या, 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गयी है। ये तब तक बदली नहीं जायेगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है—	UPPCS (Main) G.S. II nd 2005 2026
■ लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से सम्बन्धित है—	UPPCS (Main) G.S. II nd 2009 79वाँ संशोधन
■ भारत के संविधान का तिरानबेवाँ संशोधन सम्बन्धित है—	केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से
■ भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है—	संविधान संशोधन विधेयक
■ भारत की सरकारी भाषा सम्बन्धी प्रावधान का संशोधन हो सकता है—	सामान्य बहुमत से
■ संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है—	संसद के किसी एक सदन में
■ शिक्षा जो प्रारम्भ में राज्यसूची का विषय था, उसे समर्वर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया—	U.P. Lower (Pre.) G.S. 2008 42वें संशोधन द्वारा
■ भारत में एक नये राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए—	(U.P.P.C.S. 2006) (M.P.A.P.O. 2010) संसद में साधारण बहुमत से
■ संविधान में बारहवां परिशिष्ट जोड़ा गया था—	74वें संशोधन द्वारा
■ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के एक संशोधन को वर्ष _____ में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को 'केन्द्र सरकार द्वारा द्वारा निर्धारित अवधि के लिए' नियुक्त किया जाए—	SSC CGL (Tier-I) 20/04/2022 (Shift-II) 2019
■ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022, दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह _____ राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए है—	SSC CGL Mains -26/10/2023 (Shift-I) कर्नाटक
■ अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी—	SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-I) 89वें
■ संविधान (87वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया—	SSC JE CIVIL 11/10/2023 (Shift-II) 2001
■ संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 में _____ द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था—	SSC Selection Posts XI- 28/06/2023 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था— पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना	SSC CHSL (Tier-I) – 11/08/2023 (Shift-I)
■ के द्वारा, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 'राष्ट्र की एकता' शब्द को 'राष्ट्र की एकता और अखण्डता' में बदला गया—	SSC Stenographer – 11/11/2021 : Shift-I 42वाँ संशोधन अधिनियम
■ भारतीय संविधान का एक सौ तीनवां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में के लिए आरक्षण प्रदान करता है—	SSC GD 09/12/2021 (Shift-III) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
■ 103वाँ संवैधानिक संशोधन संबंधित है—	SSC GD 01/03/2019 (Shift-II) आर्थिक आरक्षण
■ 124वें संविधान-संशोधन के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत है—	SSC JE Electrical 29.10.2020 (Shift-II) 10
■ भारतीय संविधान के के द्वारा अनुच्छेद 51-A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया—	SSC CGL (Tier-I) 11/04/2022 (Shift-I) छियासीवें संशोधन अधिनियम, 2002
■ भारत के संविधान में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था—	SSC CGL (Tier-I) 13/04/2022 (Shift-I) सातवां संशोधन
■ भारत के संविधान के अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया—	SSC CGL (Tier-I) 20/04/2022 (Shift-I) 26वाँ संशोधन अधिनियम 1971
■ भारत के संविधान में संशोधन ने 'टैक्सेस ऑन सर्विसेज' नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा—	SSC CGL (Tier-I) 20/04/2022 (Shift-III) 88वें

■ भारत के संविधान के ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमीदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया-	चौथा संशोधन	SSC CGL (Tier-I) 20/04/2022 (Shift-III)
■ संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था-	56वें	SSC GD 18/11/2021 (Shift-III)
■ संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के आठवें केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया-	12वें	SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-I)
■ भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था-	वर्ष 1951 में	SSC CGL (Tier-I) – 11/06/2019 (Shift-III) SSC MTS 06/08/2019 (Shift-III) SSC CGL (Tier-I) 18/04/2022 (Shift-III) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 07/03/2020 (Shift-I)
■ संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी (अब पुदुचेरी) को केंद्र शासित प्रदेश बनाया- चौदहवें संवैधानिक संशोधन		SSC JE Mechanical – 22/03/2021 (Shift-II)
■ सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था-	22 जुलाई, 2019	SSC JE Civil 11.12.2020 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है- को प्राप्त करना और बांगलादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना	भारत द्वारा क्षेत्रों	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-II)
■ 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद पर लागू किया गया था-	297	SSC CGL (Tier-I) 18/04/2022 (Shift-III)
■ 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में सुधार किया गया था- दलबदल विरोधी कानून को शामिल किया गया		SSC GD 18/02/2019 (Shift-I)
■ 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में भाग जोड़ा है- IX A		SSC MTS 16/08/2019 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I) 19/04/2022 (Shift-II)
■ 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है- 5 वर्ष		SSC MTS 14/08/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी, भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी- प्रणब मुखर्जी		SSC CGL (Tier-I) 12/04/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम, अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा-	चौबीसवें संशोधन	SSC CGL (Tier-I) 12/04/2022 (Shift-I)
■ 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में जोड़ा गया है- भाग IX		SSC MTS 09/08/2019 (Shift-III)
■ एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए- साधारण		SSC JE Civil - 23/01/2018 (Shift-II)
■ भारत के संविधान में संशोधन के अंतर्गत् वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था- 101 वें		SSC CGL (Tier-I)-2019 – 09/03/2020 (Shift-II)
■ संसद ने संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है। यह राज्य से संबंधित है-	उत्तर प्रदेश	SSC MTS/Havaladar-04/09/2023 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I) – 19/07/2023 (Shift-IV)
■ संविधान (अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है-	गोंड	SSC CHSL (Tier-I) – 02/08/2023 (Shift-I)
■ सही सुमेलन है-		RO ARO GS Mains Re-exam 2016
(A) संविधान (94वाँ संशोधन अधिनियम-2006)	सूची-II (संशोधन) (i) अनु. 164 में संशोधन	
(B) संविधान (95वाँ संशोधन) अधिनियम-2009	(ii) अनु. 334 में संशोधन	
(C) संविधान (96वाँ संशोधन) अधिनियम-2011	(iii) आठवीं अनुसूची में संशोधन	
(D) संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम-2019	(iv) अनु. 15 में संशोधन	

वरीयता अनुक्रम

■ _____ में, भारतीय संसद ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) कानून पारित किया—	SSC GD – 08/02/2023 (Shift-IV) दिसंबर 2019
■ राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है— केवल भारतीय संसद के पास	UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया था—	UPPCS (Pre) G.S., 1994 भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान

राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली (State Structure and Its Working)

राज्यपाल/उपराज्यपाल

■ राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है—	राज्यपाल	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
■ भारत के संविधान के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है—	राज्य के राज्यपाल के	लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल होता है— 5 वर्ष का		Lower Exam – 30-09-2019 (Shift-II)
■ स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थीं—	सरोजिनी नायडू	Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-I) UPSI Batch-3, 14 Dec 2017 UPPCS (Main) G.S. II nd 2013 SSC CHSL (Tier-I) – 09/07/2019 (Shift-I)
■ किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है—	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	Lower-II (Re-exam) (28-07-2019) Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-I)
■ विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है—	राज्यपाल में	ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (shift- I)
■ भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका का एक अंग है—	राज्य के राज्यपाल	RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा—	अनुच्छेद 154	RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-I) SSC CHSL 24/05/2022 (Shift-I)
■ केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं—	वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान	RRB JE - 23/05/2019 (Shift-II)
■ भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है—	अनुच्छेद 155	RRB NTPC 12.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है—	राज्यपाल को	RRB NTPC 22.02.2021 (Shift-I) Stage Ist Lower Exam – 01-10-2019 (Shift-II)
■ सामूहिक रूप से राज्य के विधान सभा के प्रति जवाबदेह होती है—	राज्य मंत्रिपरिषद्	RRB NTPC 22.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है—	35 वर्ष	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-I) Stage II nd SSC MTS 22/10/2021 (Shift-II) SSC CHSL 09/08/2021 (Shift-III)
■ राज्य के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है—	राष्ट्रपति द्वारा	RRB Group-D 07-12-2018 (Shift-I) RRB NTPC 31.03.2016 (Shift-I) Stage I st SSC MTS 13/08/2019 (Shift-II) SSC GD 22/11/2021 (Shift-I) SSC MTS/Havaladar– 11/07/2022 (Shift-III)
■ भारतीय गणराज्य में, एक केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है—	उपराज्यपाल	RRB NTPC 02.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ भारत में लेफिटनेंट गवर्नर—	केन्द्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं	RRB NTPC Stage I st 22.04.2016 (Shift-I)
■ राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं—	प्रधानमंत्री के सुझाव पर	UPSI Batch-3, 13 Dec 2017
■ स्वयं इस्तीफा देने के अलावा, वह पद्धति जिसके द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है—	राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति	UPSI Batch-3, 14 Dec 2017

■ किसी राज्य के राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं-	भारत के राष्ट्रपति	UPSI 17.11.2021 Shift-III
■ 'राज्य विधायिका' द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार है-	राज्य के राज्यपाल के पास	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए आवश्यक योग्यताएँ हैं-		UPSI Batch-1, 20 Dec 2017
1. उसकी उम्र कम से कम पैंतीस साल होनी चाहिए		
2. उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए		
3. वह भारत का नागरिक होना चाहिए		
■ चण्डीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है-	पंजाब के राज्यपाल की	UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है-	राज्यपाल	UPP Constable, 26.10.218 (Shift-2) UPP Constable, 26.10.218 (Shift-2)
■ राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है-	अनुच्छेद 213 में	UPSI (Mains), 2014 RO ARO GS Mains Re-exam 2016 SSC JE Civil - 23/09/2019 (Shift-I) SSC Stenographer – 15/11/2021 : Shift-II
■ राज्य का प्रमुख होता है-	राज्यपाल	ACF/RFO (Mains) IIInd 2018
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अन्तर्गत आता है-	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	UP PCS (Pre) 2019
■ जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियाँ और भत्ते होंगे— इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आंबंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2016	
■ विधान सभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिये, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिये एवं विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है-	राज्य का राज्यपाल	UPPCS (Pre) 2009
■ अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य के विधान सभा के गठन में साठ से कम सदस्य नहीं होंगे-	सिविक्कम राज्य	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2015
■ पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए 'वित्त आयोग' का गठन करता है— सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल		UPPCS (Pre) G.S. 2015
■ राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था—	रघुकुल तिलक	UPPCS (Main) G.S. 2003
■ किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑडिनेन्स का अनुमोदन होना आवश्यक है—	राज्य की विधायिका द्वारा	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd 2008
■ एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने (अपना पदभार ग्रहण करने) से पहले _____ के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है—	राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	SSC CGL (Tier-I) – 25/07/2023 (Shift-IV) UP Lower (M) G.S. 2013
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है—	153	SSC MTS 18/10/2021 (Shift-III) SSC MTS/Havaldar–08/09/2023 (Shift-II) SSC CGL (Tier-I) – 12/06/2019 (Shift-I)
■ राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है—	राज्य के राज्यपाल	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 07/03/2020 (Shift-III)
■ महाधिवक्ता, _____ के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है—	राज्यपाल	SSC GD 13/12/2021 (Shift-III)
■ किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल—	पद्मजा नायदू	SSC CGL (Tier-I) – 13/06/2019 (Shift-II)
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार _____ के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती—	राज्यपाल	SSC CPO-SI – 12/12/2019 (Shift-I)
■ भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख होता है—	राज्यपाल	SSC CHSL 18/03/2020 (Shift-III)
■ मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे—	डॉ. सीतारमैया (वर्तमान मंगुभाई पटेल)	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 04/03/2020 (Shift-II)

राज्य विधानमंडल

■ वह राज्य जिसमें विधान परिषद है-	कर्नाटक	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-I UPSI 22.11.2021 Shift-III
■ किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं-	60 एवं 500	ग्राम पंचायत अधिकारी- 21-02-2016 RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-I) RRB NTPC 14.03.2021 (Shift-I) Stage 1st UPSI 17.11.2021 Shift-I UPSI, 1999 UPSI Batch-1, 19 Dec 2017 UPSI - 1999 UPPCS (Main) G.S. II nd 2014
■ भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित करता है-	राज्य विधानसभा का अध्यक्ष	लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ भारत में किस राज्य विधानसभा ने 2020 में, राज्य के लिए तीन राजधानियों (विधायी, कार्यकारी और न्यायिक) का प्रस्ताव करते हुए 'सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक' पारित किया-	आंध्र प्रदेश	UPSSSC JE 2018 Exam. Date:16-04-2022
■ जब भारत की तरह विधानमंडल के दो सदन होते हैं, तो इसे कहा जाता है-	द्विसदनीय विधानमंडल	RRB Group-D –05/09/2022 (Shift-III)
■ किसी भारतीय राज्य के सबसे लम्बे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं-	पवन कुमार चामलिंग	RRB NTPC 15.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 16.04.2016 (Shift-II) Stage Ist
■ वह राज्य जिसमें विधान परिषद है-	आंध्र प्रदेश	RRB NTPC 28.12.2020 (Shift-II) Stage Ist
■ वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है-	दिल्ली	RRB NTPC 28.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ वह भारतीय राज्य जिसमें द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है-	तमिलनाडु	UPP Constable, 18.06.2018 (Shift-1)
■ भारत में 'राज्य विधान सभाओं' का चुनाव आयोजित करता है- भारत निर्वाचन आयोग		UPSI 13.11.2021 Shift-II
■ उत्तर प्रदेश विधान सभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं-	403	UPSI 16.11.2021 Shift-II UPPCS (Pre.) G.S., 2002
■ जिला योजना समिति की संरचना निर्धारित की जाती है-	राज्य विधायिका द्वारा	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ राज्य के राज्यपाल विधानपरिषद् में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हैं, जैसे-	विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार होता है-	संसद को	UPSI Batch-1, 20 Dec 2017 UPPSC AE-2011 UP Lower (M) G.S. 2015-16
■ किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधान सभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे समर्थित होना चाहिए- 1. सदन की बहुमत संख्या द्वारा 2. सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत		UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ वह राज्य जिसमें द्विसदनीय विधायिका है-	बिहार	UPSI Batch-3, 22 Dec 2017 SSC JE Electrical -26/09/2019 (Shift-I) SSC MTS 14/08/2019 (Shift-I)
■ ऐसी परिस्थिति में, जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित सौंपेगा-	राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को	UPPCS (J) 2023
■ राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए 'कोरम' (गणपूर्ति) है-	दस सदस्य या कुल सदस्यता का दसवां हिस्सा, जो भी अधिक हो	UPPCS RO/ARO (Pre) 2021
■ वर्ष 1956 में युनानित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएँ थीं-	5	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd 2004
■ 'राज्य की आकस्मिक निधि' की स्थापना के लिए उत्तरदायी है-	किसी राज्य का विधानमण्डल	UP RO/ARO (Main) G.S. 2014
■ विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है-	4 माह तक	UPPCS (Main) G.S. II nd 2005
■ विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका (स्पीकर) पद पर बना रहता है-	विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd 2004

■ विधान सभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है-	उत्तर प्रदेश की	UPUDA/LDA (Pre) G.S. 2006 SSC MTS 13/10/2021 (Shift-II)
■ भारत में, विधान सभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान, यदि गणपूर्ति (quorum) नहीं है, तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना _____ का कर्तव्य होगा-	अध्यक्ष/सभापति	SSC Selection Posts XI- 27/06/2023 (Shift-III)
■ राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया-	SSC CGL (Tier-1) - 26/07/2023 (Shift-III)	
पश्चिम बंगाल		
■ राज्य के राज्य विधानमंडल में दो सदन हैं-	महाराष्ट्र	SSC MTS/Havaladar- 05/07/2022 (Shift-I)
■ जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार, उच्च सदन, जिसे राज्य विधान परिषद (विधान परिषद) कहा जाता है, राज्यों में है-	छह	SSC CHSL 16/04/2021 (Shift-I) SSC JE Civil - 24/01/2018 (Shift-II) SSC GD 25/11/2021 (Shift-II) UPSI Batch-1, 22 Dec 2017 RRB NTPC 30.01.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ विधानपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए-	1/3	SSC GD – 13/02/2023 (Shift-I) UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है-	संबंधित राज्य के राज्यपाल	SSC MTS 22/10/2021 (Shift-III)
■ कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के सदस्य हैं-	75	SSC CHSL 26/05/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है- 6 वर्ष		SSC JE Civil - 23/09/2019 (Shift-I)
■ विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं-	विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित	SSC CHSL 01/06/2022 (Shift-II)
■ विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं-	दो	SSC CHSL 06/08/2021 (Shift-I)
■ भारत के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद् होगी जिसकी संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के से अधिक नहीं होगी- 10%		SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-II)
■ किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी- पंद्रह प्रतिशत		SSC CGL (Tier-1)- 18/07/2023 (Shift-III)
■ तेलंगाना विधान सभा में मनोनीत सदस्य हैं-	एक	SSC CGL (Tier-1) – 14/07/2023 (Shift-IV)
■ दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं-	119	SSC CGL (Tier-1) – 25/07/2023 (Shift-II)
■ भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं-	सुचेता कृपलानी	SSC MTS 08/08/2019 (Shift-III) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 04/03/2020 (Shift-II) RRB JE - 24/05/2019 (Shift-II) RRB JE - 28/06/2019 (Shift-III) RRB NTPC 31.03.2016 (Shift-I) Stage I st वन रक्षक - 11-12-2015 चकवन्दी लेखपाल - 08-11-2015 (Morning)
■ भारत के संविधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तक जारी रहेगी- पांच साल		SSC MTS/Havaladar- 06/07/2022 (Shift-II)
■ राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसकी के प्रति जिम्मेदार होती है- विधान सभा		SSC Stenographer – 15/11/2021 : Shift-I
■ सही सुमेलन है-		UPPCS (Pre) Exam 2022
सूची-I (राज्य)	सूची-II (विधानसभा की सदस्य संख्या)	
गोवा	40	
उत्तराखण्ड	70	
मणिपुर	60	
उत्तर प्रदेश	403	

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

■ उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री हैं—	योगी आदित्यनाथ	UPSI, 1991
(मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय भी है।)		
■ भारत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री जो पहले मंदिर के एक पुजारी थे—	योगी आदित्यनाथ	RRB Group-D 26-09-2018 (Shift-III)
■ “द्विसदनीय विधानसभा” का मतलब है—	विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है	RRB NTPC 03.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु है—	25	RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-II) Stage II nd
■ मुख्य सचिव का चयन करता है—	राज्य का मुख्यमंत्री	UPP Constable (Main), 2014
■ दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं—	दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वावधान में।	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं—	एम. के. स्टालिन	UPP Constable (Main), 2014
■ मुख्यमंत्री से सम्बन्धी सही कथन नहीं है—	वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है	UPUDA/LDA (Main) G.S. 2010
■ किसी राज्य के मुख्यमंत्री से सम्बन्धित एक सही कथन नहीं है—	राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं	UPUDA/LDA Special (Pre) G.S. 2010
■ राज्य सरकार के मंत्रियों के बेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है—	राज्य विधान सभा द्वारा	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper 2008
■ संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है—	अनुच्छेद 167	UP Lower (M) G.S. 2013
■ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने—	नोंगथोम्बम बीरेन सिंह	SSC GD – 08/02/2023 (Shift-IV)

कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध

■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिये विशेष प्रावधान करता है।	केरल	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
इस अनुच्छेद के अन्तर्गत नहीं आता है—		
■ दिल्ली की विधान सभा विभाजित है—	70 भागों में	DIET (Pravakta) Exam 2014
■ (दिल्ली एन.सी.आर. को छोड़कर) भारत में संघीय क्षेत्र हैं—	छ: (वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 हो गये हैं)	Govt. Inter College (Pravakta) 2015
■ जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य-अवधि होती थी—	छह वर्ष	UPPCS Spl. (Pre.) G.S. 2008
■ जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में ‘सदर-ए-रियासत’ से ‘राज्यपाल’ में बदल दिया गया—	जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठें संशोधन द्वारा	UPPCS (Main) G.S. II nd 2007
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 सम्बन्धित है—	जम्मू कश्मीर राज्य से	UPUDA/LDA Special (Pre) G.S. 2010
■ अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है—	मध्य प्रदेश	UPPCS (Pre.) G.S. 1997
■ राज्य सभा, जम्मू एवं कश्मीर विधान मण्डल एवं राज्य विधान परिषदों में—	किसी भी जाति के लिये आरक्षण नहीं है	UP Lower (Pre) G.S. 1998
■ भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है—	उत्तर प्रदेश	U.P. Lower (Pre.) 2004-05
■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-ख में विशेष उपबन्ध प्रावधानित है—	असम राज्य के लिए	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ भारत का वह राज्य जहाँ “सामान्य (कॉमन) सिविल कोड” लागू है—	गोवा	Govt. Inter College (Pravakta) 2014
■ भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति (Chief Justice) हैं—	डी.वार्ड.चंद्रचूड़	SSC Selection Posts XI– 28/06/2023 (Shift-I)

उच्चतम न्यायालय-गठन, शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

■ मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की मिनर्वा मिल्स	SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-III)
---	-------------------------------------

■ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा-निवृति की सही आयु है-	65 वर्ष	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-II RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II) UPSI 14.11.2021 Shift-I RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-I) RRB JE – 27/06/2019 (Shift-I) RRB NTPC 10.04.2016 (Shift-III) Stage I st RRB NTPC 29.03.2016 (Shift-II) Stage I st RRB NTPC 04.04.2016 (Shift-III) Stage I st RRB NTPC 17.01.2017 (Shift-III) Stage I st RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-III)
■ वह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है-	124	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-1 RRB NTPC 29.01.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI (Mains), 2014 SSC JE Electrical – 24/03/2021 (Shift-II)
■ याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है-	उत्प्रेषण	UPSSSC Computer Operator 10/01/2020
■ भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं-	फतिमा बीबी	UDA/LDA 29-11-2015 असिस्टेन्ट एकाउटेन्ट 22-11-2015 RRB NTPC 11.04.2016 (Shift-I) Stage I st
■ भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी– जस्टिस टी० एस० ठाकुर ने		ग्राम पंचायत अधिकारी- 21-02-2016
■ किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो-	दस	कानून सहायक - 19-02-2019 RRB Group-D 12-11-2018 (Shift-I)
■ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वर्षों की सेवा आवश्यक होती है-	5 वर्ष	व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-II)
■ वह संस्थान जिसके पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है-	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का संरक्षक होता है-	सर्वोच्च न्यायालय	RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift-III)
■ अभिप्राय उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है-	आरंभिक अधिकारिता	RRB Group-D : 13/09/2022 (Shift-I)
■ भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं-	भारत के राष्ट्रपति	RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-I) RRB NTPC 05.04.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश औरअवर न्यायाधीश (puisne Judges) हो सकते हैं – जहाँ इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी-	7	RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-I)
■ भारत के संविधान के के खंड (2) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं-	अनुच्छेद 124	RRB Group-D – 06/10/2022 (Shift-I)
■ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार पृछा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है-	क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत	RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-I)
■ उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष होता है-	महासचिव	RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-II)
■ भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई, से पहले मुख्य न्यायाधीश थे-	दीपक मिश्रा	RRB NTPC 21.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है-	यतो धर्मस्ततो जयः	RRB NTPC 21.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषता 'भारतीय न्यायपालिका' से संबंधित है-	न्यायिक स्वतंत्रता	RRB NTPC 25.01.2021 (Shift-II) Stage Ist

■ वर्तमान परिसर से पहले, भारत का उच्चतम न्यायालय संचालित किया जाता था-	संसद भवन से	RRB NTPC 31.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे-	न्यायमूर्ति रंजन गोगोई	RRB NTPC 04.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे-	रंजन गोगोई	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे-	भारत के मुख्य न्यायाधीश	RRB NTPC 06.04.2016 (Shift-II) Stage I st RRB NTPC 04.04.2016 (Shift-II) Stage I st
■ भारतीय संविधान के भाग-V में अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं-	124 से 147	RRB Group-D 13-12-2018 (Shift-II)
■ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं-	डॉ.वार्ड. चंद्रचूड	RRB Group-D 01-12-2018 (Shift-II) UPP Constable (Pre), 2013
■ अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है—	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	RRB NTPC Stage I st 29.04.2016 (Shift-III)
■ भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है—	न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह	RRB NTPC 11.04.2016 (Shift-I) Stage I st
■ भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है—	भारत के मुख्य न्यायाधीश	RRB NTPC 17.01.2017 (Shift-I) Stage I st
■ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संसद और राज्य विधान सभा की विधायी अतिरेक की जांच की जाती है—	न्यायिक समीक्षा के जरिए	RRB NTPC Stage I st 30.04.2016 (Shift-III)
■ भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रावधानों के अनुसार 'भारत का संघीय न्यायालय' स्थापित किया गया था—	सन् 1937 में	UPSI 14.11.2021 Shift-III UPPCS (Main) G.S. Hind Paper 2015
■ भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है—	भाग II	UPP Constable, 25.10.2018
■ भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून का अंतिम व्याख्याकार होता है—	सर्वोच्च न्यायालय	UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह भाग जो भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन अधिकार क्षेत्र शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है—	भाग V	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ लैटिन शब्द 'हैबियस कॉर्पस' का अर्थ है—	व्यक्ति को पेश किया जाना	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ भारत में सर्वोच्च न्यायालिका निकाय है—	उच्चतम न्यायालय	UPSI 13.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय (कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड)' होगा—	अनुच्छेद 129	UPSI 13.11.2021 Shift-II UPPCS (J) 2023 SSC CHSL 25/05/2022 (Shift-III)
■ न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में 'पीआईएल' का पूर्ण रूप है—	पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ परम दायित्व की अवधारणा को.....के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है—	एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ	UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ भारत में जनहित याचिका के लिए नींव रखी—	न्यायिक सक्रियता ने	UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है—	भारत के राष्ट्रपति के पास	UPSI 13.11.2021 Shift-I
■ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति है—	भारतीय संसद के पास	UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ—	संयुक्त राज्य अमेरिका में	UPSI 20.11.2021 Shift-III
■ 1947 में "न्यायिक सक्रियतावाद" शब्दपद गढ़ा था—	आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने	UPSI 20.11.2021 Shift-II
■ अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था—	ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल	UPSI 20.11.2021 Shift-II
■ भारत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) की अधिकतम संभावित संख्या होती है—	34	UPSI 12.11.2021 Shift-II UPSI Batch-3, 22 Dec 2017

■ भारतीय संविधान का वह भाग जो सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है-	भाग V	(UP SI/ ASI 2018)
■ उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई-	सन् 1950 ई. में	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017 RPF Constable 05/02/2019 RRB NTPC Stage I st 19.01.2017 (Shift-II) RRB NTPC 18.04.2016 (Shift-II) Stage I st SSC MTS 20/10/2021 (Shift-III) SSC CHSL 19/04/2021 (Shift-I)
■ वह याचिका जो सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है—अधिकार पृच्छा (को वारंटो)		UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध हैं— 1. भारत का नागरिक हो 2. कम से कम पांच साल के लिए, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश (लगातार) रहा हो 3. किसी उच्च न्यायालय में एक बकील के रूप में कम से कम दस साल विधिक व्यवसाय किया हो 4. एक प्रतिष्ठित कानूनविद, राष्ट्रपति की राय में	UPSI Batch-1, 19 Dec 2017	
■ यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्यों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है—		UPSI Batch-3, 22 Dec 2017
■ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए तरीका है— सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा		UPSI Batch-1, 21 Dec 2017
■ उच्चतम न्यायालय ने केस में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं— डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार		UPSI (Ranker), 2011
■ राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है— भारत के उच्चतम न्यायालय के पास		UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ भारत के उच्चतम न्यायालय नेके मामले में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया था— एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ		UPSI 20.11.2021 Shift-II
■ वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-23 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया— दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018		UPPCS (J) 2023
■ भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है— संसद में		UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II UPPSC Staff Nurse 2017(2022)
■ सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग-पत्र संबोधित होता है— राष्ट्रपति को		UPPCS (Pre) 2023
■ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है— राष्ट्रपति		UPPCS (Pre.) G.S., 2003 UPPCS (Pre.) G.S., 2000
■ सर्वोच्च न्यायालय में तर्दह न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब— न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है		UPPCS (Pre) G.S., 2000
■ “मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा.....भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता को बनाए रखूँगा.....अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा.....संविधान और कानूनों की रक्षा करूँगा।” यह शपथ ली जाती है— भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा		UPPCS (Main) Spl. G.S. IIInd Paper, 2004
■ उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए— पाँच		UPPCS (Pre) G.S., 2012
■ उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के लिये परामर्श प्रक्रिया के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है— खण्ड (1), अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत		UP Lower (Pre) G.S., 1998
■ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है— संसद द्वारा		UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2008 RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-II)

<p>■ केन्द्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है, वह है— प्रारम्भिक</p>	UPPCS (Pre.) G.S., 2004
<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संविधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है— अनुच्छेद 134-ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना</p>	UPPCS (Pre.) G.S. 2001 UPUDA/LDA (Pre.) G.S., 2001
<p>■ सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है— मूल अधिकारों का संरक्षण</p>	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2006
<p>■ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान के आधारभूत ढाँचे’ के सिद्धान्त को स्पष्ट किया है— केशवानन्द भारती वाद 1973 में</p>	UPPCS (Pre.) G.S. 2016
<p>■ भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक “अभिलेख न्यायालय” है। इसका आशय है कि— इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता है</p>	UPPCS (Pre.) G.S. 2008
<p>■ अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है— सर्वोच्च न्यायालय को</p>	UPPCS (Main) G.S. IIInd Paper 2005
<p>■ भारत में ‘संविधान की मूल संरचना (बुनियादी ढाँचा) के सिद्धान्त’ का स्रोत है— न्यायिक व्याख्या</p>	UPUDA/LDA (Main) G.S., 2010
<p>■ हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम, 1983 को केन्द्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है— अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत</p>	UPPCS (Pre.) G.S. 2005
<p>■ जनहित याचिका की शुरूआत की गई— न्यायिक पहल द्वारा</p>	UPPCS (Main) G.S. IIInd 2008
<p>■ भारत में ‘न्यायिक सक्रियता’ से सम्बन्धित है— जनहित याचिका</p>	UP RO/ARO (Pre) G.S., 2014 Govt. Inter College (Pravakta) 2015 U.P.P.C.S. (J) G.K. 2016
<p>■ प्रत्यक्ष बन्दीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये बन्दी बनाया जा सकता है— 3 माह के लिए</p>	U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013
<p>■ उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है— पांच रिट याचिकायें</p>	U.P. Civil Judge (Pre) 2012
<p>■ न्यायालय में कार्यवाही लम्बित होने की दशा में लागू की जाती है— उत्प्रेषण रिट</p>	(UPPCS (Pre.) G.S. 2010)
<p>■ एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह, वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है— मैण्डेमस (परमादेश)</p>	UPPCS (Pre.) G.S. 2003 UPPCS (Main) G.S. IIInd 2007
<p>■ मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है—सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को</p>	(U.P. Civil Judge (Pre) G.K. 2016)
<p>■ नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है— परमादेश रिटों में</p>	(U.P.P.C.S. 1992)
<p>■ उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खण्डपीठ बनी— गोलकनाथ केस में</p>	UPPCS (Main) Spl. G.S. IIInd Paper, 2004
<p>■ भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह विहित है— भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा</p>	UPPCS (Main) G.S. IIInd 2013
<p>■ उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि “अनुच्छेद 72 तथा 161 के अन्तर्गत दाखिल की गयी दया याचिकायें उनकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है”— शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद</p>	U.P. Civil Judge (Pre) 2013
<p>■ उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ‘संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णीत किये जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा’— नीलवती बहेरा बनाम उडीसा राज्य के वाद में</p>	(U.P. Civil Judge (Pre) 2003)
<p>■ सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्याब्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है— सेहत बनाम भारत संघ के वाद में</p>	(U.P.P.C.S. (Pre) GS 2004) (U.P. Civil Judge (Pre) 2006)
<p>■ पांच न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेक्षित किया है कि ‘स्थगन का सिद्धांत’ विचारण पूर्ण होने तक निर्देश माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मैटिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केन्द्रित है— सहारा इण्डिया रीयल स्टेट कारपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के वाद में</p>	(U.P. Civil Judge (Pre) 2013)

■ भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ‘धूमपान न करने वालों को वायु-प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है’- मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में	(U.P.P.C.S (J). 2013)
■ उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिकसमता एवं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है, वह था— विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य	(U.P.P.C.S. (J) (Pre) 2006)
■ उच्चतम न्यायालय ने पी. ए. संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का निर्णय किया— 3 : 2 के बहुमत	(U.P. Civil Judge (Pre) 2013)
■ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते प्रभारित किये जाते हैं— भारत की संचित निधि	(U.P. Civil Judge (Pre) 2013)
■ भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है— संसदीय अधिनियम द्वारा	U.P. Lower (P) 2004
■ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है। परन्तु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया— बंगाल इम्यूनिटी कं. लि. बनाम बिहार राज्य के वाद में	(U.P. Civil Judge 2006)
■ उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परन्तु ऐसी नियुक्ति की अवधि— दो वर्ष से अधिक नहीं होगी	(U.P.P.C.S. (J) (Pre) 2015)
■ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है— उसने 35वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो	(U.P.P.C.S. (J) 2003)
■ संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाये जा सकते हैं— इसके प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत	UP Lower (M) G.S. 2013
■ वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है— सर्वोच्च न्यायालय	UPPSC AE-2008
■ भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक है— न्यायपालिका	UPPSC AE-2008
■ बेस्ट बेकरी मामले की प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गयी— न्यायालय के समक्ष अपने बयान से बार-बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए	UPPSC AE-2004
■ भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने— हीरालाल जे किसुनदास कानिया	SSC CHSL (Tier-II) – 26/06/2023 SSC MTS 13/08/2019 (Shift-II) UPSI Batch-2, 16 Dec 2017
■ भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत के राज्य से संबंधित हैं— केरल	SSC Selection Posts XI– 27/06/2023 (Shift-I)
■ जनवरी 2022 में, उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है कि, हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियमन से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा— 1956	SSC CGL (Tier-1) – 27/07/2023 (Shift-III)
■ सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकती है— भारत की संसद	SSC CGL (Tier-1) – 26/07/2023 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा— अनुच्छेद 141	SSC CGL (Tier-1) – 21/07/2023 (Shift-II) SSC CGL (Tier-1) – 24/07/2023 (Shift-I)
■ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सौंप सकता है— भारत के राष्ट्रपति को	SSC CHSL 01/06/2022 (Shift-I)
■ भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है— राष्ट्रपति	SSC MTS 02/08/2019 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के अनुसार, के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है— राष्ट्रपति	SSC CHSL 05/08/2021 (Shift-I)
■ PIL का पूर्ण रूप है— पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन	SSC JE Mechanical 27.10.2020 (Shift-II)

■ भारत के संविधान का , सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है-	SSC JE Mechanical - 25/09/2019 (Shift-II) अनुच्छेद 124
■ उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था— जस्टिस वी. रामास्वामी	SSC CGL (Tier-I) – 04/06/2019 (Shift-I)
■ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार वर्ष में लाया गया था— 1991	SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-I)
■ भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है— उच्चतम न्यायालय	SSC MTS 13/08/2019 (Shift-I)
■ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय — पर बाध्यकारी हैं— भारत में सभी न्यायालयों	SSC MTS 13/08/2019 (Shift-I)
■ सर्वोच्च न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है— अनुच्छेद 140	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 06/03/2020 (Shift-III)
■ मई 2023 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों का भारतीय संविधान के _____ के अंतर्गत 'विवाह के असाध्य रूप से टूटने' के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया— अनुच्छेद 142(1)	SSC CHSL (Tier-II) – 26/06/2023

उच्च-न्यायालय-गठन, शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

■ भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है— कलकत्ता उच्च न्यायालय	RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift-II) RRB NTPC 11.04.2016 (Shift-I) Stage I st SSC CHSL (Tier-I) – 21/03/2023 (Shift-II) SSC CHSL 26/05/2022 (Shift-I)
■ जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं— राज्य के उच्च न्यायालय	RRB NTPC 01.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ किंग जॉर्ज - तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई थी— वर्ष 1800 में	RRB NTPC 13.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ नवसृजित उच्च न्यायालय हैं— मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश	लोअर द्वितीय- 06-03-2016
■ विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है— इलाहाबाद हाई कोर्ट	अमीन परीक्षा- 14-08-2016 (Paper-I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है— 241	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-II) RO ARO GS Mains Re-exam 2016
■ उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उल्लिखित है— अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत	RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-II)
■ न्यायालय के आदेशों के लम्बित रहने की स्थिति में पेश धन सौंप दिए जाएंगे— कांजी हाउस को	UPSI (Ranker), 2011 UPSI 17.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है— अनुच्छेद 219	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-III) RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-I)
■ दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी— वर्ष 1966 में	RRB Group-D – 17/09/2022 (Shift-II)
■ भारत के वे तीन शहर जहाँ उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी— कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास	RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-II)
■ नवंबर, 2020 के अनुसार, भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय बनाया गया है— अमरावती में	RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ नवम्बर 2020 के अनुसार, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है— 25	RRB NTPC 29.12.2020 (Shift-II) Stage Ist UPSI, 1999
■ भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनैतिक दल और राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते— जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना	RRB Group-D 10-10-2018 (Shift-III)
■ संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है— उच्च न्यायालय के सामने	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका (seat) को 1869 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था— इलाहाबाद में	UPSI 21.11.2021 Shift-III

■ राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है—	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृति की आयु 62 वर्ष है—		UPSI 21.11.2021 Shift-II SSC CHSL 07/06/2022 (Shift-II) UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय, उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत करेगा—	उच्च न्यायालय के समक्ष	UPSI 21.11.2021 Shift-II
■ भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार स्थापित की गई थी—	सन् 1862 में	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद मृत्युदंड दिया जा सकता है—सत्र न्यायालय द्वारा		UPSI 14.11.2021 Shift-I
■ 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था—	इलाहाबाद में	UPSI 16.11.2021 Shift-II
■ उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को प्रकार की याचिका (रिट) जारी की जाती है, जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात्तरण से रोका जा सके, जो उसके पास नहीं है—	निषेध	UPSI 22.11.2021 Shift-III
■ दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है—	भारत की संसद के पास	UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था—	सन् 1869 में	UPSI 17.11.2021 Shift-II UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 35 के अनुसार, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तराँचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया—	13	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है—	राज्यपाल	UPSI Batch-1, 12 Dec 2017
■ केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है—	कोलकाता उच्च न्यायालय	UPSI Batch-3, 14 Dec 2017
■ वह राज्य जिसके उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांगलादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है—	मेघालय	UPP Constable (Main), 2014
■ संविधान के के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है—	अनुच्छेद 227	UPSI (Mains), 2014
■ वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि ‘उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी होगा’—	अनुच्छेद 141	UPPSC AE 2021
■ पूर्वोत्तर के वह चार राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से सम्बद्ध हैं—	असम, नागालैंड, मिजोरम, एवं अरुणाचल प्रदेश	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है—	इक्कीस (वर्तमान में 25 है)	U.P. Lower (Pre) G.S. 2008
■ सबसे अधिक बैंच है—	गुवाहाटी उच्च न्यायालय की	UPPCS (Main) G.S. II nd 2007
■ बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई—	1861 में	UPPCS (Pre.) G.S., 2013 UPUDA/LDA Special (Pre) G.S., 2010
■ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है—	भारत की संचित निधि से	UPPCS (Main) G.S. II nd 2013
■ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है—	बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट	UPPCS (Pre) Re-exam G.S., 2015
■ उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अन्तर्गत आते हैं—	परमादेश जारी करने की शक्ति	UPPCS (Pre.) G.S. 1997
■ भारत में एक उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में सही कथन नहीं है—	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है	UPPCS (Main) G.S. II nd 2016
■ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है—	परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार	UPPCS (Main) G.S. II nd 2007
■ कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है—	उच्च न्यायालय	RO-ARO GS Re Exam. Pre 2016
■ हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष _____ में लागू किया गया था—	1955	SSC CGL (Tier-I) 21/04/2022 (Shift-II)
■ भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार के पास होता है—	संसद	SSC MTS 19/08/2019 (Shift-III)
■ किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्तति _____ द्वारा की जाती हैं—	उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल	SSC JE CIVIL 09/10/2023 (Shift-I)

■ वर्ष..... तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा—	1971	SSC CGL (Tier-I) – 27/07/2023 (Shift-II)
■ दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन् में की गई थी—	1966	SSC MTS – 08/05/2023 (Shift-III)
■ तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही—	हिमा कोहली	SSC CHSL 12/04/2021 (Shift-I)
■ 1862 में, उच्च न्यायालय की स्थापना पहले की गई थी—	मद्रास	SSC MTS 18/10/2021 (Shift-I)
■ भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है—	राज्यपाल	SSC JE Electrical -26/09/2019 (Shift-II)
■ भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव वर्ष — में शुरू किया गया था—	1991	SSC JE Electrical -26/09/2019 (Shift-I)
■ भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है—	भारत के राष्ट्रपति	SSC JE Civil - 27/01/2018 (Shift-II)

अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण

■ भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त वह शर्त जो एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है—	कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है	UPSI (Ranker), 2011
■ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण' की स्थापना की गई थी—	सन् 1985 में	UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है—	राज्यपाल	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
■ भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी—	सन् 2009 में	UPSI 16.11.2021 Shift-II
■ राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों कोके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है—	संबंधित राज्य का राज्यपाल	UPSI 20.11.2021 Shift-I
■ राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है—	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति	UPPCS (J) 2023
■ जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियन्त्रण में—	राज्य के उच्च न्यायालय के	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के आधार पर की गयी थी—	पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ भारत की संसद में शामिल है—	राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा	SSC CGL (Tier-I) – 10/06/2019 (Shift-I)
■ लोक अदालतें के अधीन बनाई गई है—	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम	SSC CGL (Tier-I) – 06/06/2019 (Shift-I)
■ भारत के संविधान के में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे—	अनुच्छेद 144	SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-I)

स्थानीय शासन (Local Governance)

पंचायती राज का विकास एवं संरचना

■ त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था—	बलवंत राय मेहता कमेटी ने	UPSSSC PET 24/08/2021 Sift-II जनियर इंजीनियर/तकनीकी - 27-12-2015 लोअर ड्रिलीय- 06-03-2016 राज्य मण्डली परिषद् - 30-05-2019 (Shift-I) RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-I) RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-I) Stage Ist UPPSC Polytechnic Lecturer 2022 UPPCS (Pre.) G.S., 1996 BEO Exam 2003 RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-II)
---	---------------------------------	--

■ भारत में राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी—	राजस्थान	UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-I राजस्व लेखपाल - 13-09-2015 (Evening) ग्राम विकास अधिकारी - 22-12-2018 (Shift- II) RRB Group-D – 17/08/2022 (Shift-I) RRB NTPC 21.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB Group-D 15-11-2018 (Shift-I) RRB Group-D – 06/09/2022 (Shift – III) UPSI Batch-3, 20 Dec 2017 UPP Constable (Main), 2014 (UPPCS (Main) G.S. 2003) (UPPCS (Pre.) G.S. 2012) GIC (Pravakta) 2015
■ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद के तहत दिया गया था—	अनुच्छेद 243	UPSSSC Supply Inspector Exam. Date:17/07/2022
■ ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं—	छवि राजावत	UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-I
■ ग्राम सभा में शामिल हैं— वे सभी व्यक्ति जिनके नाम, गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है		UPSSSC Homeopathic Pharmacist 24/10/2019 Cane Supervisor (31-08-2019) RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-I)
■ पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था—	डॉ. मनमोहन सिंह	UPSSSC Homeopathic Pharmacist 24/10/2019
■ वह राज्य जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है—	नागालैंड	UDA/LDA 29-11-2015
■ किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है—	2 3	ग्राम पंचायत अधिकारी- 21-02-2016
■ पंचायती राज संस्था नहीं है—	ग्राम सहकारी संस्था	ग्राम पंचायत अधिकारी - 04-12-2016
■ प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (दिन) को मनाया जाता है। यह दिन संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है—	24 अप्रैल	व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व-सरकार की संस्था है—	पंचायत	कनिष्ठ सहायक - 31-05-2019
■ ग्राम पंचायत तंत्र के तीन स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होती है—	पंचायत समिति	राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया—	1992 में 73वें	राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift - II) RRB Group-D – 11/10/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 06/09/2022 (Shift – III)
■ 27 अगस्त, 2009, को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी—	50%	राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift - II) गत्रा पर्यवेक्षक - 03-07-2016 (Paper-I) RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-II) UPPCS (Pre.) G.S. Spl., 2004 UPPCS (Pre.) G.S., 2012
■ पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाई गई—	वर्ष 2018 में	व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-II)
■ भारत की पंचायती राज व्यवस्था में स्तर हैं—	तीन स्तर	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-I UPSI Batch-1, 16 Dec 2017 SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-I)
■ वह सरकार जो आम लोगों के सबसे करीब हैं—	स्थानीय	RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-II) UPSSSC Mandi Parishad 22/05/2022
■ भारतीय संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं— स्थानीय सरकार के मंत्री		RRB NTPC 24.07.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है—	243J	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का वह भाग जो पंचायतों से संबंधित है—	IX	RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 22/08/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 22/08/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है—	243G	RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-II)

<p>■ भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक पंचायत, जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से वर्ष तक बनी रहेगी, और उससे अधिक नहीं—</p>	5	<p>RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 27/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 17/08/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 25/08/2022 (Shift-III) UPSI 12.11.2021 Shift-III UPSI Batch-3, 21 Dec 2017 SSC CGL (Tier-I) – 11/06/2019 (Shift-I) UP Lower (M) G.S. 2013 SSC MTS 18/10/2021 (Shift-II) SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-II) RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है—</p>	पंचायतें	<p>RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-III) RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ वह इकाई जिसको राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है—</p>	ग्राम सभा	<p>RRB Group-D – 06/10/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है—</p>	तहसील स्तरीय पंचायत	<p>RRB Group-D 29/08/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करना है—</p>	73वां और 74वां	<p>RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift-III) SSC GD 14/02/2019 (Shift-II)</p>
<p>■ 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की— पी. के. थुंगन समिति ने</p>	पंचायत समिति ने	<p>RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift -III) RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है—</p>	नगर पंचायत	<p>RRB Group-D – 17/09/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है—</p>	ग्राम निगम	<p>RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift -I)</p>
<p>■ खंड (Block) पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है—</p>	समिति के सदस्यों द्वारा	<p>RRB Group- D – 11/10/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन..... से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है—</p>	20 लाख	<p>RRB Group-D – 25/08/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-II) SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-II)</p>
<p>■ वह राज्य जिसमें कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है—</p>	मेघालय	<p>RRB Group- D – 14/09/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है—</p>	पंचायतों को	<p>RRB Group- D – 27/09/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ भारत के राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है—</p>	नागालैंड	<p>RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था—</p>	वर्ष 2004 में	<p>RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ न्याय पंचायत का प्रमुख होता है—</p>	सरपंच	<p>RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ पार्षद का निर्वाचन होता है—</p>	नगर निगम में	<p>RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए का प्रावधान है—</p>	नगर पंचायत	<p>RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-III)</p>
<p>■ वह अधिनियम जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को विस्तारित करना था—</p>	PESA अधिनियम 1996	<p>RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद, भारत के सभी राज्यों में एक समान स्तरीय पंचायती राज संरचना है—</p>	3	<p>RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-I)</p>
<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम सभा से संबंधित है—</p>	अनुच्छेद 243 A	<p>RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-II)</p>
<p>■ सभी पंचायत संस्थाओं में, वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के से कम न हों, को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा—</p>	एक तिहाई	<p>RRB Group-D – 14/09/2022 (Shift-II)</p>

■ संविधान के अनुच्छेद 243(C) के तहत, पंचायत की संरचना से सम्बन्धित निर्णय करता है— राज्य विधानमंडल (Legislature of State)	RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-II)
■ किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार होता है— राज्य सरकार के पास	RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-II)
■ भारत के संविधान के में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों— अनुच्छेद 40	RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-I) UPPSC AE-2013
■ पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243D संबंधित है— पंचायत में सीटों के आरक्षण से	RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-III)
■ प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है— एक सरपंच	RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-III)
■ सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है— 1/3	RRB Group-D – 17/08/2022 (Shift-II) RRB NTPC 26.07.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 23.07.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के अंतर्गत आता है— छावनी परिषद (Cantonment Board)	RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-II)
■ 1992 के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था— भाग IX ‘पंचायत’ को	RRB Group-D – 14/09/2022 (Shift-III)
■ पंचायती राज संस्थाओं को अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया— 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992	RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान में पंचायत के लिए स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं— 29 विषय	RRB Group-D 22/08/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 30/08/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 08/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D : 08/09/2022 (Shift -II)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत, नगर पालिकाओं को वर्गीकृत किया गया है— तीन श्रेणियों में	RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-I)
■ शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है— जिला पंचायत	RRB Group-D – 11/10/2022 (Shift-III)
■ वह कार्य जो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के अंतर्गत नहीं आता है— कानून एवं व्यवस्था	RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-III)
■ पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था— 1989 में	RRB Group-D – 06/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है— पंचायती राज संस्थान में	RRB NTPC 13.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ अनुच्छेद 243 C संबंधित है— पंचायतों की संरचना से	RRB NTPC 17.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के अनुसार, पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु है— 21 साल	RRB NTPC 12.01.2021 (Shift-I) Stage Ist UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा— स्थगित समय से 6 माह के अन्दर	RRB NTPC 17.01.2017 (Shift-I) Stage Ist
■ विधान सभा ने पंचायती राज (संशोधन) बिल 2018 पारित किया, ताकि तीन-सतहों की पंचायती राज्य प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में दो-सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके— अरुणाचल प्रदेश	RRB Group-D 07-12-2018 (Shift-I)
■ भारत का पहला नगरपालिका निगम था— मद्रास नगर निगम	RRB Group-D 09-10-2018 (Shift-II)
■ “लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनःस्थापना” के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम था— एल. एम. सिंघवी समिति	RRB NTPC Stage I st 27.04.2016 (Shift-III) UPSI 15.11.2021 Shift-I
■ हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) बिल, 2015 के अनुसार, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन (PRIs) चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है— मैट्रिक	RRB NTPC Stage I st 29.04.2016 (Shift-II)
■ राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता है— न्यूनतम योग्यता, कक्षा 5 है	RRB NTPC Stage I st 26.04.2016 (Shift-II)

■ भू-राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है— गाँव, तालुका, राजस्व प्रभाग और कलेक्टोरेट	UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है— जिलाधिकारी	UPP Constable (Main), 2014
■ पंचायतों द्वारा खातों के रख-रखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा (ऑफिटिंग) के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार है— राज्य विधायिका को	UPSI 21.11.2021 Shift-II
■ वह निकाय जिसमें गाँव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं— ग्राम सभा	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ भारतीय संविधान के “अनुच्छेद 263” के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था— सन् 1954 में	UPSI 20.11.2021 Shift-III
■ वह समिति जो भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है— एन.आर. नारायण मूर्ति समिति	UPSI 20.11.2021 Shift-II
■ स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार (गाँव और नगरीय स्तर की सरकार) को वर्ष..... में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था— 1993	UPSI Batch-1, 13 Dec 2017 RRB Group-D – 13/09/2022 (Shift-II)
■ पंचायती राज व्यवस्था की तीन स्तरीय संरचना है। तीन स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है— ग्राम पंचायतें	UPSI Batch-1, 13 Dec 2017
■ 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था— 73 वाँ संशोधन	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए— महिलाओं के लिए	UPSI Batch-1, 19 Dec 2017
■ भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत सभा का उल्लेख है— ग्राम सभा	UPSI (Ranker), 2011
■ भारत में राजनैतिक विकेन्द्रीकरण सिद्ध करता है— पंचायती राज की स्थापना	UPSI, 1999
■ भारत की संसद द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम लागू किया गया था— सन् 1996 में	UPSI 13.11.2021 Shift-II
■ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है— अनुच्छेद 243डी (3) में	UPPCS (J) 2023
■ भारत के संविधान के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली है— 21 वर्ष की	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है— राज्य निर्वाचन आयोग	UPPCS (Pre) 2023
■ पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन (1977) की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है/हैं पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए।	UPPCS (Pre) 2023
■ पंचायतों में अध्यक्ष-पद के लिए आरक्षण का आधार है— लिंग और जाति	BEO Re-exam-2006-I
■ ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है— स्थानीय मेलों पर कर	UPPCS (Pre) 2018
■ ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है— कृषि आय पर कर	GIC (Pravalkta) 2015
■ पंचायती राज प्रणाली है— स्थानीय स्वशासन	GIC (Pravakta) 2009
■ प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं— पंचायत समिति के सदस्य	UPPCS (Pre.) G.S. 2013
■ संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है— राज्य सरकार द्वारा	UPPCS (Main) G.S. Hind 2008
■ पंचायतों की संरचना के बाबत उपबन्ध करने को अधिकृत है— राज्य का विधान मण्डल	UPPCS (Pre) G.S. 2016
■ पंचायती राज व्यवस्था अपनायी गयी थी—लोकतंत्र की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिये	UPPCS (Pre.) G.S., 2016
■ पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में प्राविधान किया गया— 1993 में	UPPCS (Pre.) G.S., 2010
■ जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं— प्रधान, पंच	UPPCS (Pre.) G.S., 2004
■ स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक व्यवस्था है— पंचायती राज	UP Lower (Pre.) G.S. 1998

■ संविधान के अन्तर्गत पंचायतों में महिलाओं के एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है— अनुच्छेद 243 घ	UPUDA/LDA Special (Main) G.S., 2010	
■ पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी— एल.एम. सिंघवी कमेटी	UPPCS (Main) G.S. II nd 2008	
■ पंचायती राज संस्था से सम्बन्धित नहीं है— पी. वी. एन. राव समिति	UPPCS (Pre.) G.S., 2014	
■ अशोक मेहता समिति ने 'पंचायती राज' के लिए संस्तुति की थी— द्वि-स्तरीय प्रतिमान की	U.P. Lower (Pre.) G.S. 2009	
■ भारतीय संविधान के 73वें (तिहतरवें) संशोधन में सम्मिलित है— जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत	UPUDA/LDA (Pre.) G.S. 2010	
■ पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिये पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा— अरुणाचल प्रदेश	UPPCS (Pre.) G.S., 2016	
■ उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है— नगर पंचायत	UPPCS (Pre.) G.S., 2016	
■ स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है— केन्द्रीय नियंत्रण	UPPCS (M) Spl. G.S. II nd 2008	
■ पंचायती राज संस्था नहीं है— नागालैण्ड	UPPCS (Main) G.S. II nd 2011, 2005	
■ पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बन्दी बनाये जाने की सजा देने का अधिकार है— बिहार राज्य में	UPPCS (Main) G.S. II nd 2005	
■ एक पंचायतों से सम्बन्धित नहीं है— संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010	
■ पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा— राज्य के राज्यपाल द्वारा	UP Lower (M) G.S. 2013	
■ पंचायत के विघटन के उपरान्त वह अवधि जो नए चुनाव सम्पत्र कराने हेतु सही है— छ: माह के अंदर ही	UP Lower (M) G.S. 2015-16	
■ पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धान्त पर फंक्शन सेट अप (आयोजित) करता है, उसे कहते हैं— लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण	UPPSC AE- 2007 Paper (I)	
■ पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रमानुसार क्रम है— 1. बी. आर. मेहता समिति 2. अशोक मेहता समिति 3. राव समिति 4. एल.एम. सिंघवी समिति	UPPSC BEO (Pre) 2019	
■ नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन _____ की जिम्मेदारी है— राज्य निर्वाचन आयोग	SSC MTS- 18/05/2023 (Shift-I)	
■ भारतीय संविधान के भाग-IX के अंतर्गत आता है— पंचायत	SSC CHSL (Tier-1) – 09/03/2023 (Shift-IV)	
■ भारतीय संविधान के के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है— अनुच्छेद 243 ZD	SSC JE Civil - 23/01/2018 (Shift-II)	
■ पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु (संविधान द्वारा निर्धारित) है— 21 वर्ष	SSC Stenographer – 11/11/2021 : Shift-II SSC GD 07/12/2021 (Shift -II)	
■ राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है— अरुणाचल प्रदेश में	SSC JE Mechanical - 27/09/2019 (Shift-II)	
■ भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है— प्रशासनिक प्राधिकरण	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-I)	
■ स्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में _____ शामिल नहीं है— ग्राम समिति	SSC GD 11/02/2019 (Shift-II)	
■ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं— पंचायत चुनाव	RRB Group-D – 17/09/2022 (Shift-II)	
■ सही सुमेलन है— सूची-I (समितियाँ) A. पी.के. थुंगन B. अशोक मेहता C. बी.आर. मेहता D. एल. एम. सिंघवी	सूची-II (वर्ष) 1. 1988 2. 1977 3. 1957 4. 1986	UPPCS RO/ARO (Mains) 2017

■ सही सुमेलन है-		ACF/RFO (Mains) IIInd 2018
पंचायतीराज से संबंधित (समितियाँ)	गठन वर्ष	
(A) अशोक मेहता समिति	(i) 1977 ई.	
(B) जी.के.वी. राव समिति	(ii) 1985 ई.	
(C) एल.एम. सिंघवी समिति	(iii) 1986 ई.	
(D) पी.के. थुंगन समिति	(iv) 1988 ई.	
■ सही सुमेलन है-		UPPCS (Pre) Exam 2022
सूची-I (समिति)	सूची-II (नियुक्ति का वर्ष)	
बलवंत राय मेहता समिति	1957	
अशोक मेहता समिति	1977	
एल.एम. सिंघवी समिति	1986	
पी.के. थुंगन समिति	1988	
नगरीय शासन		
■ भारत में पंचायतीराज की तीन-स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है-	नगर परिषद्	ग्राम विकास अधिकारी - 23-12-2018 (shift- I)
■ राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है-	नगर आयुक्त	RRB Group-D – 30/08/2022 (Shift-III)
■ नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है-	महापौर (मेयर)	UPSI 15.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कार्यात्मक मदों को रखा गया है-	18	UPSI 14.11.2021 Shift-I
■ नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था-	सन् 1992 में	UPSI Batch-2, 14 Dec 2017
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-प के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियत तारीख से वर्ष तक बनी रहेगी-	5 वर्ष	UPSI (Ranker), 2011
■ वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसमें “शहरी स्थानीय शासन” से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे-	74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992	UPSI 12.11.2021 Shift-II RRB Group - D : 07/10/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-II)
■ ‘74वां संवैधानिक संशोधन’ लागू हुआ था-	1 जून 1993 को	UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था-	मद्रास में	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है-	द्वितीय अवस्था को	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ राष्ट्रीय विस्तार सेवा सम्बन्धित है-	विकास खण्ड से	UPPSC Feed & Sanitary Inspector Exam 2013
■ नगरपालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति की गई है-	संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992	UP Lower (M) G.S. 2013
■ संविधान का वह भाग जो नगरपालिकाओं से संबंधित है-	भाग IX (A)	UP Lower (M) G.S. 2015-16
■ किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिये सक्षम है-	संबंधित राज्य का राज्यपाल	UP Lower (M) G.S. 2015-16
■ सही सुमेलन है-		UPPCS (Pre.) G.S. 2009
सूची-I (नगरीय/ग्रामीण इकाई)	सूची-II (स्थानीय शासन संस्था)	
A. झाँसी	1. नगर निगम	
B. मछली शहर	2. नगर पंचायत	
C. टूंडला	3. नगर पालिका परिषद	
D. सैफई	4. क्षेत्र समिति	
■ भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची..... की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है-	शहरी स्थानीय निकायों	RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में ‘वार्ड समितियों’ का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या होनी चाहिए-	तीन लाख या उससे अधिक	RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-III)
■ भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है-	महापौर	RRB Group-D – 20/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-II)

सहकारी समितियाँ

■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है–	21	UPPCS (Pre.) 2016
■ सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है– प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त, ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में		UPPCS (Main) G.S. I st 2008

संवैधानिक निकाय

निर्वाचन आयोग

■ संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे छह साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं यावर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो—	65	राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift - II) विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift- II) UPPCS (Pre.) G.S. 2012
■ संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है–	भारत के राष्ट्रपति	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
■ यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है, तो उसे - करना होगा— किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते		UPSSSC Homeopathic Pharmacist 24/10/2019
■ भारत के ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त’ की नियुक्ति करता है—	राष्ट्रपति	जूनियर इंजीनियर/तकनीकी- 31-07-2016 RRB JE - 30/05/2019 (Shift-I) RRB NTPC 02.03.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI 13.11.2021 Shift-I SSC CGL (Tier-1) – 18/07/2023 (Shift-II) SSC MTS 27/10/2021 (Shift-I)
■ ‘चुनाव आचार संहिता’ के अनुसार, चुनावों के समय निषेध है— 1. घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना 2. प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग 3. निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण		चक्रवर्णी लेखपाल - 08-11-2015 (Evening)
■ भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता की उम्र है—	18 वर्ष	लोअर फ़िल्टरीय - 15-07-2018 UPSI 20.11.2021 Shift-I UPSI Batch-3, 20 Dec 2017 RRB NTPC 13.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 01.02.2021 (Shift-II) Stage Ist SSC CHSL 05/08/2021 (Shift-III)
■ वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं—	राजीव कुमार	UPSSSC JE 2018 Exam. Date:16-04-2022
■ राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है—	राज्य विधान सभाओं	RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-III)
■ भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग गठित किया गया था—	सन् 1952 में	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को दायर किया जा सकता है— सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष		UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ वह संगठन जो भारत में ‘राजनीतिक दलों’ को मान्यता देता है—	भारत निर्वाचन आयोग	UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ ‘भारत के राष्ट्रपति’ के पद का चुनाव आयोजित करता है—	भारत निर्वाचन आयोग	UPSI 15.11.2021 Shift-III UPSI Batch-3, 20 Dec 2017
■ ‘राज्य विधान सभा’ के चुनाव का संचालन करता है—	भारत निर्वाचन आयोग	UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ ‘चुनवा सुधार’ के संबंध में सिफारिशें (अनुशंसाएं) करने के लिए गठन किया गया था— दिनेश गोस्वामी समिति का		UPSI 16.11.2021 Shift-II
■ भारत में एक संवैधानिक निकाय है—	भारत निर्वाचन आयोग	UPSI 22.11.2021 Shift-III
■ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर, भारत निर्वाचन आयोग में सदस्य हैं—	2	UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार है—	भारत के राष्ट्रपति के पास	UPSI 20.11.2021 Shift-II

■ संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव-नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच-प्रक्रिया है-	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017 चुनाव याचिका
■ भारत में मतदाता सूची के बारे में सही कथन हैं– 1. मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है 2. मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद, राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती हैं	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017
■ बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र चर्चा में रहा क्योंकि– कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लोक सभा का चुनाव यहां से लड़ी थीं	UPSI, 1999
■ संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन करता है–	RRB NTPC (Stage-2) 14/06/2022 (Shift-I) चुनाव आयोग
■ भारत में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है– राजनीतिक दलों का पंजीकरण	RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-II)
■ एक राजनीतिक अधिकार है– मतदान का अधिकार	RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें, देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में, भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की परिकल्पना की गई है–	RRB Group-D – 25/08/2022 (Shift-I) अनुच्छेद 324
■ नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है– 21 वर्ष	RRB NTPC 23.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है– राज्यपाल	RRB NTPC 05.04.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ EVM का पूर्ण रूप है– इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन	RRB NTPC 01.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 09.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीने विधान सभा चुनावों में पहली बार प्रयोग में लाई गई थीं– केरल	RRB Group-D 26-11-2018 (Shift-III) RRB NTPC 29.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे– सुकुमार सेन	RRB Group-D 02-11-2018 (Shift-I) RRB NTPC 27.01.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी– 25 जनवरी, 1950 को	RRB NTPC 19.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ नोटा (NOTA) के विकल्प को भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था– वर्ष 2013 में	RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 18.01.2021 (Shift-II) Stage Ist SSC CGL (Tier-II) – 07/03/2023
■ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है– छः वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो	RRB NTPC 03.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पूरे देश में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया– 25 जनवरी को	RRB Group-D 18-09-2018 (Shift-I)
■ आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव हुए थे– 1952 में	RRB Group-D 30-10-2018 (Shift-I) RRB JE CBT-II 29-08-2019 (evening) RRB NTPC 18.01.2017 (Shift-II) Stage II nd SSC JE Mechanical 27.10.2020 (Shift-II) SSC GD 29/11/2021 (Shift-II)
■ भारतीय निर्वाचन आयोग की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है– पंचायत चुनाव	RRB NTPC 11.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है– संसद के दोनों सदन	RRB NTPC 06.04.2016 (Shift-I) Stage I st
■ CEC का अर्थ है– चीफ इलेक्शन कमिश्नर	RRB NTPC 19.04.2016 (Shift-III) Stage I st

■ भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी-	रमा देवी	UPPCS (Pre) Exam 2021
■ भारतीय संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है—	अनुच्छेद 243 K	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ राज्य विधान सभा का निर्वाचन संचालन करता है—	भारत का निर्वाचन आयोग	UPPCS (Main) G.S. Hind Paper 2008
■ निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है—	मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा	UPPCS (Pre.) G.S. 2014
■ मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है— संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर		UPPCS (Pre.) G.S. 1991
■ चुनाव की अधिसूचना जारी करना सम्बन्धित नहीं है—	चुनाव आयोग से	UPPCS (Pre.) G.S., 1992
■ नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में—	1989 में	UPPCS (Pre.) G.S. 2011
■ भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भारत नहीं है— भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेन्शन		UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper, 2004
■ संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित करता है—	अनुच्छेद 324	SSC CGL (Tier-I) – 06/06/2019 (Shift-III) UPPSC AE-2011
■ भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है— 15वाँ		UPPSC AE-2013
■ संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं—		SSC JE CIVIL 11/10/2023 (Shift-I)
■ भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कराता है—	निर्वाचन आयोग	SSC MTS/Havaldar-04/09/2023 (Shift-II) SSC MTS 13/08/2019 (Shift-III)
■ किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को _____ कहा जाता है—	मतदान प्रतिशत	SSC MTS- 16/05/2023 (Shift-II)
■ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के आम चुनाव पहली बार हुए थे—	1993 में	SSC Selection Posts XI- 27/06/2023 (Shift-II)
■ भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना _____ में हुई थी—	1950	SSC Selection Posts XI- 28/06/2023 (Shift-II)
■ भारत का चुनाव आयोग (ECI) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के _____ में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित हैं—	अनुच्छेद 324	SSC CGL (Tier-I) 11/04/2022 (Shift-II)
■ संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराया जाता है—		SSC Stenographer – 12/11/2021 : Shift-II
■ कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे—	अनुच्छेद 326	SSC JE Civil 11.12.2020 (Shift-II)
■ महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थीं—	नीला सत्यनारायण	SSC MTS 13/10/2021 (Shift-III)
■ निर्वाचक नामावली को सामान्यतः कहा जाता है—	मतदाता सूची	SSC MTS 20/10/2021 (Shift-III)
■ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल समय का होता है— 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो		SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-III)
■ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य था— मणिपुर		SSC CHSL 09/08/2021 (Shift-I)
■ _____ मानदंडों और दिशानिर्देशों का एक समूह होता है, जिनका राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान पालन करना होता है—	आचार संहिता	SSC CHSL 19/04/2021 (Shift-II)
■ भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में, VVPAT में 'T' का अभिप्राय है—	ट्रैल	SSC GD 06/12/2021 (Shift-II)
■ प्राधिकरण ने पी. पी. आर. टी. एम. एस. (पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम) शुरू किया—	भारतीय चुनाव आयोग	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 05/03/2020 (Shift-III)
■ सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय/ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को कहा जाता है—	उप चुनाव	
■ मई 1982 में हुए आम चुनावों में निम्नलिखित में से राज्य में पहली बार EVMs का प्रयोग किया गया—	केरल	SSC Selection Posts XI- 27/06/2023 (Shift-IV)
■ भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर, 2021 में सभी मतदान केन्द्रों की डिजिटल मैपिंग के लिये शुरू किया है—	गरुड़ ऐप	UPPSC AE 2021

केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग

<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति को प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है-</p>	अनुच्छेद 280	RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 14/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 09/09/2022 (Shift-I) SSC CHSL (Tier-I) – 10/07/2019 (Shift-II) SSC CPO-SI – 12/12/2019 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 05/03/2020 (Shift-III)
<p>■ वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है-</p>	राष्ट्रपति	SSC JE Electrical 10.12.2020 (Shift-II)
<p>■ 13 वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं-</p>	विजय केलकर	RRB JE CBT-II 28-08-2019 (morning)
<p>■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत प्रावधान है कि, “राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी”-</p>	243 I	RRB Group-D – 27/09/2022 (Shift-I) UPSI 17.11.2021 Shift-I
<p>■ राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका होती है-</p> <p style="text-align: center;">राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का वितरण और निर्धारण</p>		RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-II)
<p>■ प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी-</p>	1951 में	RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-II)
<p>■ भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने-</p>	एन. के. सिंह	RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift-I) RRB NTPC 30.12.2020 (Shift-I) Stage 1st UPSI 12.11.2021 Shift-I
<p>■ भारत सरकार का वह मंत्रालय जो राजकोषीय नीति तैयार करता है-</p>	वित्त	RRB Group-D 28-09-2018 (Shift-I)
<p>■ 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत, वह वृहत्तम मानदंड जिसके आधार पर केन्द्र द्वारा संगृहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है-</p>	राजकोषीय क्षमता	UPSI Batch-2, 22 Dec 2017
<p>■ राष्ट्रपति प्रत्येक वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं-</p>	5	UPSI Batch-1, 14 Dec 2017
<p>■ भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धान्तों पर राष्ट्रपति से सिफारिश करता है-</p>	वित्त आयोग	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017
<p>■ वह संवैधानिक संस्था जिसको ‘भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र (बैलेंसिंग व्हील)’ माना जाता है-</p>	वित्त आयोग	UPSI 14.11.2021 Shift-I
<p>■ वित्त आयोग का गठन किया जाता है-</p>	भारत के राष्ट्रपति द्वारा	UPSI 15.11.2021 Shift-I
<p>■ वह संवैधानिक निकाय जो राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ‘ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण’ के बारे में अनुशासनाएं प्रस्तुत करता है-</p>	वित्त आयोग	UPSI 21.11.2021 Shift-III
<p>■ 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं-</p>	2021-22 से 2025-26 तक	UPPCS (J) 2023
<p>■ भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है-</p> <p style="text-align: center;">संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना</p>		UPPCS (Pre) Exam 2021
<p>■ भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे –</p>	श्री के.सी. नियोगी	UPPCS (Pre) Exam 2021
<p>■ 15 वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मापदण्डों के अन्तर्गत मापदण्ड को उच्चतम भार (प्रतिशत) मिला-</p>	आय दूरी	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
<p>■ बारहवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केन्द्र और राज्यों के राजस्व को घटा कर शून्य करना है वर्ष-</p>	2008-09 तक	BEO Re-exam 2006-I
<p>■ केलकर समिति सम्बन्धित है-</p>	वित्त विभाग	Assistant Professor (Pravakta) 2014
<p>■ 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे-</p>	वाई. वी. रेण्डी	UPPCS (Pre.) G.S. 2016
<p>■ भारत सरकार ने दिनांक 02-01-2013 को गठित किया था-</p>	14वाँ वित्त आयोग	UPPSC AE-2011

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

<p>■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं-</p>	गिरिश चन्द्र मुर्मू	UPSI Batch-1, 20 Dec 2017
<p>■ भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है, जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय (receipts) एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिमेदारी सौंपी गई है-</p>	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	RRB NTPC (Stage-2) 13/06/2022 (Shift-I) RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-III) UPSI Batch-3, 14 Dec 2017 RRB Group-D – 08/09/2022 (Shift-I) RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-II)

■ वह संवैधानिक पदाधिकारी जिसको 'सार्वजनिक कोष (पब्लिक पर्स) का संरक्षक' कहा जाता है—	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	UPSI 17.11.2021 Shift-III
■ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति करते हैं—	राष्ट्रपति	UPSI Batch-2, 15 Dec 2017 RRB JE - 30/05/2019 (Shift-III)
■ भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है—	एक संवैधानिक निकाय	UPSI Batch-3, 22 Dec 2017
■ भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है—	राष्ट्रपति को	UPSI Batch-1, 22 Dec 2017
■ एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है—	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को	UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ वह मामला जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच-पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया—	सत्यम कंप्यूटर्स मामला	UPSI Batch-1, 12 Dec 2017
■ एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है—	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को	UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के आडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है—	लोक लेखा समिति	UPPCS (Pre) Exam 2022
■ वह वर्ष जब एकाउंटिंग को ऑडिटिंग (लेखा परीक्षा) से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया—	1976	UP PCS (Pre) 2019
■ नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है—	संसद की	Govt. Inter College (Pravakta) 2015
■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सूजन किया गया था—	संविधान द्वारा	UPPCS (Pre.) G.S., 2012
■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का कार्यकाल होता है—	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो	UPPSC Food & Sanitary Inspector Exam, 2013 UPPCS (Pre.) G.S., 1993 RRB NTPC 09.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सम्बन्ध में सही नहीं है—	उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं	U.P. PSC Kanoongo Exam 2015
■ लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है—	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को	UPPCS (Main) G.S. II nd 2008
■ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है—	लोक लेखा समिति	UPPCS (Main) G.S. II nd 2006
■ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है—	संसद की	UP RO/ARO (Main) G.S., 2014
■ भारत में, केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी होती है—	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की	SSC CGL (Tier-II) – 06/03/2023
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 _____ के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है—	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	SSC CGL (Tier-II) – 06/03/2023
■ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 _____ से संबंधित है—	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां	SSC MTS/Havaldar-01/09/2023 (Shift-I)
■ भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है—	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	SSC CGL (Tier-I) – 14/07/2023 (Shift-I)
■ भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना वर्ष में हुई थी—	1858	SSC MTS 27/10/2021 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है—	अनुच्छेद 148	SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I)-2019 – 07/03/2020 (Shift-II)

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग

■ “अखिल भारतीय सेवा” नहीं है—	भारतीय विदेश सेवा	UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ एक “अखिल भारतीय सेवा” है—	भारतीय वन सेवा	UPSI 22.11.2021 Shift-II UPSI 12.11.2021 Shift-I

■ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को पूरा किया जाता है-	भारत के समेकित कोष से	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ संघ लोक सेवा आयोगके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी ज़रूरत (ज़रूरतों) को पूरा करता है-	राज्य के राज्यपाल	UPSI 15.11.2021 Shift-III UPSI 14.11.2021 Shift-I
■ सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है जैसे-		UPSI 14.11.2021 Shift-I
1. बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी		
2. एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी		
3. व्यापार रहस्य (ट्रेड सीक्रेट)		
4. भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना		
■ भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं-	भाग XIV	UPSI 13.11.2021 Shift-I
■ संसद द्वारा “अखिल भारतीय सेवा अधिनियम” अधिनियमित किया गया था-	सन् 1951 में	UPSI 20.11.2021 Shift-III
■ वह विधि जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती नहीं करता है-	मंत्रीय सिफारिशें	UPSI Batch-3, 22 Dec 2017
■ अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण करती है-	केन्द्र सरकार	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है-	राज्यपाल	UPSI Batch-2, 15 Dec 2017 UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ ‘संघ लोक सेवा आयोग’ के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है-	भारत के राष्ट्रपति	UPSI 15.11.2021 Shift-III
■ संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का “कार्यकाल” होता है-		UPSI 17.11.2021 Shift-II
6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो		
■ संविधान द्वारा भारत में वह निकाय जिसको ‘योग्यता पद्धति के प्रहरी (मेरिट पद्धति का प्रहरी)’ के रूप में माना गया है-	संघ लोक सेवा आयोग	UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है-	अनुच्छेद-317	UPPSC Mines Inspector 2022
■ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है-	उच्चतम न्यायालय की जाँच के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा	UPPCS (Pre) Exam 2021 UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ दो या दो से अधिक राज्यों के लिये एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है-	संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा	UPPCS (Pre) Exam 2022
■ किसी राज्य में सेवारत, अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिये अधिकृत है-	केन्द्र सरकार	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है-	राष्ट्रपति को	U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013 UPUDA/LDA Special (Pre) G.S. 2010
■ किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है-	भारत के राष्ट्रपति	UP RO/ARO (Main) G.S. 2014
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं-	राज्य की संचित निधि पर	UPPCS (Pre.) G.S., 2010
■ अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा-श्रेणियाँ हैं-	3	UPPSC Asstt. Forest Conservator Exam, 2015
■ ‘अखिल भारतीय सेवाओं के जनक’ के रूप में जाना जाता है—सरदार वल्लभभाई पटेल को		UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था—	01-10-1926 को	SSC JE Electrical 10.12.2020 (Shift-II)

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग

■ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी-	सन् 1993 में	UPSI 20.11.2021 Shift-I
■ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है-	भारत के राष्ट्रपति	UPSI 21.11.2021 Shift-III UPSI 17.11.2021 Shift-II
■ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक-	संवैधानिक निकाय	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया-	नागालैंड	UPPSC Ayurvedacharya 2022
■ भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में से निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित है-	असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम	UPPCS (Main) G.S. IInd 2016
■ जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह है-	भारत का राष्ट्रपति	U.P.P.C.S. (J) 2003

भारत का महान्यायवादी

■ भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं-	भारत के महान्यायवादी (एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया)	UPSSSC Assit.Boring Technician 3-7-2022 RRB NTPC 18.01.2021 (Shift-II) Stage Ist ग्राम पंचायत अधिकारी - 04-12-2016 UPSI 13.11.2021 Shift-I RRB NTPC 08.04.2021 (Shift-II) Stage Ist जूनियर इंजीनियर/तकनीकी- 31-07-2016 SSC JE Civil - 23/01/2018 (Shift-II) SSC CHSL (Tier-1) - 15/03/2023 (Shift-III) SSC MTS- 12/05/2023 (Shift-III) SSC GD 17/11/2021 (Shift-II) SSC CHSL (Tier-1) – 21/03/2023 (Shift-II)
■ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी (एटॉर्नी जनरल) थे-	मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-III)
■ भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी (law officer) होता है-	भारत के अटॉर्नी जनरल	RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं-	अनुच्छेद- 76	RRB Group- D – 11/10/2022 (Shift-II) RRB NTPC (Stage-2) 15/06/2022 (Shift-III)
■ भारत के 15वें महान्यायवादी के के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार मिला-	वर्ष 2020 में	RRB Group-D – 17/08/2022 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी (एटॉर्नी-जनरल) के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, जो होने के लिए पात्र हो-	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त	RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्य-काल होता है-	अनिश्चित	RRB Group-D 15-11-2018 (Shift-II) UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ वह विधि अधिकारी जिसके पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है-	महान्यायवादी (एटॉर्नी जनरल)	RRB JE - 30/05/2019 (Shift-III)
■ भारत के अटॉर्नी जनरल थे-	के.के. वेणुगोपाल	RRB Group-D 11-10-2018 (Shift-II)
■ भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार है-	भारत के राष्ट्रपति के पास	UPSI 16.11.2021 Shift-II
■ लोक सभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है-	महान्यायवादी को	UPSI, 2001
■ भारत का 16वाँ महान्यायवादी नियुक्त किया गया है-	आर.वेंकटरमणी को	UPPSC Ayurvedacharya 2022
■ वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त धारण करता है-	भारत का महान्यायवादी	U.P.P.C.S. (J) 2003

राज्य का महाधिवक्ता

■ विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार होता है-	महाधिवक्ता के पास	RRB Group-D 22/08/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है— राज्य के महाधिवक्ता		RRB Group-D – 27/09/2022 (Shift-III)
■ 1983 में भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था— सरकारिया आयोग		RRB Group-D 27-11-2018 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है— अनुच्छेद 165		UPSI 22.11.2021 Shift-III
■ राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है— राज्य के महाधिवक्ता के पास		UPSI 16.11.2021 Shift-II UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति होती है— राज्य के राज्यपाल के पास		UPSI 14.11.2021 Shift-II
■ भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है— महाधिवक्ता की		UPP Constable, 19.06.2018 (Shift-2)
■ वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्प्रीति होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है परन्तु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है— भारत के महाधिवक्ता को		BEO Exam 2003
■ राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है— महाधिवक्ता		UPPCS (Main) G.S. II nd 2014
■ भारत में, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है— राज्य का राज्यपाल		SSC CGL (Tier-II) – 07/03/2023

राजभाषा एवं सेवाएँ

■ वह भाषा जो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, (मार्च, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार)— राजस्थानी		RRB NTPC (Stage-2) 17/06/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी— अनुच्छेद 343 (1)		RRB Group-D : 23/08/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-II) RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-III) RRB NTPC 21.01.2021 (Shift-I) Stage 1st RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है— अवधीं भाषा का		RRB Group-D : 30/08/2022 (Shift -I)
■ वह भाषा जिसको 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था— सिंधी		RRB Group-D – 01/09/2022 (Shift-I)
■ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था— वर्ष 2004 में		RRB Group-D – 22/09/2022 (Shift-I)
■ प्रारंभ में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया था— 14		RRB Group-D – 16/09/2022 (Shift-II)
■ राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था— 1963 में		RRB Group-D – 18/09/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 18/08/2022 (Shift-II)
■ 30 जून 2022 तक, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, भारत में आधिकारिक भाषाएं हैं— 22		RRB Group-D – 07/10/2022 (Shift-III) RRB Group-D – 19/09/2022 (Shift-II) RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-II) Stage 1st RRB NTPC 21.01.2021 (Shift-I) Stage 1st RRB Group-D 06-12-2018 (Shift-III) RRB NTPC Stage I st 28.04.2016 (Shift-I) RRB NTPC 24.07.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है— संस्कृत		RRB Group-D – 02/09/2022 (Shift-III)
■ आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है— तेलुगू		RRB Group-D – 28/09/2022 (Shift-II)

■ गोवा की राजभाषा है-	कोंकणी	RRB Group-D – 15/09/2022 (Shift-I) RRB NTPC Stage I st 27.04.2016 (Shift-II)
■ तेलंगाना की दूसरी राजभाषा है-	उर्दू	RRB Group-D – 27/09/2022 (Shift-I)
■ संविधान के अनुच्छेद 348 (1) के अनुसार, भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए उपयोग किया जाता है-	अंग्रेजी भाषा का	RRB NTPC 11.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है-	गढ़वाली भाषा को	RRB NTPC 27.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB Group-D 06-12-2018 (Shift-III)
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है-	अनुच्छेद 343 (1)	RRB NTPC 14.03.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 05.04.2016 (Shift-II) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था-	15 वर्ष	RRB NTPC 11.03.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु याद किया जाता है-	पुरुषोत्तम दास टंडन	RRB NTPC 17.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है-	VIII	RRB Group-D 10-12-2018 (Shift-I)
■ केरल की राज्य भाषा है-	मलयालम	RRB Group-D 29-10-2018 (Shift-III)
■ नागालैंड की राजकीय भाषा है-	अंग्रेजी	RRB NTPC Stage I st 26.04.2016 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है-	अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा	UPPCS (Pre) 2018
■ भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में सही है-	बोडो संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है	UPPCS (Main) G.S. II nd 2016
■ संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है-	उत्तराखण्ड में	UPPCS (Pre.) G.S. 2011
■ संविधान की आठवीं अनुसूची में समिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाले हैं-	बंगाली	UPPCS (Pre.) G.S. 1998
■ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है-	अठारह (वर्तमान में 22 भाषायें हैं)	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper, 2004
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था-	वर्ष 1955 में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में	UPPCS (Pre.) G.S. 1998

प्रमुख आयोग/समिति एवं संवैधानिक संस्थायें

■ केन्द्र-राज्य संबंधों पर, भारत सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था-	वर्ष 1983 में	RRB NTPC (Stage-2) 16/06/2022 (Shift-I) UPP Constable (Main), 2014 RRB Group-D – 17/09/2022 (Shift-I) SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-I)
■ अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की अनुशंसा पर की गई थी—सरकारिया समिति		SSC MTS 08/08/2019 (Shift-III)
■ भारत में पहली बार प्राकलन समिति का गठन वर्ष में किया गया था—	1950	SSC CGL (Tier-II) – 02/03/2023
■ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है—	अनुच्छेद 317	SSC Selection Posts XI– 27/06/2023 (Shift-IV)
■ वर्ष 2022 में, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था—	जस्टिस ऋतुराज अवस्थी	SSC CGL (Tier-1) – 20/07/2023 (Shift-I)
■ भारत के पद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे—	एन.के. सिंह	SSC CGL (Tier-1) – 21/07/2023 (Shift-IV)
■ भारत के संविधान में अनुच्छेद _____ की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCBC) का गठन किया गया था—	338B	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 05/03/2020 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद _____ में कहा गया है कि ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा’—	338B (1)	SSC CGL (Tier-I) 19/04/2022 (Shift-III)

■ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष _____ में बदल दिया गया था-	2018	SSC GD 17/11/2021 (Shift-III)
■ भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है-	पाँच	SSC MTS 20/10/2021 (Shift-III)
■ भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए संविधान द्वारा संस्था अनिवार्य है-	वित्त आयोग	SSC Stenographer – 11/11/2021:Shift-II
■ ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी-	मंडल आयोग	SSC MTS 07/10/2021 (Shift-I)
■ संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है-	65	SSC MTS 11/10/2021 (Shift-III)
■ 1990 में, विषय पर सिफारिशें देने के लिए, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था-	चुनावी सुधार	SSC MTS 20/10/2021 (Shift-I)
■ भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है-	अनुच्छेद 320	SSC MTS 20/10/2021 (Shift-II)
■ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था-	2004	SSC MTS 22/10/2021 (Shift-I)
■ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है-	6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो	SSC CHSL 12/04/2021 (Shift-III)
■ लोक लेखा समिति के सदस्यों को की अवधि के लिए चुना जाता है-	एक वर्ष	SSC CHSL 25/05/2022 (Shift-I)
■ पी.के. थुग्न समिति संबंधित है-	पंचायती राज	SSC JE Civil 30.10.2020 (Shift-II)
■ पुंछी आयोग किससे संबंधित है-	केन्द्र – राज्य संबंध	SSC JE Civil 11.12.2020 (Shift-II)
■ भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व ने किया था-	काका कालेलकर	SSC CHSL 20/10/2020 (Shift-III)
■ भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को के तहत, संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है-	अनुच्छेद 312	SSC CPO-SI – 12/12/2019 (Shift-I)
■ भारतीय संविधान के इकहतरवें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है-	आठवीं	SSC CHSL (Tier-I) – 17/03/2023 (Shift-II)
■ हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है-	अनुच्छेद 343	SSC CHSL (Tier-I) – 15/03/2023 (Shift-I) SSC MTS 05/08/2019 (Shift-I)
■ भारत के संविधान के में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी-	अनुच्छेद 343 (1)	SSC MTS 27/10/2021 (Shift-I) SSC MTS 22/10/2021 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान के ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया-अनुच्छेद 343 (3)		SSC MTS 07/10/2021 (Shift-II)
■ भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी-	तमिल	SSC MTS 08/10/2021 (Shift-II)
■ डोगरी भाषा प्रमुख रूप से राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में बोली जाती है-	जम्मू और कश्मीर	SSC CHSL (Tier-I) – 09/07/2019 (Shift-II) SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-III)
■ में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं-	अनुच्छेद 347	SSC CGL (Tier-I)-2019 – 05/03/2020 (Shift-III)

गैर-संविधानिक निकाय (Non-Constitutional Body)

योजना आयोग/नीति आयोग

■ “योजना आयोग” के स्थान पर वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा गठित किया गया है-	नीति आयोग	बन रक्षक - 11-12-2015 RRB NTPC 08.02.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB Group-D 10-12-2018 (Shift-III) RRB NTPC 18.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
---	-----------	--

■ एक संवैधानिक संस्था नहीं थी-	योजना आयोग	लोअर द्वितीय- 06-03-2016
■ नीति आयोग का अध्यक्ष होता है-	प्रधानमंत्री	लोअर द्वितीय - 15-07-2018 RRB NTPC 28.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था-	वर्ष 1950 में	RRB JE - 27/05/2019 (Shift-II) RRB NTPC 02.02.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 29.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB NTPC 14.03.2021 (Shift-II) Stage Ist UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ NITI आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था-	1 जनवरी	RRB NTPC 13.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत की केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को भंग किया गया था-	वर्ष 2014 में	RRB NTPC 03.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ नीति (NITI) आयोग के पहले अध्यक्ष थे-	नरेन्द्र मोदी	RRB Group-D 18-09-2018 (Shift-III) RRB NTPC 10.01.2021 (Shift-I) Stage Ist RRB NTPC 03.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे-	राजीव कुमार	RRB NTPC 01.02.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB Group-D 12-10-2018 (Shift-III)
■ नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा वूमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स शुरू किए गए थे-	वर्ष 2016 में	RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ नीति (NITI) आयोग का मुख्यालय स्थित है-	नई दिल्ली में	RRB Group-D 27-11-2018 (Shift-I)
■ अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है-	नीति आयोग	RRB JE - 26/05/2019 (Shift-II)
■ योजना आयोग (Planning Commission) के पहले अध्यक्ष थे-	जवाहरलाल नेहरू	RRB JE - 27/06/2019 (Shift-I)
■ हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन (GES - 2017) का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति (NITI) का पूर्ण रूप है-	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया	RRB Group-D 22-09-2018 (Shift-I)
■ भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित हुई थी-	वर्ष 1952 में	RRB JE - 24/05/2019 (Shift-II)
■ वह संस्थान जिसने 'इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफार्म इकोनॉमी' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की-	नीति आयोग	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2
■ नीति आयोग, योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था-	सन् 2015 में	UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है-	मुख्यमंत्री	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper-I
■ नीति आयोग द्वारा दिसम्बर 2019 में जारी 'सत्रृ विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20'	अच्छा प्रदर्शन (परफार्मर) वर्ग में	UP PSC (Pre) 2020
पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है-		
■ अशोक चन्द्रा द्वारा भारत में 'आर्थिक मंत्रिपरिषद' कहा गया-	योजना आयोग को	UPPCS (Pre) 2018
■ एक संविधानेतर संस्थान है-	नीति आयोग	UPPCS (Pre) 2018
■ भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई-	संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से	RO ARO GS Mains Re-exam 2016
■ केन्द्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है-	राष्ट्रीय विकास परिषद	UPPCS GDC 2012
■ संवैधानिक संस्था नहीं है-	योजना आयोग	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष हैं-	प्रधानमंत्री	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ एक संवैधानिक निकाय नहीं है-	योजना आयोग	UPPCS (Pre.) G.S. 2013
■ योजना आयोग का अंत किया-	नरेन्द्र मोदी ने	UPPCS (Pre.) G.S. 2015
■ भारत में एक समय के लिये योजना अवकाश की अधिकतम अवधि थी-	3 वर्ष	UPPSC AE- 2007 Paper (I)
■ एक संविधान का अंग नहीं है-	योजना आयोग	UPPSC AE-2008
■ नीति (NITI) आयोग अस्तित्व में आया-	वर्ष 2015	SSC CHSL 21/10/2020 (Shift-II)

राष्ट्रीय विकास परिषद

■ “राष्ट्रीय एकता परिषद” की पहली बैठक आयोजित की गई थी—	सन् 1962 में	UPSI 16.11.2021 Shift-II
■ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था—	1952 ई. में	UPPCS RO/ARO (Mains) 2021 UPPSC Polytechnic Lecturer 2021 UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II RRB Group-D 25-09-2018 (Shift-II)
■ राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य सम्बन्ध होता है— पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से		UPPCS (Pre.) G.S. 2001
■ राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना एवं राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशानिर्देश प्रदान करना यह कार्य है—		UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2010 UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2005
	राष्ट्रीय विकास परिषद	
■ राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का अध्यक्ष होता है—	भारत के प्रधानमंत्री	RRB NTPC 06.04.2021 (Shift-II) Stage Ist

राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग

■ मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था—	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ ‘राज्य मानवाधिकार आयोग’ के अध्यक्ष’ और सदस्यों की नियुक्ति करता है—	राज्य के राज्यपाल	UPSI 13.11.2021 Shift-II
■ वह अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जिसको सभी मानव जाति के लिए ‘अंतर्राष्ट्रीय मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है—	मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र	UPSI 14.11.2021 Shift-I UPSI 22.11.2021 Shift-III
■ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 में अनुच्छेद है—	30	UPSI 21.11.2021 Shift-I
■ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) की स्थापना हुई थी—	सन् 1993 में	UPSI 17.11.2021 Shift-III UPP Constable, 18.06.2018 (Shift-1)
■ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति है—	भारत के राष्ट्रपति के पास	UPSI 17.11.2021 Shift-I UPSI 12.11.2021 Shift-II
■ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु है—	70 वर्ष	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे—	न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ “मानवाधिकार दिवस” 2020 का विषय था—	बेहतर पुनर्प्राप्ति-मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ	UPSI 12.11.2021 Shift-III
■ एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है—	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	UPSI Batch-1, 16 Dec 2017
■ नवंबर 2018 में, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं—	न्यायमूर्ति एम. रफत आलम	(UP SI/ ASI 2018)
■ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है—	10 दिसम्बर	(UP SI/ ASI 2018)
■ संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघिय जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना—	विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधिपत्र	UPSI Batch-1, 20 Dec 2017
■ मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे—	एलेनोर रोसवेल्ट	UPSI Batch-1, 19 Dec 2017
■ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है—	गुलामी से स्वतंत्रता	UPP Constable, 19.06.2018 (Shift-1)
■ वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा [Universal Declaration of Human Rights (UDHR)] का वैधानिक स्वरूप है—	संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव	UPP Constable (Main), 2014
■ राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है—	उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश	UPP Constable (Main), 2014
■ मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन (अंतर्राष्ट्रीय) देश में आयोजित किया गया था—	तेहरान	UPSI (Mains), 2014
■ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है—	उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश (अन्य न्यायाधीश भी)	UPSI (Mains), 2014 UPPSC AE- 2007 Paper (II)

■ थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिये आप प्रकार कार्य करेंगे— उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे	UPSI (Ranker), 2011
■ केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है— प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ एक संवैधानिक संस्था नहीं है— मानवाधिकार आयोग	UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2007
■ मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है— मानव होने के नाते मानव गरिमा पर	UPPCS (Main) G.S. IInd Paper 2014

केन्द्रीय एवं राज्य सूचना आयोग

■ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है— राज्य के राज्यपाल के पास	UPSI 12.11.2021 Shift-I
■ एक संवैधानिक निकाय नहीं है— राज्य सूचना आयोग	UPSI 17.11.2021 Shift-I
■ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी— सन् 2005 में	UPSI 20.11.2021 Shift-III UPSI 21.11.2021 Shift-III
■ सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में सही कथन है— यह एक विधिक अधिकार है	UPPCS (Pre.) G.S. 2015
■ सूचना का अधिकार अधिनियम _____ सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है— 2005	SSC CGL (Tier-I) 19/04/2022 (Shift-I)
■ सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था— अक्टूबर, 2005 में	RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-I) Stage I st RRB Group-D 11-12-2018 (Shift-II) RRB NTPC 29.03.2016 (Shift-III) Stage I st SSC JE CIVIL 10/10/2023 (Shift-I)

लोकपाल एवं लोकायुक्त

■ “लोकपाल” एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में जिसका अर्थ है— लोगों की देखभाल करने वाला	UPSI Batch-3, 12 Dec 2017
■ 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे— परमाणु ऊर्जा उत्पादन	UPSSSC PET 15.10.2022 Shift-2
■ “लोकपाल बिल” पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे— प्रणब मुखर्जी	UPSI Batch-2, 13 Dec 2017
■ सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी— महाराष्ट्र	UPPCS (Pre.) Re-exam G.S. 2015
■ भारत के पहले लोकपाल बने— पिनाकी चन्द्र घोष	SSC CHSL 04/08/2021 (Shift-I) SSC CGL (Tier-I) – 19/06/2019 (Shift-III)
■ भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पारित किया गया था— लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम	SSC MTS 11/10/2021 (Shift-II)
■ पहला ‘लोकपाल विधेयक’ भारत की संसद में पेश किया गया था— 1968 में	RRB Group-D 16-11-2018 (Shift-I)

विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग

■ “राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016” के प्रस्तावित मसौदे में शामिल नहीं है— आचमन युक्त धारा	RRB Group-D 01-10-2018 (Shift-II)
■ प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई— 2002 में	लोअर द्वितीय - 06-03-2016
■ कारगिल समस्याओं पर बैठायी गई जांच समिति थी— के. सुब्रमण्यम समिति	UPSI, 1999
■ भारत में अंतर-राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं— भारत के प्रधानमंत्री	UPSI 15.11.2021 Shift-II
■ वह प्राधिकरण जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है— भारत के राष्ट्रपति	UPSI 21.11.2021 Shift-II UPSI 14.11.2021 Shift-II
■ ‘राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम’ अधिनियमित किया गया था— सन् 2008 में	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ भारत में एक वैधानिक निकाय है— राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	UPSI 16.11.2021 Shift-III
■ भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किया था— वीरप्पा मोइली ने	UPSI 20.11.2021 Shift-II
■ गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो की स्थापना की गई थी— सन् 1963 में	UPSI 20.11.2021 Shift-II

■ सरकारिया आयोग स्थापित किया गया था-	केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु	UPPCS (Pre.) G.S. 2016
■ संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं-	न्यायमूर्ति बैंकटचेलैया	UPPCS (Main) G.S. 2002 BPSC (Pre.) G.S. 2002
■ उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है-	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	U.P. PSC Kanoongo Exam 2015
■ राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं पंचायत हैं-	संवैधानिक प्राधिकरण	UPPCS (Main) G.S. Hind Paper 2012
■ भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ-	1993 ई. में	UPPSC AE-2013
■ स्वतंत्रता के बाद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था-	6 अगस्त, 1952	SSC JE Civil 29.10.2020 (Shift-I)
■ भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था-	वर्ष 1979 में	SSC JE Mechanical 27.10.2020 (Shift-I)
■ 1979 में 'द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग' की अध्यक्षता _____ के द्वारा की गई थी-	बी.पी. मंडल	SSC MTS 08/10/2021 (Shift-III)
■ वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी-	जनता दल पार्टी की सरकार ने	SSC MTS 02/08/2019 (Shift-I)
■ भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँगों का अध्ययन करने के लिए, 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे-	एस. के. धर	SSC JE Civil - 23/09/2019 (Shift-II)
■ न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था-	भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति	SSC CHSL (Tier-I) -11/07/2019 (Shift-I)

राजनीतिक गतिशीलता (Political Dynamics)

राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता

■ एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और ये सदस्य कम से कम तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं-	राज्य मण्डी परिषद - 30-05-2019 (Shift-I) 11 सीटें
■ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी-	वर्ष 1980 में
■ भारत में प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है-	बहु-दलीय प्रणाली
■ जो पार्टी लोकसभा चुनावों में या चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों में से कम से कम 6 प्रतिशत वोट हासिल करती है, और लोकसभा में कम से कम चार सीटें जीतती है, उसे-	राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है
■ तमிலनாடு राज्य एवं पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी-	AIADMK
■ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे-	मानवेंद्र नाथ रॉय
■ राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी-	कांशीराम ने
■ बहुजन समाज पार्टी को के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है-	हाथी
■ मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के संस्थापक थे-	लाल डेंगा
■ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से पार्टी का चुनाव चिह्न घड़ी है-	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
■ राजनीतिक दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी का नेतृत्व करते हैं-	विजय सरदेसाई

■ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिह्न है-	मर्कें और हंसिया	RRB Group-D 28-09-2018 (Shift-I) RRB Group-D 28-09-2018 (Shift-III) RRB Group-D 15-10-2018 (Shift-III)
■ अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है-	पंजाब	RRB Group-D 26-10-2018 (Shift-II)
■ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) का नेता है-	सीताराम येचुरी	RRB Group-D 11-12-2018 (Shift-II)
■ महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है-	शिवसेना	RRB Group-D 11-12-2018 (Shift-II)
■ एन.टी.रामा राव ने तेलुगू देशम पार्टी स्थापित की थी-	29 मार्च 1982 को	RRB Group-D 24-10-2018 (Shift-II)
■ कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव राजनीतिक दल के नेता हैं-	तेलंगाना राष्ट्र समिति	RRB Group-D 22-10-2018 (Shift-III)
■ राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है-	वाम-पंथी	RRB Group-D 22-10-2018 (Shift-II)
■ वह भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल जिसका नेतृत्व एन. चंद्रबाबू नायडू करते हैं-	तेलुगू देशम पार्टी	RRB Group-D 22-10-2018 (Shift-II)
■ आंध्र प्रदेश राज्य की राजनीतिक पार्टी है-	तेलुगू देशम पार्टी	RRB Group-D 07-12-2018 (Shift-I)
■ वह राजनीतिक पार्टी जो तेलुगू अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गयी, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गयी- प्रजा राज्यम पार्टी (Praja Rajyam Party)		RRB ALP & Tec. (10-08-18 Shift-I)
■ राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी-	जनता पार्टी	RRB Group-D 16-10-2018 (Shift-II)
■ पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल सत्ता में है-	तृणमूल कांग्रेस	RRB Group-D 05-12-2018 (Shift-III)
■ भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं-	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस	RRB Group-D 15-10-2018 (Shift-I)
■ भारतीय राज्य के राजनीतिक दल केरल कांग्रेस (एम) का नेतृत्व किया है- सी.एफ. थॉमस ने		RRB Group-D 30-10-2018 (Shift-II)
■ बीजू जनता दल भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है-	ओडिशा	RRB Group-D 30-10-2018 (Shift-II)
■ भारतीय राजनीतिक गठबंधन, (NDA) का पूर्ण रूप है-	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन	RRB Group-D 29-10-2018 (Shift-III)
■ राज्य स्तरीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का नेतृत्व करते हैं-	ई. मधुसूदन	RRB Group-D 16-10-2018 (Shift-I)
■ भारतीय राजनीतिक दल जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं-	उमर अब्दुल्ला	RRB Group-D 19-09-2018 (Shift-II)
■ आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था-	वर्ष 2012 में	RRB NTPC 16.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की स्थापना की-	सी.एन. अन्नादुर्रई ने	RRB NTPC 28.03.2016 (Shift-II) Stage I st
■ राजनीतिक नेता नवीन पटनायक भारतीय राज्य से सम्बन्धित हैं-	ओडिशा	RRB Group-D 31-10-2018 (Shift-I)
■ राजनीतिक नेता नीतीश कुमार भारतीय राज्य से हैं-	बिहार	RRB Group-D 30-10-2018 (Shift-III)
■ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया-	सन् 1925 में	UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की-	सन् 1979 में	UPSI 16.11.2021 Shift-III SSC GD 22/11/2021 (Shift-I)
■ राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली-	1985 में	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है, कम से कम-	चार राज्यों में	UPPCS (Pre.) G.S. 2000
■ क्षेत्रीय राजनीतिक दल है-	अकाली दल	UPPCS Spl. (Pre) G.S. 2008
■ लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए-	55 सदस्य	UPPCS (Pre.) G.S. 2006
■ केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था-	1957 में	UP RO/ARO (Main) G.S. 2014

<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>सूची-I (राजनीतिक दल)</p> <p>(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (B) भारतीय जनता पार्टी (C) बहुजन समाज पार्टी (D) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (E) तृणमूल कांग्रेस</p>	<p>सूची-II (स्थापना वर्ष)</p> <p>(i) 1885 (ii) 1980 (iii) 1984 (iv) 1964 (v) 1998</p>	RRB NTPC 23.07.2021 (Shift-I) Stage Ist
<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>सूची-I (राजनैतिक दल)</p> <p>तेलुगू देशम पार्टी बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस</p>	<p>सूची-II (स्थापना का वर्ष)</p> <p>1982 1984 1992 1998</p>	UPPCS (Pre) Exam 2022

दल परिवर्तन कानून

<p>■ भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 'दलबदल विरोधी' कानून के प्रावधान शामिल हैं-</p> <p style="text-align: center;">दसवीं अनुसूची</p>	UPSI 13.11.2021 Shift-I BEO exam-2006 (I) UPPSC Asstt. Forest Conservator Exam 2015	
<p>■ दल-बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय.....के मामले में सही ठहराया था-</p> <p style="text-align: center;">किहोता होलोहन बनाम जाचिल्हू</p>	UPSI 17.11.2021 Shift-II	
<p>■ दल-बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि है- 15 फरवरी, 1985</p>	UPPCS Spl. (Pre.) G.S. 2008	
<p>■ एक दल-बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है-</p> <p style="text-align: center;">किसी दल में एक साथ पूर्ण दल-बदल</p>	UPPCS (Main) G.S. IInd 2010	
<p>■ चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को _____ कहा जाता है-</p> <p style="text-align: center;">राजनीतिक दल</p>	SSC GD – 06/02/2023 (Shift-III)	
<p>■ 1977 में जगजीवन राम ने राजनीतिक दल की स्थापना की थी, जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया-</p> <p style="text-align: center;">कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी</p>	SSC JE Mechanical – 23/03/2021 (Shift-II)	
<p>■ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M) का गठन वर्ष में किया गया था- 1964</p>	SSC MTS 18/10/2021 (Shift-III)	
<p>■ भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है-</p> <p style="text-align: center;">भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस</p>	SSC GD 03/03/2019 (Shift-I)	
<p>■ भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति _____ द्वारा स्थापित भारतीय जन संघ में निहित है-</p> <p style="text-align: center;">श्यामा प्रसाद मुखर्जी</p>	SSC GD 12/02/2019 (Shift-III)	
<p>■ सही सुमेलन है-</p> <p>सूची-I हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम सती प्रथा निषेध अधिनियम हिन्दू विवाह अधिनियम</p>	<p>सूची-II</p> <p>1956 2019 1987 1955</p>	UPPCS (J) 2023

विविध

<p>■ राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक (National Anti-Doping Bill), 2021 भारत के _____ क्षेत्र को लक्षित करता है-</p> <p style="text-align: center;">खेल</p>	SSC MTS– 19/05/2023 (Shift-III)
<p>■ भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 भारत के _____ मंत्रालय से संबंधित है- पृथ्वी विज्ञान</p>	SSC MTS – 15/05/2023 (Shift-I)
<p>■ के अनुसार, बेटे, बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है-</p> <p style="text-align: center;">हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005</p>	SSC GD 30/11/2021 (Shift-I)
<p>■ न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था-</p> <p style="text-align: center;">संयुक्त राज्य अमेरिका में</p>	SSC JE Civil - 23/01/2018 (Shift-II)

■ देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई-	अमेरिका	SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-I)
■ भारत में वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था-		RRB Group-D 12-11-2018 (Shift-II)
2006		
■ दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की विशेषताओं में से एक वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचानकर घर खरीदारों को राहत है-		RRB Group-D 26-09-2018 (Shift-II)
■ केन्द्रीय सर्वकाता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है-	4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु	लोअर त्रितीय - 26-06-2016
■ आर्थिक आसूचना परिषद् (ई. आइ. सी.) के अध्यक्ष होते हैं-	वित्त मंत्री	कनिष्ठ सहायक - 24-04-2016
■ भारत के संविधान में 'जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता' शामिल है-	राज्य सूची में	UPSSSC PET 24/08/2021 Sift-I
■ भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था-	1954	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-II
■ NFWP का तात्पर्य है-	नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम	UPSSSC Lower Mains 21/10/2021 Paper-I
■ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के काम की जाँच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके-	1993	UPSSSC Junior Assistant 04/01/2020 Shift-II
■ भारत की संसद द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम लागू किया गया-	सन् 1955 में	Lower-II (Re-exam) (28-07-2019)
■ कैबिनेट स्तर का होता है-	विपक्ष का नेता	राजस्व लेखपाल - 13-09-2015 (Morning)
■ भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसीए) के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है-	1988	विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift- I)
■ मानसिक 'विक्षिप्ति' भारतीय दण्ड संहिता के धारा में सन्तुष्टि है-	धारा 84	कनिष्ठ सहायक - 24-04-2016
■ घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम लागू किया गया-	वर्ष 2006 में	स्टेनोग्राफर - 26-07-2015
■ केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में को की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया-	शैल; पेट्रोलियम	विधान भवन रक्षक - 02-12-2018 (shift- I)
■ केन्द्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है-	रक्षा व्यय	राजस्व लेखपाल - 13-09-2015 (Morning)
■ 'परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है', यह कथन है-	अरस्तू का	लोअर प्रथम- 28-02-2016
■ हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में से प्रतिबंधित किया गया है-		अमीन परिक्षा- 14-08-2016 (Paper-I)
	1993	
■ हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून (हरियाणा संशोधन) 2018, विधेयक पारित किया, जो साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है-	व्यायाम प्रशिक्षक - 16-09-2018 (Shift-I)	
	12	
■ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) का गठन 31 अगस्त 2005 कोकी अध्यक्षता में जाँच आयोग के रूप में किया गया था-	वीरप्पा मोइली	राज्य मण्डी परिषद् - 30-05-2019 (Shift - II)
■ 'राइटर्स बिल्डिंग' भारत की राज्य सरकार का सचिवालय भवन है-	पश्चिम बंगाल सरकार	Lower Exam – 30-09-2019 (Shift-II)
■ नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है-	विधानमण्डल	ग्राम पंचायत अधिकारी - 04-12-2016
■ भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है-	सामंतशाही को प्रोत्साहन	RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-III)
■ प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजिए (Le Corbusier) द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधान सभा स्थित है-	चंडीगढ़ में	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-II)
■ केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाएगा-	26 नवंबर	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-II)
■ 1960 में, तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था-	गुजरात	RRB NTPC (Stage-2) 12/06/2022 (Shift-II)

■ मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (MANUU) एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था-	1998 में	RRB Group-D – 12/09/2022 (Shift-II)
■ भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालानुक्रम है—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम		RRB Group-D – 30/09/2022 (Shift-I)
■ भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था—	वर्ष 1950 में	RRB Group-D – 18/08/02022 (Shift-III)
■ त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम, 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए—		RRB Group-D – 18/08/02022 (Shift-III)
बंगाली और कोकबोरोक		
■ भारत के वह प्रधानमंत्री जिसके मंत्रिमंडल में डॉ. मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने—	पीवी नरसिंहा राव	RRB Group- D – 14/09/2022 (Shift-I)
■ भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है—	सरदार वल्लभ भाई पटेल	RRB Group- D – 27/09/2022 (Shift-II)
■ भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे—	जगजीवन राम	RRB Group-D – 26/08/2022 (Shift-I) RRB Group-D – 26/09/2022 (Shift-I)
■ वह भाषा जो द्रविड़ भाषा परिवार की चार सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है—	संस्कृत	RRB Group-D – 23/08/2022 (Shift-II)
■ तमिलनाडु की आधिकारिक और प्रमुख भाषा तमिल का संबंध भाषा परिवार से है—	द्रविड़	RRB Group-D – 05/09/2022 (Shift-I)
■ वह भारतीय भाषा जिसको सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा/राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है—	तमिल	RRB Group-D – 25/08/2022 (Shift-I)
■ भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था—	वर्ष 1910 में	RRB Group-D – 17/08/2022 (Shift-II)
■ भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले, भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रति वर्ष तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है—	26 जनवरी	RRB Group-D – 17/08/2022 (Shift-III)
■ वह भारतीय राज्य जिसकी आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा ‘कोकबोरोक’ है—	त्रिपुरा	RRB Group- D – 09/09/2022 (Shift-I)
■ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है—		RRB Group-D – 06/09/2022 (Shift-I)
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC)		
■ लोकसभा में परिवार न्यायालय के (संशोधन) विधेयक पारित किया गया—	जुलाई 2022 में	RRB Group-D –05/09/2022 (Shift-III)
■ दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था—	1954 में	RRB Group-D – 29/09/2022 (Shift-II)
■ द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है—	मराठी	RRB NTPC Stage I st 30.04.2016 (Shift-III)
■ गाँधी सृति एवं दर्शन समिति (GSDS) का गठन किया गया था—	सितम्बर, 1984 में	RRB NTPC 04.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी—	मई, 2016 में	RRB NTPC 09.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ वे कर जो केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं—	वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क	RRB NTPC 10.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा, दो अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है—	राजस्थानी और अंग्रेजी	RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है—	डॉ. यशवंत सिंह परमार को	RRB NTPC 09.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम पारित किया गया था—	वर्ष 1926 में	RRB NTPC 05.04.2021 (Shift-II) Stage Ist

■ लिंचिंग (भीड़ द्वारा गैर-कानूनी तरीके से पीट-पीटकर मार डालना) के मामलों पर अंकुशश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है—	मणिपुर	RRB NTPC 29.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया था—	1973 में	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य था—	गुजरात	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत के द्वितीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है—	विजय घाट	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, कहलाती है—	संघवाद	RRB NTPC 05.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था—	15 अगस्त, 1974 को	RRB NTPC 16.02.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को कहा जाता था—	विशालांध्र आन्दोलन	RRB NTPC 05.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत में राजनीतिक शब्दावली में ‘आया राम, गया राम’ की अभिव्यक्तिकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई—	गया लाल	RRB NTPC 05.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील जिन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया—	मेनका गुरुस्वामी और अंसुधाति काटजू	RRB NTPC 07.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में ने कहा, ‘मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे।’—	गोविंद बल्लभ पंत	RRB NTPC 08.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ भारत मेंएक भ्रष्टाचार-निरोधक संस्था है, जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जाँच कर सकती है—	लोकपाल	RRB NTPC 17.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है—	विकास प्राधिकरण	RRB NTPC 18.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत में ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ का प्रकाशन करता है—	वित्त मंत्रालय	RRB NTPC 06.04.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए, शक संवत् पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था—	वर्ष 1957 से	RRB NTPC 26.07.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय दंड-संहिता (Indian Penal Code) जो 1860 में अधिनियमित हुई, का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता की थी—	लॉर्ड मैकाले ने	RRB NTPC 25.01.2021 (Shift-II) Stage Ist RRB Group-D 04-12-2018 (Shift-III)
■ भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था—	1968 में	RRB NTPC 01.02.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ ‘संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है’— यह कथन है—	डॉ. बीआर अब्बेडकर का	RRB NTPC 02.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है—	कार्यपालिका	RRB NTPC 11.01.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ एकात्मक राज्यों में, सरकार सभी सरकारी कार्य करती है—	केन्द्र	RRB NTPC 23.01.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार बनी थी—	केरल राज्य में	RRB NTPC 27.01.2021 (Shift-II) Stage Ist UPPCS (Pre) G.S. 2010
■ भारतीय अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Indian Official Secrets Act) पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया—	1904 में	RRB NTPC 07.03.2021 (Shift-I) Stage Ist
■ भारतीय संविधान के संबंध में सत्य कथन है— मौलिक अधिकार वादयोग्य होते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर-वाद योग्य होते हैं		RRB NTPC 14.03.2021 (Shift-II) Stage Ist
■ किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने से सरकार द्वारा गठन किया जाता है—	वार्ड समिति का	RRB NTPC 11.03.2021 (Shift-II) Stage Ist

■ भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी— मई 2005, जून 2005	RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-I) Stage 1st
■ भारत में दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) पारित किया गया था— वर्ष 1985 में	RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है— राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए	RRB NTPC 09.02.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारतीय संविधान में ‘लोकायुक्त’ का अर्थ है— लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की श्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है	RRB NTPC 22.02.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत की सरकार के अर्ध-संघीय रूप (quasi-federal form) का प्रावधान लिया गया था— कनाडा से	RRB NTPC 27.03.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ भारत का वह राज्य जो यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है— केरल	RRB NTPC 28.01.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की वह धारा जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर चार से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है— धारा 144	RRB NTPC 10.02.2021 (Shift-II) Stage 1st
■ वह भारतीय मुख्यमंत्री जिनके पिता ‘महाराजा’ थे— अमरिंदर सिंह	RRB ALP & Tec. (09-08-18 Shift-II)
■ वह सांविधिक कानून जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किये गये थे— भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947	RRB ALP & Tec. (09-08-18 Shift-I)
■ IPC का विस्तार है— इण्डियन पैनल कोड	RRB J.E. (14.12.2014, Green paper) RRB NTPC 07.04.2016 (Shift-II) Stage 1 st
■ धारा 66 A, हाल में, मीडिया के विवाद में था। यह धारा संबंधित है— सूचना प्रौद्योगिकी से	RRB J.E. (14.12.2014, Green paper)
■ वह राज्य जिसके द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के तीन तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया— उत्तर प्रदेश	RRB Group-D 12-10-2018 (Shift-II)
■ शिक्षा भारत सरकार के मंत्रालय का एक कार्य था— मानव संसाधन विकास	RRB Group-D 12-11-2018 (Shift-II)
■ ट्रिपल तलाक संबंधित है— तलाक से	RRB Group-D 06-12-2018 (Shift-II)
■ संघीय (फेडरल) सरकार की प्रणाली लागू नहीं है— चीन में	RRB Group-D 13-12-2018 (Shift-II)
■ वह धार्मिक समुदाय जिसको 30 जनवरी, 2014 को भारत सरकार द्वारा ‘अल्पसंख्यक’ का दर्जा दिया गया है— जैन	RRB NTPC Stage I st 28.04.2016 (Shift-II)
■ ‘गजट आफ इंडिया’ के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन (प्रश्रयदाता) हैं— कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन	RRB NTPC Stage I st 19.01.2017 (Shift-I)
■ 26 जनवरी 1950 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जिसे पूर्व में कहते थे— इरविन स्टेडियम	RRB NTPC Stage I st 19.01.2017 (Shift-I)
■ वह सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है— रेलवे सुरक्षा बल	RRB NTPC 06.04.2016 (Shift-II) Stage 1 st
■ स्वतंत्रता के समय, भारत में रजवाड़े थे— 565	RRB NTPC 12.04.2016 (Shift-III) Stage 1 st
■ स्वतंत्रता से पूर्व अनेक रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत थी— हैदराबाद	RRB NTPC 16.04.2016 (Shift-I) Stage 1 st
■ 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था— आर. के. घण्मुखम चेड़ी ने	RRB NTPC 18.04.2016 (Shift-I) Stage 1 st
■ भारत की अधिराज्य की अवधि दर्शाती है— स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक	RRB NTPC 19.04.2016 (Shift-I) Stage 1 st

■ उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है-	75	RRB Group-D 10-12-2018 (Shift-I)
■ भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे-	पिण्डिमारी वेंकट सुल्बाराव	RRB NTPC 04.04.2016 (Shift-III) Stage I st
■ भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य है-	असम	RRB ALP & Tec. (29-08-18 Shift-III) ग्राम पंचायत अधिकारी - 04-12-2016
■ वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया-	सरदार बल्लभभाई पटेल	RRB NTPC 31.03.2016 (Shift-I) Stage I st
■ वह देश जिसको मुख्य रूप से कम्युनिस्ट/माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था—	चीन	RRB Group-D 12-11-2018 (Shift-I)
■ राज्य पुनर्गठन अधिनियम.....में लागू किया गया था—	1956	RPF Constable 05/02/2019
■ “हालमार्क” लोगो का उपयोग होता है-	आभूषणों के लिए	UPSSSC PET 16.10.2022 Shift-II
■की स्थापना भारत की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी—	राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड(NATGRID)	UPSI 22.11.2021 Shift-II
■ कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित शब्द है-	प्रतिभूतिकरण	UPSI 14.11.2021 Shift-III
■ लदाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जेछप ला (Jechap La) तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है-	इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल	(UP SI/ ASI 2018)
■ नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया—	ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा	UPSI Batch-3, 15 Dec 2017
■ आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है—	पोटा	UPSI, 2001
■ को भारत, राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि, इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी—	26 जनवरी, 1950	UPSI Batch-1, 19 Dec 2017
■ ग्रैनील ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है, एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें, जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरणस्वरूप भारत—	सहकारी संघवाद	UPSI Batch-2, 15 Dec 2017
■ भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी रखी गयी—	संसद की लाइब्रेरी में	UPSI Batch-1, 15 Dec 2017
■ महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से सम्बन्धित वह अधिनियम जो पिछले दो वर्षों में पारित किया गया है—	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारक, प्रतिबंध एवं प्रतितोष) अधिनियम	UPSI (Mains), 2014
■ ‘क्षेत्रीय परिषद’ के सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं—	केन्द्रीय गृह मंत्री	UPSI 15.11.2021 Shift-III
■ भारत के संविधान के वे घटक जो मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है—	1. मौलिक अधिकार 2. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत	UPSI Batch-2, 20 Dec 2017
■ चतुर्थ संभ से आशय है—	प्रेस	UPSI, 1999
■ वह विषय जिसमें संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है—	विद्युत	UPSI 20.11.2021 Shift-III
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय, इसका हिस्सा है—	भारत की समेकित निधि	UPSI Batch-2, 19 Dec 2017
■ अनुलाभ (परिलिङ्ग) की परिभाषा एक..... परिभाषा है—	समावेशी	UPSI 16.11.2021 Shift-II

■ एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है— कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	UPSI Batch-1, 16 Dec 2017
■ वे कार्यकलाप जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं— भर्ती, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्ति उपरान्त वितरण	UPSI Batch-3, 21 Dec 2017
■ भारत में पहली बार भारतीय भाषा को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा दिया गया था— तमिल	UPSI 22.11.2021 Shift-I
■ वे अनुच्छेद जो भारत के मूल संविधान का अंश नहीं थे— अनुच्छेद-51(A), अनुच्छेद-300(A)	UPPSC Mines Inspector 2022
■ भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवम्बर, 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है— मणिपुर	UPPSC Ayurvedacharya 2022
■ वह राज्य जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है— राजस्थान	UPPSC ACF/RFO 2021 Mains GS Paper II
■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है - यातना के विरुद्ध निषेध	UPPCS (Pre) 2023
■ भारतीय संघ को "सौदेबाजी का संघ कहा— मौरिस जोन्स	Govt. Inter College (Pravakta) 2015
■ भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है— स्वतंत्र प्रेस	Govt. Inter College (Pravakta) 2015
■ इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ— वर्ष 1985	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं— आनन्दी बेन पटेल	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है— नई दिल्ली	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ कोठारी कमीशन सम्बन्धित है— शिक्षा	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है— विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ "बिना बोझ के सीखना" समिति के अध्यक्ष थे— प्रो. यशपाल	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ वह राज्य जिसमें ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है, जिससे नौकरशाही की बेहिसाब (अनएकाउंटेड) परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकेगा— राजस्थान	UPPCS GDC 2012
■ राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं जिला पंचायत हैं— संवैधानिक प्राधिकरण	UPPCS (Pre.) G.S. 2012
■ एक मूलभूत अधिकार नहीं है— सम्पत्ति का अधिकार	UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ राज्य सभा रोक सकती है— वित्तीय बिल	UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ जिस राजनीतिक दल को चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है, वह दल होता है— राष्ट्रीय स्तर का	UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ अपराध जिसमें बिना वारन्ट गिरफ्तारी की जा सकती है,— संज्ञेय अपराध	UP Lower (Pre) G.S. 2002
■ दल का आन्तरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय-समय पर उपयोग होता है— आन्तरिक दलीय लोकतंत्र में	U.P. Lower (Pre.) Spl. G.S. 2004
■ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है— अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को	UPPCS (Pre) G.S. 2013 U.P. Lower (Pre.) G.S. 2013
■ संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ है— वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है	UPUDDA/LDA (Pre.) G.S. 2001
■ भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है— बहुफसली योजना	UPPCS (Pre.) G.S. 2015
■ "असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम" पारित हुआ था— 2008 में	UPPCS (Pre.) G.S. 2015 UPPCS (Pre.) G.S. 2012
■ बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम स्थापित किया गया— वर्ष 1976 में	UPPCS (Pre.) G.S. 2002
■ मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक-वैधानिक अधिकार	UP RO/ARO (Pre) G.S. 2013
■ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है— 25 जनवरी को	UPPCS (Pre) G.S. 2015
■ 'खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम' प्रथम बार लागू हुआ था— 1954 में	UPPCS (Main) G.S. II nd Paper 2006
■ 1971 का संशोधन (महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति) अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सी.ए.जी. को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया— 1976 में	UPPCS (Main) Spl. G.S. II nd Paper 2004
■ 'नालन्दा परियोजना' कार्यक्रम है— अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय	UPPCS (Pre.) G.S. 2014

■ 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबन्धन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है—	बिहार	UPPCS (Pre.) 2013
■ उच्च/उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, जिन्होंने अपनी परिसम्पत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है—	न्यायमूर्ति के. कन्नन	UPPCS (Pre.) G.S. 2009
■ वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केन्द्रीय विधान सभा का अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया—	विठ्ठल भाई पटेल	UPPCS (Pre.) G.S. 2007
■ एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है—	लंदन में	UPPCS (Pre) G.S. 2003
■ किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थीं—	श्रीमांवो भण्डारनायके	UPPCS (Pre) G.S. 2001
■ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है—	हेग	UPPCS (Pre) G.S. 1994
■ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है—	9 वर्ष	UPPCS (Pre.) G.S. 1998
■ संविधान के अन्तर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं— नहीं		UPPCS (Main) G.S. II nd 2012
■ आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है—	श्रेत पत्र	UPPCS (Main) G.S. II nd 2008
■ व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गयी है— (मरणोपरान्त) सम्पदा शुल्क		UPPCS (Main) G.S. 2002
■ 2003 में गोरखाओं को ओ.बी.सी. का दर्जा दिया गया—	उत्तराखण्ड में	UPPCS (Main) G.S. II nd 2010
■ असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व ये सभी कारण हैं—	भारत के क्षेत्रवाद के	UPPCSD (Main) Spl. G.S. II nd Paper 2008
■ लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु है—	18 वर्ष	UPPCS (Main) G.S I st 2004
■ भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया है— जोखिम भरे उद्योगों में बालश्रम का उपयोग		UP Lower (Pre) Spl. G.S. 2002
■ धन विधेयक के उपबन्ध में सम्मिलित नहीं किया गया है—	जुर्माने या अर्थदण्ड से सम्बन्धित उपबंध	UPUDA/LDA (Pre) G.S. 2010
■ ‘2014 : द इलेक्शन डैट चेंज इंडिया’ पुस्तक के लेखक हैं—	राजदीप सरदेसाई	U.P.P.C.S. (J) G.K. 2016
■ ‘पिछड़े वर्ग का नागरिक’ से सम्बन्धित पदों में से संविधान में परिभाषित नहीं है— आर्थिक दृष्टि से पिछड़े		U.P.P.C.S. (J) G.K. 2016
■ भारतीय संविधान है—	न ही कठोर न ही लचीला	UPPCS (Main) G.S. II nd 2006
■ भारत में सम्प्रभु है—	हम भारत के लोग	U.P.P.C.S. 2000
■ PIL से सम्बन्धित व्यक्ति हैं—	न्यायाधीश भगवती	U.P. Civil Judge (Pre) 2013
■ उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय जिसमें सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहित वाद की अवधारणा की व्याख्या की गयी—	एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ	U.P. Civil Judge (Pre) 2013
■ संविधान का ‘पूर्ण विश्वास एवं मान्यता’ खण्ड लागू नहीं होता है—	निगमों के कृत्यों में	U.P. Civil Judge 2006
■ “जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता” यह कथन सम्बन्धित है—	आभासी विघटन के सिद्धान्त से	U.P.P.C.S. (J) 2003
■ प्रेस को विधानमण्डल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि— विधानमण्डल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है		U.P.P.C.S. (Special) 2006
■ भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है— अनु. 360		UP Lower (M) G.S. 2015-16
■ 1972 में प्रारम्भ की गयी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारम्भ की गयी थी—	महाराष्ट्र में	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया—	1956	Assistant Professor (Pravakta) 2014
■ एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है—	3840 वोट	UPPSC AE- 2007 Paper (II)
■ भारतीय संविधान का वह संशोधनों जो मंत्रिमण्डल के आकार पर अंकुश लगाता है— संशोधन 91वाँ		UPPSC AE-2004
■ वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा, भारतीय संविधान में नौवां अध्याय जोड़ा गया— 73वाँ		UPPSC AE-2013

■ भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद (Bargaining Federalism) के रूप में वर्णित किया—	मॉरिस जोन्स	SSC CHSL (Tier-I) – 07/08/2023 (Shift-IV)
■ बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर वर्ष करने का प्रयास करता है—	21	SSC MTS— 04/05/2023 (Shift-II)
■ ऐसे अपराध, जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे कहते हैं—	संज्ञेय अपराध	SSC MTS— 02/05/2023 (Shift-I)
■ कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021, के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है—	1961	SSC Selection Posts XI— 27/06/2023 (Shift-III)
■ जनवरी 2022 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 से आगे वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी—	तीन	SSC Selection Posts XI— 27/06/2023 (Shift-I)
■ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है—	तीन	SSC GD – 13/02/2023 (Shift-I)
■ 2022 में लोकसभा में पारित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, वडोदरा (एक मानित विश्वविद्यालय) को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की माँग करता है—	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	SSC MTS— 10/05/2023 (Shift-I)
■ 5 अप्रैल, 2022 से संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष हैं—	डॉ. मनोज सोनी	SSC MTS— 10/05/2023 (Shift-I)
■ सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों पर पाबंदी) संशोधन विधेयक 2022 ने में संशोधन किया है—	सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों पर पाबंदी) अधिनियम, 2005	SSC CHSL (Tier-I) – 04/08/2023 (Shift-III)
■ भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, 20 जुलाई 2022 तक, असंगठित क्षेत्र के लगभग श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं—	1961	SSC CHSL (Tier-I) – 10/03/2023 (Shift-II)
■ भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक (डायरेक्ट टैक्स कोड बिल) पेश किया गया था—	2010 में	SSC CHSL (Tier-I) – 10/03/2023 (Shift-II)
■ NCRB का फुलफार्म है—	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो	SSC CHSL (Tier-I) – 09/03/2023 (Shift-IV)
■ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनकी पारिवारिक आय से कम है—	₹8 लाख	SSC MTS 07/10/2021 (Shift-I)
■ राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है—	महाराष्ट्र	SSC Stenographer – 11/11/2021 : Shift-I
■ राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी—	1962	SSC MTS 12/10/2021 (Shift-I)
■ में उल्लिखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा—	दंड प्रक्रिया संहिता	SSC MTS 14/10/2021 (Shift-I)
■ 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे—	बूटा सिंह	SSC CHSL 05/08/2021 (Shift-II)
■नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में सेवा करने में मदद करता है, जिस पर देश के सभी व्यक्ति उस देश के शासित होने के तरीके के आधार पर सहमत हो सकते हैं—	संविधान	SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-II)

■ किसी देश के राज्यतंत्र को उसके/उसकी _____ के अनुसार डिज़ाइन किया जाता हैं और राज्य में कोई भी बदलाव तभी संभव है, जब कोई संशोधन किया जाए— संविधान	SSC CHSL 19/04/2021 (Shift-I)
■ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 _____ को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ— जम्मू और कश्मीर	SSC GD 07/12/2021 (Shift-I)
■ सूचना का अधिकार अधिनियम, कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि— यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है	SSC GD 18/11/2021 (Shift-I)
■ मूल भारतीय संविधान को हस्तालिखित..... ने किया था— प्रेम बिहारी नारायण रायजादा	SSC GD 14/12/2021 (Shift-III)
■ हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था— वर्ष 1856 में	SSC GD 22/11/2021 (Shift-III)
■ विकास किशनराव गवली बनाम के मामले में, जनवरी 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि OBC आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता— महाराष्ट्र राज्य	SSC CHSL 30/05/2022 (Shift-II)
■ वर्ष _____ में, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए 'गेहूं क्रांति' शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे— 1968	SSC CGL (Tier-I) 18/04/2022 (Shift-III)
■ भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा हुआ था— वर्ष 1929 में	SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-II)
■ चीन का राष्ट्रीय पक्षी है— 'रेड क्राउन्ड क्रेन' (लाल मुकुट वाली क्रेन)	SSC JE Civil 30.10.2020 (Shift-I)
■ लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को नियुक्त करते हैं— संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) के राज्यपाल/ उपराज्यपाल	SSC JE Mechanical 27.10.2020 (Shift-II)
■ NRC का शुद्ध पूर्ण रूप है— नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स	SSC JE Mechanical 11.12.2020 (Shift-I)
■ अभिव्यक्ति 'कानून का नियम' से तात्पर्य है— कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है	SSC JE Mechanical 27.10.2020 (Shift-I)
■ संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम देश में हुआ— ब्रिटेन	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-II)
■ "आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है", यह कथन है— जी.डी.एच. कोल का	SSC JE Civil - 27/01/2018 (Shift-I)
■ "मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धान्तों" को अस्वीकार किया है— हर्बर्ट साइमन ने	SSC JE Civil - 25/01/2018 (Shift-I)
■ केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है— 12	SSC JE Civil - 29/01/2018 (Shift-I)
■ वर्तमान समय में भारत में क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं— 6	SSC JE Civil - 24/01/2018 (Shift-II)
■ विचारक "राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना" से सम्बंधित है— रुसो	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-I)
■ ने कहा था, 'एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है— अरस्तू	SSC JE Civil - 22/01/2018 (Shift-I)
■ संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य व्यवस्थाएं होती हैं— दो	SSC CPO-SI – 09/12/2019 (Shift-I)
■ राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक ——— महीनों में एक बार बैठक करता है— 3	SSC CGL (Tier-I) – 06/06/2019 (Shift-III)
■ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था— 2006	SSC CGL (Tier-I) – 13/06/2019 (Shift-III)
■ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी— 1956	SSC CGL (Tier-I) – 12/06/2019 (Shift-II)
■ ब्रेटन वुड्स समझौते ने का निर्माण किया— अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	SSC GD 01/03/2019 (Shift-II)
■ भारत में, लोगों की वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं— अधिक आबादी	SSC GD 12/02/2019 (Shift-III)
■ लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह— लोगों की गरिमा बढ़ाता है	SSC GD 11/03/2019 (Shift-II)

■ भारत ने देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे-	चीन	SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-II)
■ भारतीय सेना के वे पहले जनरल हैं, जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रति वर्ष 'सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस' के रूप में मनाया जाता है—जनरल के. एम. करिप्पा		SSC CGL (Tier-I)-2019 – 06/03/2020 (Shift-I)
■ सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है— हिंदू विवाह अधिनियम, 1955		SSC CGL (Tier-I) 21/04/2022 (Shift-I)
■ श्रीलंका की संसद में सदस्य होते हैं—	225	SSC CGL (Tier-I) – 10/06/2019 (Shift-II)
■ सही सुमेलन है— सूची-I A. नये राज्यों का गठन B. नागरिकता C. मौलिक अधिकार D. प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना	सूची-II 1. भारतीय संविधान का अनु. 3 2. भारतीय संविधान का भाग-2 3. भारतीय संविधान का भाग-3 4. भारतीय संविधान का अनु. 323 A	UP Lower (M) G.S. 2015-16
■ सही सुमेलन है— सूची-I (A) भारत का संघ (B) ग्राम पंचायत (C) नगर-निगम (D) राज्य	सूची-II (i) राष्ट्रपति (ii) सरपंच (iii) महापौर (मेरार) (iv) राज्यपाल	गत्रा पर्यवेक्षक - 03-07-2016 (Paper-I)
■ सही सुमेलन है— सूची-I (व्यक्ति) एम.एस. स्वामीनाथन एल. के. झा वर्गीज कुरियन मोरारजी देसाई	सूची-II (सम्बद्धता/सम्बन्ध) हरित क्रान्ति आर्थिक प्रशासन सुधार दुग्ध उत्पादन बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण	UPPCS (Pre) Exam 2022
■ सही सुमेलन है— सूची-I A. मौलिक कर्तव्य B. संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है C. मूल ढाँचे का सिद्धान्त D. इन्सानों के अनैतिक व्यापार का निषेध	सूची-II 1. संविधान का 42वाँ संशोधन 2. केशवानन्द भारती केस 3. मिनर्वा मिल केस 4. संविधान का अनुच्छेद 23	UPPCS (Main) G.S. II nd 2007
■ सही सुमेलन है— सूची-I A. वित्त आयोग B. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक C. संघ लोक सेवा आयोग D. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग	सूची-II 1. अनुच्छेद 280 2. अनुच्छेद 148 3. अनुच्छेद 315 4. अनुच्छेद 338	U.P.P.C.S. (J) G.K. 2016
■ सही सुमेलन है— सूची-I A. भारत के राष्ट्रपति B. भारत के राज्यपाल C. राज्य के मुख्यमंत्री D. भारत के उपराष्ट्रपति	सूची-II 1. निर्वाचिक मंडल द्वारा निर्वाचित 2. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3. राज्यपाल द्वारा नियुक्त 4. सांसदों द्वारा निर्वाचित	U.P.P.C.S. (J) G.K. 2016

Download All Subject Free PDF



General Knowledge



Child Development
and Pedagogy



Current Affairs



History



Maths



Geography



Reasoning



Economics



Science



Polity



Computer



Environment



General Hindi



MP GK



General English



UP GK

Join Our Best Course

GK Trick By
Nitin Gupta



Current Affairs



Daily Current Affairs PDF, Best Test Series, Best GK PDF के लिए हमें Follow करें



GK Trick By Nitin Gupta
The Ultimate Key to Success.

Welcome To

GK TRICK BY NITIN GUPTA APP

यहाँ पर आपको मिलेगा

- ✓ Best PDF Notes For All Exams
- ✓ Best Test Series For All Exams
- ✓ Daily Current Affairs PDF
- ✓ सभी Course बहुत ही कम Price पर
- ✓ सभी Test Detail Description के साथ व Analysis करने को सुविधा

